अध्याय-IV

वाणिज्य बैंकों का परिचालन और कार्यनिष्पादन

वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव की पृष्ठभूमि में वर्ष 2008-09 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए परीक्षण का वर्ष रहा है। किंतु, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र इस परीक्षण में खरा उतरा और इस क्षेत्र की आघात सहने की क्षमता पूर्णत: स्पष्ट हुई। भारतीय बैंक उक्त संकट के प्रति व्यापक रूप से सुरक्षित थे क्योंकि जोखिमपूर्ण आस्तियों के प्रति उनका एक्सपोजर बहुत कम था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण में तेजी की अवधि के साथ ही मंदी की अवधि के दौरान प्रति-चक्रीय विवेक सम्मत विनियम अपनाने संबंधी किए गए उपाय सफल सिद्ध हुए। एससीबी का जोखिम भारित आस्ति-पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2008 के अंत के 13.0 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत हो गया। साथ ही, मार्च 2009 के अंत में सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए)-सकल अग्रिम अनुपात मार्च 2009 के अंत में पिछले वर्ष के 2.3 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ भी 1.0 प्रतिशत पर पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा। उल्लेखनीय बात यह है कि इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 2007-08 के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 13.3 प्रतिशत हो गया जो क्षमता में वृद्धि का संकेत करता है जिसके आधार पर बैंक पूंजी को उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार, तुलनपत्र का विस्तार कम होने के बावजूद आस्ति गुणवत्ता बनाई रखी गई। आगे, बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौती इस क्षेत्र की क्षमता और मजबूती सुनिश्चित करते हुए ऋण वृद्धि को सहायता देने की होगी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि पथ की ओर बढ़ रही है।

1. परिचय

4.1 भारत स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)[1] के तुलनपत्र वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में भी मजबूत बने रहे। यह उल्लेखनीय है कि कुछ विकसित देशों की प्रवृत्ति के विपरीत भारत में लिवरेज अनुपात (टियर I पूंजी-कुल आस्ति अनुपात) अधिक बना रहा जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती दर्शाता है। किंतु, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी से पूर्णत: अप्रभावित नहीं था।

4.2 एससीबी के समेकित तुलनपत्रों में पिछले वर्ष के 25.0 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान 21.2 प्रतिशत विस्तार हुआ। जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों ने अपनी वृद्धि की गति बनाए रखी, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों ने गिरावट दर्ज की।

4.3 2008-09 के दौरान, बैंकों द्वारा उद्योग, व्यक्तियों और सेवा क्षेत्र को दिए उधार की वृद्धि दर में गिरावट आई, वहीं कृषि और संबंधित कार्यों को दिए बैंक उधार की वृद्धि दर बढ़ गई। समग्र रूप से, वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात में तेज गिरावट हुई क्योंकि कंपनियों ने व्यापक अनिश्चितता को देखते हुए अपने निवेश आस्थगित कर दिए थे। बैंकों की निवेश वृद्धि कुछ कम हो गई किंतु निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश का अनुपात बढ़ गया जो व्यापक सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम दर्शाता है। परिणामस्वरूप, वृद्धिशील निवेश जमा (आइ-डी) अनुपात बढ़ गया।

4.4 प्रवृत्ति के विपरीत, एससीबी का तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर,जिसमें हाल के वर्षों में घातकी (एक्सपोनेंशल) वृद्धि हुई थी, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.4 प्रतिशत कम हो गया।

[1] मार्च 2009 के अंत में, एससीबी में 27 सरकारी क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और उसके छह सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आइडीबीआइ बैंक लि.),निजी क्षेत्र के 7 नए बैंक, निजी क्षेत्र के पुराने 15 बैंक और 31 विदेशी बैंक शामिल हैं। तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक लि. के संबंध में 30 सितंबर 2009 का अलेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध है और इसी को उपयोग में लाया गया है।

इसका आंशिक कारण रिज़र्व बैंक द्वारा ओबीएस एक्सपोजर के मामले में लागू किया गया उपयुक्त विवेकसम्मत विनियमन था। एससीबी के व्यय और साथ ही आय की वृद्धि दर कम हो गई जिससे निवल लाभ की वृद्धि दर भी कम हो गई। एससीबी का पूंजी-जोखिम भारांकित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) सुधरकर मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत हो गया जो कि एक वर्ष पूर्व 13.0 प्रतिशत था और इस प्रकार यह 9.0 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित स्तर से काफी ऊपर बना रहा।

4.5 एससीबी ने 2008-09 के दौरान प्राथमिक बाजार से संसाधन नहीं जुटाए जो कि मुख्यत: शेयर बाजार का नरम कार्यनिष्पादन दर्शाता है। किंतु, बैंकों ने निजी स्थानन बाजार में ऋण निर्गम के माध्यम से संसाधन जुटाने को वरीयता दी।

4.6 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) के तुलनपत्रों की वृद्धि दर और उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन में भी गिरावट आई। किंतु, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने प्रतिकूलताओं का सामना किया और उनके तुलनपत्रों में वृद्धि हुई।

4.7 इस अध्याय में एससीबी के परिचालनों और वित्तीय कार्यनिष्पादन का समग्र और साथ ही बैंक समूहवार ब्योरा दिया गया है। यह अध्याय बारह भागों में बांटा गया है। भाग 2 में एससीबी के तुलनपत्रों के परिचालन समग्र आधार पर दिए गए हैं जबकि भाग 3 में उनके तुलनपत्रेतर परिचालनों का ब्योरा दिया गया है। एससीबी का वित्तीय कार्यनिष्पादन भाग 4 में दिया गया है। भाग 5 सुदृढ़ता संकेतकों की प्रवृत्ति दर्शाता है। एससीबी के पूंजी बाजार के परिचालनों का ब्योरा भाग 6 में दिया गया है जबकि वर्ष के दौरान बैंकिंग में हुई प्रौद्योगिकीय गतिविधियों को भाग 7 में कवर किया गया है। बैंकिंग का क्षेत्रीय विस्तार भाग 8 में दिया गया है। भाग 9 ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन की अद्यतन जानकारी देता है। व्यष्टि वित्त संबंधी पहलों में हुई प्रगति की जानकारी भाग 10 में दी गई है। एससीबी के अलावा, 91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)[2] और चार स्थानीय क्षेत्र के बैंक भी देश में कार्यरत थे। इस अध्याय का मूल भाग एससीबी का कार्यनिष्पादन है, वहीं आरआरबी और एलएबी का कार्यनिष्पादन क्रमश: भाग 11 और 12 में अलग से दिया गया है। पूर्ववर्ती भागों में की गई चर्चा के आधार पर भाग 13 में व्यापक निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताएं और आस्तियां

4.8 मार्च 2009 के अंत में, भारत में 80 अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) थे [3]। एससीबी के समेकित तुलनपत्रों की वृद्धि दर 2007-08 के 25.0 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 में 21.2 प्रतिशत रह गई। किंतु, एससीबी की आस्तियों में साधारण सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में लगातार तेज वृद्धि हुई जिससे एससीबी का आस्ति-जीडीपी अनुपात (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) उच्च हो गया। यह अनुपात मार्च 2008 के अंत के 91.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 98.5 प्रतिशत हो गया।

4.9 यह महत्वपूर्ण है कि कुछ विकसित देशों की प्रवृत्ति के विपरीत भारत में लिवरेज अनुपात[4] उच्च बना रहा जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती दर्शाता है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक द्वारा देखे अनुसार (2009)[5], यूके स्थित बैंकों का लिवरेज

[2] मार्च 2008 के अंत में।

[3] बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया सहित जिसने भारत में परिचालन बंद कर दिए और जिसका परिसमापन हो रहा है।

[4] लिवरेज अनुपात सामान्यत: कुल समायोजित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 होता है जिसमें आस्तियों के समायोजन में वे मदें शामिल होती हैं जो टियर 1 की पूंजी से पहले ही घटाई गई हो, जैसे कि सदिच्छा। यूएस जैसे अधिकांश देशों में लिवरेज अनुपात की वास्तविक गणना टियर 1 पूंजी से कुल आस्तियों पर आधारित होती है और यही बात यहां प्रयोग की जाती है।

[5] विश्व बैंक (2009), ''बैंकिंग एंड लिवरेज रेशियो'', www.crisistalk.worldbank.org पर उपलब्ध बैकग्राऊंड नोट।

अनुपात 1990 के पूरे दशक में कम होता रहा जो 2000 के बाद सर्वाधिक होकर 1990 के दशक के लगभग 5 प्रतिशत से 2008 तक लगभग 3 प्रतिशत के स्तर पर आया। दूसरी ओर, भारतीय बैंकों का लिवरेज अनुपात मार्च 2001 के लगभग 4.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 तक 6.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

4.10 एससीबी की देयताओं की संरचना 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान मोटे तौर पर वैसी ही बनी रही। सावधि जमाराशियों की वृद्धि दर बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 27.3 प्रतिशत हो गई जो पिछले वर्ष 24.8 प्रतिशत थी। मांग जमाराशियों की वृद्धि दर इसी अवधि में 24.9 प्रतिशत से कम होकर 6.9 प्रतिशत रह गईं जो आर्थिक गतिविधियों में मंदी दर्शाती है। तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में मंदी ऋण और अग्रिम घटक में तदनुरूपी गिरावट के रूप में प्रतिबिंबित हुई। मार्च 2009 के अंत में, रिज़र्व बैंक के पास एससीबी की नकदी और शेष राशि कम हो गई जिसका मुख्य कारण सीआरआर में कमी करना था। किंतु, बैंकों और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा में एससीबी की शेष राशि में वृद्धि हुई और इस प्रकार मार्च 2008 के अंत की स्थिति उलट गई [सारणी IV.1 और सारणी IV.2]।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2008		2009	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूंजी	39,963	0.9	44,037	0.8
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	2,75,524	6.4	3,24,218	6.2
3. जमाराशियां	33,20,061	76.7	40,63,203	77.5
3.1. मांग जमाराशियां	4,42,056	10.2	4,72,578	9.0
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	7,44,051	17.2	8,74,539	16.7
3.3. मीयादी जमाराशियां	21,33,953	49.3	27,16,084	51.8
4. उधार राशिया	3,02,629	7.0	3,23,184	6.2
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	3,87,987	9.0	4,86,685	9.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**43,26,166**	**100**	**52,41,330**	**100**
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	3,22,971	7.5	2,97,263	5.7
2. बैंकों के पास शेष राशियां और मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	1,09,109	2.5	1,98,581	3.8
3. निवेश	11,77,329	27.2	14,49,474	27.7
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क+ख)	9,25,723	21.4	11,64,444	22.2
क. भारत में	9,20,165	21.3	11,58,714	22.1
ख. विदेश में	5,558	0.1	5,730	0.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों म	10,587	0.2	8,153	0.2
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	2,41,017	5.6	2,76,876	5.3
4. ऋण और अग्रिम	24,76,936	57.3	30,00,906	57.3
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	1,50,988	3.5	1,73,910	3.3
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट *आदि*	8,88,882	20.5	11,13,556	21.2
4.3 मीयादी ऋण	14,37,065	33.2	17,13,439	32.7
5. अचल आस्तियां	42,394	1.0	48,361	0.9
6. अन्य आस्तियां	1,97,425	4.6	2,46,743	4.7

टिप्पणी : 2007-08 के आंकड़े 2008-09 के बैंकों के तुलनपत्र के अनुसार हैं और चूंकि कुछ बैंकों द्वारा 2007-08 के आंकड़े संशोधित किए गए हैं अत: हो सकता है कि वे भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2007-08 में प्रस्तुत आंकड़ों से मेल न खाए।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

सारणी IV.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों में वृद्धि : बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में									
	2008					2009				
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी	5.2	1.8	14.6	71.4	**35.2**	3.6	8.2	-3.1	16.3	**10.2**
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	31.3	47.1	97.9	34.7	**45.3**	20.4	14.6	9.1	25.8	**17.7**
3. जमाराशियां	23.1	19.8	23.1	26.8	**23.1**	26.9	20.3	5.4	12.0	**22.4**
3.1. मांग जमाराशियां	20.4	23.4	38.6	28.3	**24.6**	9.9	1.8	1.1	2.3	**6.9**
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	14.9	16.2	40.5	20.2	**17.8**	18.4	15.6	14.7	9.7	**17.4**
3.3. मीयादी जमाराशियां	27.0	20.2	16.0	27.7	**24.8**	33.1	24.2	3.9	18.0	**27.3**
4. उधार	28.4	8.0	26.3	14.1	**24.5**	1.2	22.6	7.1	20.3	**6.8**
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	25.6	21.6	17.3	65.5	**29.0**	21.3	8.1	12.8	57.8	**25.4**
कुल देयताएं / आस्तियां	**23.8**	**21.2**	**27.5**	**32.7**	**25.0**	**24.6**	**19.3**	**6.7**	**22.8**	**21.2**
1. भारिबैंक के पास नकदी और शेष राशि	61.5	74.4	74.2	81.2	**65.4**	-2.4	-14.6	-20.7	-28.9	**-8.0**
2. बैंकों के पास शेष राशियां तथा मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	-32.6	-24.2	-33.7	-25.1	**-31.1**	106.5	47.1	27.8	66.8	**82.0**
3. निवेश	20.3	23.9	31.3	38.4	**23.8**	26.6	33.7	4.3	31.8	**23.1**
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क + ख)	20.5	20.0	21.8	47.4	**22.7**	30.6	27.3	7.7	20.7	**25.8**
क. भारत में	20.3	20.0	21.9	47.4	**22.6**	30.8	27.3	7.7	20.7	**25.9**
ख. विदेश में	58.3	0	-53.6	0	**49.3**	4.0	0	-32.0	0	**3.1**
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों मे	-16.7	-20.7	12.0	-60.9	**-17.0**	-22.8	-24.3	-12.0	-80.7	**-23.0**
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	23.3	42.1	57.0	5.7	**31.2**	11.9	58.2	-2.8	89.4	**14.9**
4. ऋण और अग्रिम	24.8	20.2	26.4	27.5	**25.0**	25.7	15.1	9.9	2.7	**21.2**
4.1 खरीद गए तथा भुनाए गए बिल	16.3	36.9	36.8	36.6	**21.5**	18.3	7.0	16.1	-3.8	**15.2**
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट *आदि*	24.3	18.5	31.0	33.8	**25.2**	29.4	15.1	9.4	9.2	**25.3**
4.3 मीयादी ऋण	26.1	19.9	24.6	21.2	**25.3**	24.0	16.1	9.6	-1.6	**19.2**
5. अचल आस्तियां	42.6	26.1	15.9	32.3	**35.2**	17.2	8.0	1.2	19.4	**14.1**
6. अन्य आस्तियां	31.0	-1.7	28.3	67.0	**38.2**	2.0	28.2	19.8	68.1	**25.0**

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

4.11 जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्र अपनी वृद्धि की गति बनाए हुए थे, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की वृद्धि दर में गिरावट आई। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों, जिनकी वृद्धि दर निजी क्षेत्र के नए बैंकों की तुलना में बहुत कम थी, का कार्यनिष्पादन उनके नए प्रतिपक्षियों की तुलना में इस वर्ष बेहतर रहा [परिशिष्ट सारणी IV.1(क) से (ग)]।

4.12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल आस्तियों, जमाराशियों और अग्रिमों तथा निवेश में मार्च 2009 के अंत का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में गिरावट आई। इसका मुख्य कारण अन्य बैंक समूहों की वृद्धि दर में गिरावट की पृष्ठभूमि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में तुलनपत्र की सुदृढ़ वृद्धि था। (सारणी IV.3)।

जमाराशियां

4.13 एससीबी की कुल जमाराशि की वृद्धि दर मार्च 2008 के अंत के 23.1 प्रतिशत और पिछले वर्ष के 24.6 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 22.4 प्रतिशत रह गई। संसाधन जुटाने के साधन के रूप में जमा-प्रमाणपत्र (सीडी) का महत्व 2008-09 के दौरान भी बना रहा, हालांकि वृद्धि दर कुछ कम थी। कुल जमाराशि के प्रतिशत के रूप में सीडी का शेष 4.7 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.2)।

4.14 जमाराशि में बैंक समूहवार हिस्से के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंक न सिर्फ प्रमुख बने रहे, बल्कि उनका हिस्सा भी बढ़ा जबकि अन्य बैंक समूहों के संबंध में गिरावट हुई (चार्ट IV.1)।

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख घटक - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	आस्तियाँ		जमाराशियाँ		अग्रिम		निवेश	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरकारी क्षेत्र के बैंक	69.9	71.9	73.9	76.6	72.6	75.3	67.9	69.9
राष्ट्रीयकृत बैंक	43.5	44.2	48.4	49.1	45.3	47.2	42.7	41.7
स्टेट बैंक समूह	23.4	24.4	23.3	24.8	24.0	24.6	22.4	24.7
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	3.0	3.3	2.2	2.8	3.3	3.4	2.8	3.5
निजी क्षेत्र के बैंक	21.7	19.6	20.3	18.1	20.9	19.2	23.7	21.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	4.5	4.4	5.0	4.9	4.5	4.3	4.6	5.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक	17.2	15.2	15.3	13.2	16.4	14.9	19.1	16.2
विदेशी बैंक	8.4	8.5	5.8	5.3	6.5	5.5	8.4	9.0
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

4.15 बैंकों के लिए चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियां कम दर पर संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। किंतु, हाल ही में सीएएसए जमाराशियों की वृद्धि दर कम हो गई और कुल जमाराशि में उनके हिस्से में भी गिरावट आई जिससे बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौती खड़ी हो गई (बॉक्स IV.1)।

गैर जमाराशि संसाधन

4.16 गैर जमाराशि संसाधनों के बीच, बैंकों की उधार वृद्धि पिछले वर्ष के 24.5 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 6.8 प्रतिशत रह गई (सारणी IV.2 देखें)। 2007-08 के दौरान जहां बैंकों द्वारा पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से 30,455 करोड़ रुपए जुटाए, वहीं संसाधन जुटाने का यह स्रोत 2008-09 में वास्तविक रूप से सूख गया जिसका मुख्य कारण प्राथमिक के साथ ही गौण पूंजी बाजारों की नरम स्थिति था। किंतु, बैंकों ने निजी स्थानन बाजार से काफी अधिक संसाधन जुटाए (ब्योरे के लिए भाग 6 देखें)।

चार्ट IV.1: कुल जमाराशियों में अंश - बैंक समूहवार

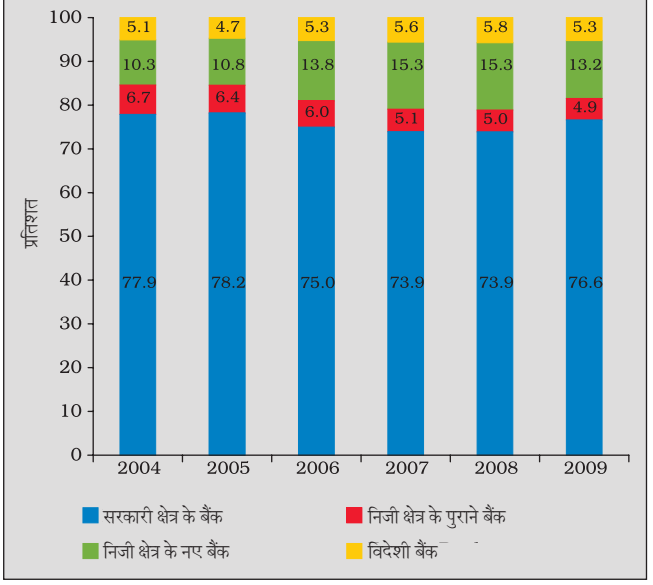

बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं

4.17 भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं (रुपए के संदर्भ में) 2007-08 के दौरान 8.4 प्रतिशत बढ़ी थीं जिनमें मार्च 2009 के अंत में 1.1 प्रतिशत की गिरावट हुई। अंतरराष्ट्रीय देयताओं में हुई इस गिरावट का मुख्य कारण एडीआर/जीडीआर जैसी 'अन्य देयताएं' में कमी आना था जो बैंकों और कंपनियों के लिए विदेशी ऋण का माध्यम सूखना दर्शाता है। दूसरी ओर, प्रवृत्ति में बदलाव करते हुए कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा जमाराशि का हिस्सा, जो 2005-08 की अवधि के दौरान लगातार कम हुआ था, 2008-09 के दौरान तेजी से बढ़ गया। इसका मुख्य कारण रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमाराशि पर ब्याज दर में ऊर्ध्वमुखी समायोजन जैसी पहलों को प्रोत्साहित करना और साथ ही अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता के संदर्भ में

बॉक्स IV.1: एससीबी की चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों (सीएएसए) की प्रवृत्ति

चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों का हिस्सा वाणिज्य बैंकों की लागत संरचना में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चालू खाते मुख्य रूप से कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्यमियों के लिए होते हैं जिन्हें प्रतिदिन असंख्य बैंकिंग लेनदेन करने होते हैं। दूसरी ओर, वैयक्तिक और गैर-वाणिज्यिक लेनदेनों के लिए बचत खाते परिचालन के सर्वाधिक सामान्य खाते हैं। बैंक चालू खातों पर ब्याज का भुगतान नहीं करते और बचत खातों पर 3.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करते हैं। इस प्रकार, जमाराशि के अन्य प्रकारों, जैसे मीयादी जमाराशि, की तुलना में सीएएसए जमाराशि धन जुटाने का सबसे सस्ता साधन है। परिणामस्वरूप, किसी बैंक की कुल जमाराशि में सीएएसए घटक जितना अधिक होगा, उसकी जमाराशि की लागत उतनी ही सस्ती होगी।

भारतीय संदर्भ में, कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का हिस्सा एक तिहाई से भी अधिक है (सारणी 1)।

कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का सर्वाधिक हिस्सा विदेशी बैंकों का था, इसके बाद एसबीआइ और उसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों का स्थान था। यह क्रम मार्च 2008 तक सुदृढ़ बना रहा, हालांकि उसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ था। इसके अलावा, एससीबी के संबंध में समेकित स्तर पर सीएएसए का हिस्सा मार्च 2006 से मार्च 2009 तक लगातार कम हुआ है। सभी बैंक समूहों की कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि घटक का हिस्सा मार्च 2006 से मार्च 2009 तक कम हुआ है, किंतु निजी बैंकों के मामले में ऐसा नहीं हुआ और उनके सीएएसए हिस्से में वृद्धि हुई।

सारणी 1: कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का बैंक समूहवार हिस्सा

(प्रतिशत)

	मार्च के अंत में			
बैंक समूह	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक	43.4	42.9	42.0	38.6
राष्ट्रीयकृत बैंक	38.2	35.4	33.0	29.9
निजी बैंक	30.4	29.8	32.8	32.9
विदेशी बैंक	50.5	45.1	44.7	41.7
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**38.6**	**36.6**	**35.7**	**33.2**

एससीबी की सीएएसए जमाराशि ने गिरावट दर्ज करते हुए मार्च 2009 के अंत में 13.4 प्रतिशत वृद्धि-दर दर्ज की जो पहले के वर्ष में 20.2 प्रतिशत थी। सीएएसए जमाराशि की वृद्धि दर राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ कम हुई और निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में इसमें तेज गिरावट हुई। एसबीआइ और उसके सहयोगी बैंकों के संबंध में 2008-09 के दौरान सीएएसए जमाराशि में वृद्धि पिछले वर्ष के स्तर पर ही रही।

अलग-अलग आधार पर किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च 2009 के अंत में विदेशी बैंकों का चालू जमाराशियों का हिस्सा बचत बैंक जमाराशि की तुलना में अधिक था जबकि अन्य बैंक समूहों के मामले में बचत बैंक जमाराशि का हिस्सा अधिक था (चार्ट)। इसके अलावा, मार्च 2009 के अंत में सभी बैंक समूहों के संबंध में सीएएसए जमाराशि में मांग जमाराशि का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया। वृद्धि के संदर्भ में, चालू जमाराशि और बचत बैंक जमाराशि में मार्च 2008 के 24.6 प्रतिशत और 17.8 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत और 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का कम होता हुआ हिस्सा और उनकी वृद्धि में गिरावट बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौती बन सकती है। इसका कारण ऊपर उल्लेख किए अनुसार यह है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए सीएएसए जमाराशि निधि का सबसे सस्ता स्रोत है। इस स्रोत में कमी आने की स्थिति में, वैकल्पिक स्रोत कठिन ही नहीं बल्कि महंगे भी होंगे। आर्थिक वृद्धि का पुनरुज्जीवन सन्निकट होने के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकता में समरूप वृद्धि के साथ, बैंकिंग उद्योग के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह अधिक सीएएसए जमाराशियां जुटाने के लिए पहल करे।

चार्ट : सीएएसए की बैंक समूहवार संरचना (मार्च 2009 के अंत में)

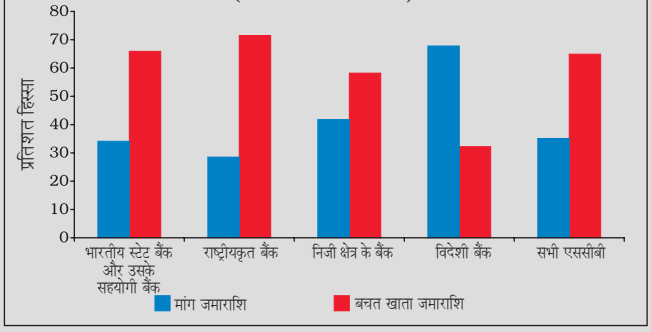

भारतीय अर्थव्यवस्था में जमाकर्ताओं का निरंतर विश्वास था (सारणी IV.4)।

4.18 पिछले कुछ वर्षों में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं में अंतरराष्ट्रीय देयताओं का हिस्सा 2008-09 के दौरान लगातार कम होता रहा जो मुख्यत: एससीबी की देशी निधि पर अधिक निर्भरता दर्शाता है ।

बैंक ऋण

4.19 एससीबी के ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि दर जो कि मार्च 2005 के अंत में 33.2 प्रतिशत की ऊंचाई पर थी, तब से मंद होती जा रही है। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, एससीबी के कुल ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि दर मार्च 2009 के अंत में कम होकर 21.2 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 25.0

सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकार के अनुसार

(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007	2008	2009
1	2	3	4
1. जमाराशियां और ऋण	**2,71,403**	**2,89,362**	**3,23,205**
	(75.2)	**(74.0)**	**(83.6)**
जिनमें से:			
क) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर(बी)]	68,086	60,340	72,783
	(18.9)	(15.4)	(18.8)
ख) विदेशी मुद्रा उधार *	61,470	77,257	75,398
	(17.0)	(19.8)	(19.5)
ग) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाता	1,12,907	1,11,301	1,24,488
	(31.3)	(28.5)	(32.2)
घ) अनिवासी सामान्य (एनआरओ) रुपया जमाराशिया	6,855	11,387	20,686
	(1.9)	(2.9)	(5.4)
2. प्रतिभूतियों / बांडों (आइएमडी/आरआइबी सहित) के अपने निर्गम	**10,036**	**9,166**	**6,864**
	(2.8)	**(2.3)**	**(1.8)**
3. अन्य देयताएं	**79,258**	**92,329**	**56,540**
	(22.0)	**(23.6)**	**(14.6)**
जिनमें से:			
क) एडीआर/जीडीआर	23,515	25,111	10,357
	(6.5)	(6.4)	(2.7)
ख) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	40,328	45,603	18,932
	(11.2)	(11.7)	(4.9)
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अन्तरराष्ट्रीय देयताएँ	15,415	21,615	27,251
	(4.3)	(5.5)	(7.0)
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**3,60,698**	**3,90,857**	**3,86,608**

* : भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार, बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं ।

स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस)।

प्रतिशत थी। चक्रीय कारकों, जिनके कारण उच्च ऋण वृद्धि की अवधि के बाद वृद्धि में नरमी आई थी, इस वर्ष यह गिरावट सर्वाधिक थी जिसका कारण वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था में आई समग्र मंदी थी। मीयादी ऋण में वृद्धि में गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था में निवेश में उनका हिस्सा 2008-09 में बढ़कर 81.0 प्रतिशत हो गया जो कि पिछले वर्ष 77.8 प्रतिशत था (चार्ट IV.2)।

बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

4.20 बैंक ऋण वृद्धि में 2007-08 के दौरान हुई गिरावट 2008-09 के दौरान भी जारी रही जो मुख्यत: वास्तविक अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ ही बढ़ती अनिश्चितता के संदर्भ में बैंकों द्वारा अपनाया गया सतर्क दृष्टिकोण दर्शाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2008-09 के दौरान बैंकों द्वारा उद्योग, व्यक्तिगत ऋण और सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण की वृद्धि दर में गिरावट हुई जबकि कृषि और संबंधित कार्यों संबंधी बैंक ऋण में काफी वृद्धि हुई (सारणी IV.5 और परिशिष्ट सारणी IV.3)।

चार्ट IV.2: मीयादी ऋण और निवेश

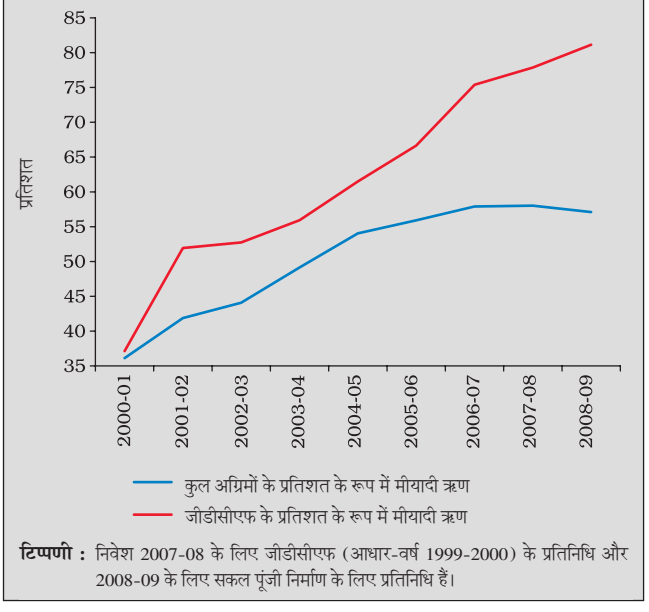

टिप्पणी : निवेश 2007-08 के लिए जीडीसीएफ (आधार-वर्ष 1999-2000) के प्रतिनिधि और 2008-09 के लिए सकल पूंजी निर्माण के लिए प्रतिनिधि हैं।

सारणी IV.5: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन - प्रवाह
(वर्ष में घट-बढ़)

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	2007-08		2008-09	
	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप	**44,966**	**19.5**	**63,313**	**23.0**
2. उद्योग	**1,69,536**	**24.3**	**1,87,515**	**21.6**
3. वैयक्तिक ऋण	**54,730**	**12.1**	**54,991**	**10.8**
जिसमें से : आवास	26,802	11.6	19,165	7.4
4. सेवाएं	**1,32,419**	**31.5**	**93,580**	**16.9**
जिनमें से:				
(i) थोक व्यापार (खाद्यान्न की सरकारी खरीद से भिन्न)	5,559	11.1	11,723	21.0
(ii) स्थावर संपदा ऋण	19,235	43.6	28,261	44.6
(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	30,094	61.5	19,835	25.1
कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	**4,01,650**	**22.3**	**3,99,400**	**18.1**
जिनमें से :				
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,11,414	17.5	1,68,506	22.5

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंधित हैं। इन आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के विलयन के प्रभाव भी शामिल है।

2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं और अंतर बैंक सहभागिता के पास पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।

स्रोत: बैंक क्रेडिट विवरणी का क्षेत्रीय एवं औद्योगिक नियोजन (मासिक)।

4.21 ऋण के क्षेत्रीय विनियोजन पर 17 जुलाई 2009 तक उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि उद्योग, सेवा और वैयक्तिक ऋण संबंधी वर्ष-दर-वर्ष आधार बैंक ऋण 30.7 प्रतिशत, 36.9 प्रतिशत और 17.0 प्रतिशत से कम होकर क्रमश: 20.8 प्रतिशत, 13.8 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत तह गई। कृषि ऋण की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 29.1 प्रतिशत हो गई। स्थावर संपदा और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) को ऋण 46.7 प्रतिशत (जुलाई 2008 में 43.9 प्रतिशत) और 31.4 प्रतिशत (जुलाई 2008 में 53.9 प्रतिशत) पर उच्च बनी रही।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

4.22 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 2007-08 के 17.1 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 18.0 प्रतिशत हो गए जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी[6]) के 42.5 प्रतिशत थे। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 2008-09 में बढ़कर 15.9 प्रतिशत हो गए जो कि पिछले वर्ष 13.5 प्रतिशत थे और एएनबीसी के 46.8 प्रतिशत थे (सारणी IV.6)।यह महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम में बढ़ती हुई यह वृद्धि अर्थव्यवस्था में मंदी और कुल बैंक ऋण में गिरावट के समय हुई है (परिशिष्ट सारणियां IV.4 से IV.7)।

4.23 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में देखी गई प्रवृत्ति के विपरीत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को विदेशी बैंकों द्वारा दिए गए उधार मार्च 2009 के अंत में कम होकर 10.4 प्रतिशत रह गए जो कि पिछले वर्ष 32.8 प्रतिशत थे। एएनबीसी/

सारणी IV.6 : सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार
(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम#	**6,10,450 (44.7)**	**7,20,083 (42.5)**	**1,64,068 (42.5)**	**1,90,207 (46.8)**
जिसमें से:				
कृषि ^	2,49,397 (18.3)	2,98,211 (17.2)	58,566 (17.1)	76,062 (15.9)
अति लघु और लघु उद्यम	1,51,137 (11.1)	1,91,307 (11.3)	46,912 (13.7)	47,916 (12.0)

अ : अनंतिम।

\# : प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में व्यापक श्रेणियों में कृषि, लगु उधम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, लघु ऋण, शिक्षा और आवास शामिल है।

^ : प्रतिशत की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि को एनएनबीसी के 4.5 प्रतिशत तक माना जाता है।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निवल बैंक ऋण/समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलन पत्र में न आनेवाले एक्सपोज़रों की ऋण समतुल्य राशि (सीईओबीएसई) के प्रतिशत दर्शाते हैं।

[6] सभी बैंकों के लिए लक्ष्य और उप-लक्ष्य अब समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण के समतुल्य राशि (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, से जोड़ दिया गया है।

सारणी IV.7 : विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
(मार्च के अंतिम रिर्पोटिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2007		2008		2009अ	
	राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसइ का प्रतिशत	राशि	एएनबीसी सीईओबीएसइ का प्रतिशत	राशि	एएनबीसी सीईओबीएसइ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम #	**37,831**	**33.4**	**50,254**	**39.5**	**55,483**	**34.3**
जिसमें से:						
निर्यात ऋण	20,711	18.3	28,954	22.7	31,511	19.4
व्यष्टि और लघु उद्यम*	11,637	10.3	15,489	12.2	18,138	11.2

अ : अनंतिम

: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापक क्षेणियों में कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, व्यष्टि ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर नए दिशानिर्देश व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और व्यष्टि उद्यमों की संशोधित परिभाषा को ध्यान में लेते हैं।

सीईओबीएसई को प्रतिशत के सदर्भ में भी, उनका संवितरण 34.3 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के 39.5 प्रतिशत से कम था (सारणी IV.7, परिशिष्ट सारणी IV.8)।

विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी)[7]

4.24 2008-09 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एसएसीपी के तहत के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए। निजी क्षेत्र के बैंक 2008-09 के दौरान अपने लक्ष्य से लगातार आगे बने रहे, यद्यपि संवितरण की वृद्धि दर में कमी आई थी (सारणी IV.8)।

सारणी IV.8 : विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य और संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	2007-08		2008-09 पी	
	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,52,133	1,33,226 (87.6)	1,59,470	1,65,198 (103.6)
निजी क्षेत्र के बैंक	41,427	47,862 (115.3)	57,353	63,753 (111.2)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े (प्रतिशत) लक्ष्यों की उपलब्धियाँ दर्शाते हैं ।

4.25 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सूचित किया गया था कि वे अपने एएनबीसी का 5 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित करें। मार्च 2009 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिया गया कुल ऋण उनके निवल बैंक ऋण के 6.3 प्रतिशत था और 25 बैंक अपने लक्ष्य तक पहुंच गए थे। सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों ने 23 विशेषीकृत शाखाएं खोली हैं।

उद्योग को ऋण

4.26 मार्च 2009 के अंत में, उद्योग (लघु, मझौले और बड़े) को ऋण की वृद्धि दर मार्च 2008 के अंत के 24.3 प्रतिशत और मार्च 2007 के अंत के 27.0 प्रतिशत से लगातार दो वर्ष कम होकर 21.6 प्रतिशत रह गई। पिछले वर्ष जैसे ही, उद्योग की ऋण वृद्धि-दर समग्र ऋण वृद्धि-दर की तुलना में अधिक थी। अत:, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में उद्योग की ओर बकाया ऋण का हिस्सा मार्च 2008 के अंत के 39.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 40.5 प्रतिशत हो गया। बुनियादी सुविधाओं, बकाया ऋण में जिनका हिस्सा सर्वाधिक होता है, का समग्र संदर्भ में उद्योग को वृद्धिशील बैंक ऋण में भी सर्वाधिक हिस्सा था, इनके बाद मूल धातु और धातु उत्पाद और वस्त्र का स्थान था। वृद्धि दरों के

[7] रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया था कि वे 1994-95 से वार्षिक आधार पर कृषि ऋण योजना बनाए ताकि कृषि-ऋण के प्रवाह में स्पष्ट और विशेष सुधार हो सके। एसएसीपी के तहत, बैंकों से अपेक्षित है कि वे वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान पूरे करने के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य बनाएं। बैंकों द्वारा सामान्यत: पिछले वर्ष किए गए संवितरण से लगभग 20-25 प्रतिशत अधिक के लक्ष्य बनाए जाते हैं।

संदर्भ में, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन को ऋण में वृद्धि दर में तीव्रतम वृद्धि हुई (63.8 प्रतिशत), इनके बाद निर्माण (37.8 प्रतिशत) और बुनियादी सुविधाएं (31.6 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.3 और परिशिष्ट सारणी IV.9)। यह महत्वपूर्ण है कि मंदी के बावजूद चुनिंदा क्षेत्रों और विशेष रूप से पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद को ऋण में तेज वृद्धि हुई।

व्यष्टि और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण

4.27 मार्च 2009 के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 1,91,307 करोड़ रुपए था जो इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 26.5 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.3 प्रतिशत था। इन अग्रिमों में से विनिर्माण उद्यमों और सेवा उद्यमों को दिए गए अग्रिम क्रमश: 1,31,177 करोड़ रुपए और 54,449 करोड़ रुपए थे जो लघु उद्यम क्षेत्र के कुल अग्रिमों का क्रमश: 68.6 प्रतिशत और 28.5 प्रतिशत थे। मार्च 2009 के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 47,916 करोड़ रुपए था जो इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 25.2 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.8 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विनिर्माण उद्यमों और सेवा उद्यमों को दिए गए अग्रिम क्रमश: 17,625 करोड़ रुपए और 26,363 करोड़ रुपए थे जो एमएसई के कुल अग्रिमों के क्रमश: 36.8 प्रतिशत और 55.0 प्रतिशत थे। एससीबी द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण मार्च 2009 के अंत में 2,57,361 करोड़ रुपए था जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 26.7 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.4 प्रतिशत था।

चार्ट IV.3: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन

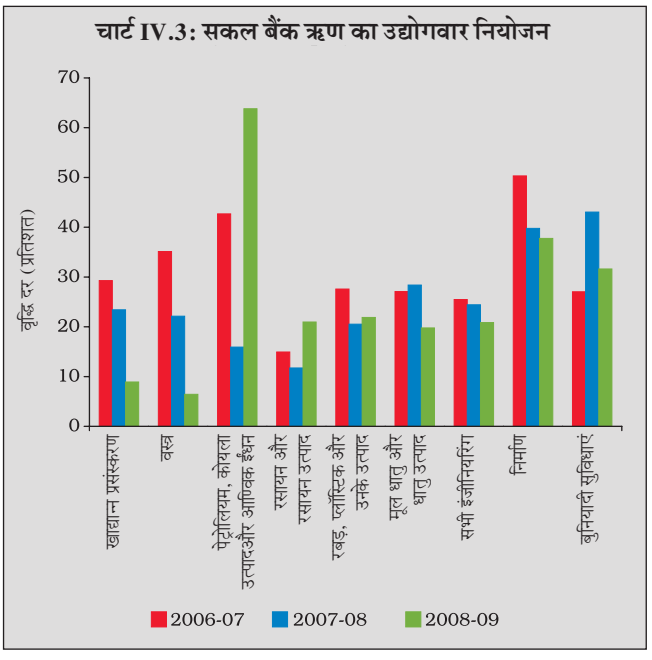

4.28 मार्च 2009 के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 18,138 करोड़ रुपए था जो इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 32.7 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.2 प्रतिशत था।

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग को ऋण

4.29 खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआइसी) को ऋण देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों का संघ बनाया गया। ये ऋण उक्त संघ के पांच प्रमुख बैंकों की औसत मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत कम दर पर दिए जाते हैं। 31 अगस्त 2009 के अंत में, इस योजना के तहत बैंकों के संघ द्वारा संवितरित 738 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

खुदरा ऋण

4.30 2004-05 और 2005-06 में 40.0 प्रतिशत से अधिक रही खुदरा ऋण वृद्धि-दर में तब से गिरावट हो रही है। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, बैंकों के खुदरा ऋण की वृद्धि-दर मार्च 2009 के अंत में और कम होकर 4.0 प्रतिशत रह गई जो एक वर्ष पहले 17.1 प्रतिशत और मार्च 2007 के अंत में 29.9 प्रतिशत थी। यह बैंकिंग क्षेत्र के समग्र ऋण की वृद्धि (21.2 प्रतिशत) से भी कम बनी रही। परिणामस्वरूप, कुल ऋण और अग्रिमों में खुदरा ऋण का हिस्सा मार्च 2008 के अंत के 24.5 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 21.3 प्रतिशत रह गया। बैंकों के खुदरा संविभाग की वृद्धि में गिरावट का मुख्य कारण आवास ऋण, आटो ऋण, क्रेडिट कार्ड रिसिवेबल्स और अन्य निजी ऋण

सारणी IV.9: बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में बकाया		प्रतिशत	
	2008	2009	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1. आवास ऋण	2,52,932	2,63,235	12.7	4.1
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	4,802	5,431	-34.2	13.1
3. क्रेडिट कार्ड की प्राप्त राशियां	27,437	29,941	49.8	9.1
4. ऑटो ऋण	87,998	83,915	6.6	-4.6
5. अन्य निजी ऋण	1,97,607	2,11,294	27.5	6.9
कुल खुदरा ऋण (1 से 5)	**5,70,776**	**5,93,815**	**17.1**	**4.0**
	(24.5)	(21.3)		
एससीबी के कुल ऋण और अग्रिम	**23,32,032**	**27,93,572**	**23.2**	**19.8**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण और अग्रिमों में प्रतिशत अंश को दर्शाते हैं।
स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियां (देशी अ-लेखा परीक्षित और अनंतिम)।

में गिरावट था, हालांकि उपभोक्ता वस्तुओं के ऋणों में सुधार हुआ था (सारणी IV.9)।

संवेदनशील क्षेत्रों को उधार

4.31 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एससीबी से संवेदनशील क्षेत्रों (पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य) को उधार में मार्च 2009 के अंत में थोड़ी वृद्धि हुई। किंतु, पूंजी बाजार के प्रति एससीबी के एक्सपोजर में 2008-09 के दौरान काफी गिरावट आई जो मुख्यत: पूंजी बाजार में मंदी की स्थिति और बाजार में अत्यधिक जोखिम की धारणा दर्शाती है। जहां पण्य को प्राप्त ऋण कम हो गया, वहीं स्थावर संपदा बाजार में मंदी के बावजूद स्थावर संपदा बाजार के ऋण में वृद्धि होती रही (सारणी IV.10)। इससे वाणिज्यिक स्थावर संपदा 100 प्रतिशत तक किए गए दावों के प्रति जोखिम भार का सामान्यीकरण और अग्रिम पुनर्निधारण योजना के तहत वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों के साथ विशेष विनियामक व्यवहार करने को विस्तार भी आंशिक रूप से दिखा। संवेदनशील क्षेत्र के प्रति कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में एससीबी का समग्र एक्सपोजर कम होकर 19.3 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष 21.0 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.11)।

4.32 सभी बैंक समूहों के बीच, संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति विदेशी बैंकों का एक्सपोजर मार्च 2009 के अंत में सर्वाधिक था जिसका मुख्य कारण स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति अधिक उधार था। किंतु, कुल ऋणों और अग्रिमों में संवेदनशील क्षेत्र के उधार का हिस्सा

सारणी IV.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को उधार
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2008		2009	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूंजी बाजार	61,638 (75.6)	11.9	55,282 (-10.3)	9.5
2. स्थावर संपदा बाजार	4,56,858 (22.5)	87.8	5,24,227 (14.8)	90.3
3. पण्य	1,643 (90.6)	0.3	897 (-45.4)	0.2
कुल (1+2+3)	**5,20,140** (27.2)	**100.0**	**5,80,407** (11.6)	**100.0**

- : नगण्य।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर दर्शाते हैं।
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के संबंध में कम हो गया (सारणी IV.11, परिशिष्ट सारणी IV.11)।

निवेश

4.33 बैंकों के निवेश की वृद्धि-दर मार्च 2009 के अंत में कम होकर 23.1 प्रतिशत रह गई। किंतु, एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एसएलआर प्रतिभूतियां वर्ष के दौरान बढ़ गईं जिसका कारण विद्यमान अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में बैंकों द्वारा अपनी निधियों का निवेश कम जोखिम और कम प्रतिलाभ वाले लिखतों में करने को वरीयता देना था (सारणी IV.12)।

सारणी IV.11: संवेदनशील क्षेत्र को उधार - बैंक समूहवार*
(मार्च अंत के अनुसार)

(प्रतिशत)

क्षेत्र / बैंक समूह	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		विदेशी बैंक	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूंजी बाजार#	1.7	1.5	5.6	3.1	2.3	1.8	3.3	3.6
स्थावर संपदा @	15.8	14.8	28.9	27.6	16.7	17.3	23.2	26.8
पण्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.1	0.0
संवेदनशील क्षेत्र को कुल अग्रिम	**17.5**	**16.3**	**34.5**	**30.7**	**19.7**	**19.8**	**26.6**	**30.5**

* : संबंधित बैंक समूह के कुल ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में संवेदनशील क्षेत्र को दिए गए ऋण।
# : पूंजी बाजार के जोखिम में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।
@ : स्थावर संपदा के जोखिम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों उधार शामिल हैं।

4.34 यद्यपि मार्च 2009 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा धारित अतिरिक्त एसएलआर निवेश 1,69,846 करोड़ रुपए था (24.0 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से अधिक), किंतु अनेक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात का संविभाग निर्धारित न्यूनतम स्तर के बहुत करीब था। एससीबी का अतिरिक्त एसएलआर निवेश 25 सितंबर 2009 को बढ़कर 2,88,754 करोड़ रुपए हो गया। परिणामस्वरूप, एनडीटीएल के संबंध में एसएलआर निवेश बढ़कर 30.4 प्रतिशत हो गया। एलएएफ समायोजित एसएलआर धारिता 1,82,639 करोड़ रुपए थी जो एनडीटीएल के 28.0 प्रतिशत थी (चार्ट IV.4)।

सारणी IV.12: एससीबी के निवेश और जमाराशि में वृद्धि

(प्रतिशत)

वर्ष	एसएसआर निवेश	एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एसएलआर निवेश (मार्च अंत)	कुल निवेश	जमा	ऋण और अग्रिम
1	2	3	4	5	6
2005-06	-2.9	31.3	-0.4	17.8	31.8
2006-07	10.3	27.9	9.7	24.6	30.6
2007-08	22.8	27.8	23.8	23.1	25.0
2008-09	20.0	28.1	23.1	22.4	21.2

स्रोत : कॉलम सं. 2 और 3 के लिए एससीबी द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियाँ; कॉलम सं. 4-6 के लिए संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

एसएलआर से भिन्न निवेश

4.35 एसएलआर से भिन्न प्रतिभूतियों (अर्थात बांड/डिबेंचर/शेयर और वाणिज्यिक पत्र) में बैंकों के निवेश की वृद्धि 2008-09 के दौरान कम होकर 10.5 प्रतिशत रह गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान इसमें 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी IV.13)। एससीबी से वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल निधि प्रवाह, ऋण और एसएलआर से भिन्न निवेश 2008-09 में 17.5 प्रतिशत (4,21,091 करोड़ रुपए) बढ़ गया जबकि पिछले वर्ष यह 22.6 प्रतिशत (4,44,807 करोड़ रुपए) बढ़ा था ।

चार्ट IV.4: एसएलआर प्रतिभूतियों में एससीबी का निवेश
(एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में)

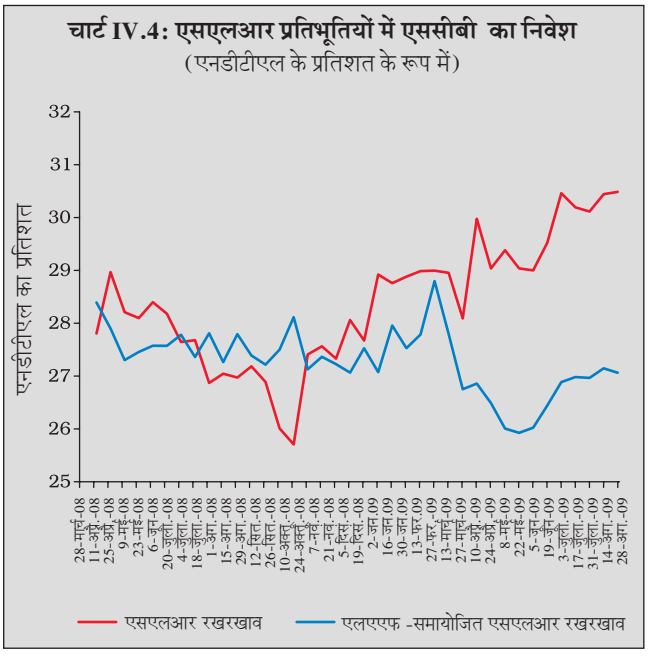

सारणी IV.13: एससीबी के गैर -एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	28 मार्च 2008 तक	कुल का प्रतिशत	27 मार्च 2009 तक	कुल का प्रतिशत	12 सितं. 2008 तक	कुल का प्रतिशत	11 सितं. 2009 तक	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वाणिज्यिक पत्र	13,270	11.5	20,001	13.9	12,538	10.8	12,875	5.1
2. शेयरों में निवेश	26,414	22.9	27,829	19.4	27,716	23.9	27,105	10.7
जिनमें से :								
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	3,025	2.6	2,769	1.9	3,497	3.0	2,345	0.9
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	23,389	20.3	25,060	17.5	24,219	20.9	24,761	9.7
3. बांडों/डिबेंचरों में निवेश	56,635	49.2	58,587	40.8	53,437	46.2	57,545	22.6
जिनमें से:								
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,935	24.3	25,456	17.7	25,548	22.1	22,312	8.8
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	28,700	24.9	33,131	23.1	27,889	24.1	35,233	13.8
4. म्यूच्युअल फंड के यूनिट	18,824	16.3	37,035	25.8	22,042	19.0	1,56,963	61.7
कुल गैर-एसएलआर निवेश (1+2+3+4)	**1,15,143**	**100.0**	**1,43,452**	**100.0**	**1,15,733**	**100.0**	**2,54,488**	**100.0**

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां।

4.36 बैंकों के एसएलआर से भिन्न निवेश की संरचना में हाल के वर्षों में और विशेष रूप से 2004-05 से बदलाव आया है। बैंकों द्वारा शेयरों, वाणिज्यिक पत्रों और पारस्परिक निधियों के यूनिटों में निवेश का हिस्सा बढ़ गया जबकि बांडों/डिबेंचरों में निवेश के हिस्से में गिरावट जारी है जो आंशिक रूप से भारत स्थित वाणिज्य बैंकों का जोखिम के प्रति बदलता रुख दर्शाती है। शेयरों में बैंकों के निवेश को छोड़कर यह प्रवृत्ति 2008-09 में भी जारी रही जिसका मुख्य कारण भारतीय शेयर बाजार की मंद स्थिति था (सारणी IV.14)।

बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां

4.37 भारत स्थित एससीबी की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की वृद्धि-दर मार्च 2009 के अंत में कम होकर 3.0 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 9.7 प्रतिशत थी। इस प्रवृत्ति के विपरीत 'नोस्त्रो शेष', जो कि भारत में ब्याज दर तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण पिछले वर्ष तेजी से कम हो गए थे, देशी ब्याज दर कम हो जाने के कारण इस वर्ष बढ़ गए। जहां ऋण प्रतिभूतियों की धारिता में निरंतर कमी आई, वहीं निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण भी पिछले वर्ष की तेज वृद्धि के विपरीत कम हो गए (सारणी IV.15)।

4.38 बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे, तत्काल देश जोखिम के आधार पर, मार्च 2009 के अंत में 32.6 प्रतिशत बढ़े जबकि पिछले वर्ष के दौरान 13.5 प्रतशित बढ़े थे। समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में अल्पावधि दावों का हिस्सा (एक वर्ष से की अवशिष्ट अवधि पूर्णता के साथ) मार्च 2009 के अंत में घट गया जबकि दीर्घावधि दावों में तदनुरूपी वृद्धि हुई। बैंकों के समेकित

सारणी IV.14: गैर -सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की संरचना

(प्रतिशत)

लिखत	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	12 सितं. 2008 तक	11, सितं. 2009 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाणिज्यिक पत्र	3.1	2.7	2.7	5.4	9.4	11.5	13.9	10.8	5.1
बांड/डिबेंचर	84.2	81.5	79.2	68.9	59.0	49.2	40.8	46.2	22.6
शेयर	7.9	7.3	9.4	14.2	19.3	22.9	19.4	23.9	10.7
म्यूच्युअल फंड के यूनिट	4.9	8.5	8.7	11.5	12.3	16.3	25.8	19.0	61.7

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां।

सारणी IV.15: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - प्रकारानुसार

आस्ति	मार्च के अंत	
	2008	2009
1	2	3
अंतरराष्ट्रीय आस्तियां (1+2+3)	**2,22,711**	**2,29,356**
1. ऋण और जमाराशियां	2,12,126	2,19,547
	(95.2)	(95.7)
जिनमें से :		
क) अनिवासियों को ऋण*	8,565	8,341
	(3.8)	(3.6)
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण**	108,440	99,973
	(48.7)	(43.6)
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिल	49,011	44,564
	(22.0)	(19.4)
घ) *नोस्ट्रो* शेष@	45,752	66,496
	(20.5)	(29.0)
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	334	76
	(0.1)	(0.0)
3. अन्य आस्तियां @@	10,250	9,733
	(4.6)	(4.2)

* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण को शामिल किया गया है।

** : एफसीएनआर (बी) जमाराशियों से दिए गए ऋण और पीसीएफसी तथा एफसी को दिए गए उधार भारत के बैंकों में जमा राशियां।

@ : विदेश के प्लेसमेंट एवं अनिवासी के बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियाँ।

@@ : भारतीय बैंकों की शाखाओं/सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत : लोकेशनल बैंकिंग स्टॅटिस्टिक्स।

अंतरराष्ट्रीय दावों का क्षेत्रवार श्रेणीकरण दर्शाता है कि बैंकों के हिस्से में सुधार हुआ (पिछले वर्ष के 36.8 प्रतिशत की तुलना में 45.5 प्रतिशत) और बैंकेतर निजी क्षेत्र में तदनुरूपी गिरावट हुई (सारणी IV.16)।

4.39 बैंकों के देशवार समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों, तत्काल देश जोखिम के आधार पर, में मार्च 2009 के अंत में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। जहां यूएस, यूके, हांग कांग और संयुक्त अरब अमिरात पर दावों का हिस्सा बढ़ गया, वहीं जर्मनी का हिस्सा कम हो गया। यूएस, यूके, सिंगापुर और हांग कांग पर संयुक्त दावे कुल अंतरराष्ट्रीय दावों के 50 प्रतिशत से अधिक थे (सारणी IV.17)।

सारणी IV.16: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - अवधिपूर्णता एवं क्षेत्रवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

अवशिष्ट अवधिपूर्णता /क्षेत्र	2008	2009
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**1,69,481**	**2,24,665**
(क) अवधिपूर्णतावार		
1) अल्पावधि (अवशिष्ट अवधिपूर्णता एक वर्ष से कम)	1,17,279	1,40,289
	(69.2)	(62.4)
2) दीर्घावधि (अवशिष्ट अवधिपूर्णता एक वर्ष तथा उससे अधिक)	50,232	79,828
	(29.6)	(35.5)
3) अनाबंटित	1,970	4,548
	(1.2)	(2.0)
(ख) क्षेत्रवार		
1) बैंक	62,394	1,02,223
	(36.8)	(45.5)
2) बैंकेतर सरकारी	748	656
	(0.4)	(0.3)
3) बैंकेतर निजी	1,06,339	1,21,786
	(62.7)	(54.2)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते है।

2. अनाबंटित अवशिष्ट अवधिपूर्णता में गैर लागू अवधिपूर्णता (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई अवधिपूर्णता सूचना शामिल है।

3. बैंक क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आइएफसी, ईसीबी आदि,) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।

4. मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व बैंकेतर सरकारी क्षेत्र में ऐसे बैंकों को छोड़कर जिनमें राज्य / केंद्रीय सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य/केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित कंपनियां/ संस्थाएं शामिल थीं। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर पब्लिक' क्षेत्र में केवल राज्य / केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं तथा तद्नुसार बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं को 'बैंकेतर प्राइवेट' क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा रहा है।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) विवरण पर आधारित - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

तिमाही प्रवृत्ति-वाणिज्य बैंकिंग सर्वेक्षण [8]

4.40 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यों के तिमाही विश्लेषण से अनेक महत्वपूर्ण बातों का पता चला (सारणी IV.18,परिशिष्ट सारणी IV.12)। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, बैंकों द्वारा जमाराशि का संग्रह 2008-09 की पहली दो तिमाहियों में कम रहा, यह संग्रह अगली दो तिमाहियों में बढ़ गया और यह पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिक था। दूसरी ओर, ऋण विस्तार में मिश्रित स्वरूप देखा गया। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में 2008-09 की पहली दो तिमाहियों के दौरान वृद्धि हुई और

[8] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 42 (2) विवरणीयों के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर।

सारणी IV.17: भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008	2009
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**1,69,481**	**2,24,665**
जिनमें से :		
क) संयुक्त राज्य अमरीका	35,374	55,734
	(20.9)	(24.8)
ख) यूनाइटेड किंगडम	21,899	29,753
	(12.9)	(13.2)
ग) सिंगापुर	11,918	15,762
	(7.0)	(7.0)
घ) जर्मनी	10,607	9,869
	(6.3)	(4.4)
ड) हांगकांग	9,792	19,031
	(5.8)	(8.5)
च) संयुक्त अरब अमीरात	7,990	11,309
	(4.7)	(5.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों के प्रतिशत अंश हैं।
स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

अक्तूबर 2008 में वह शीर्ष पर पहुंच गया। 2008-09 की बाद की तिमाहियों में बैंक ऋण में सतत गिरावट देखी गई। इससे बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश बढ़ाने का अवसर मिला।

2009-10 का घटनाक्रम

4.41 2009-10 के दौरान अब तक (25 सितंबर 2009 तक), एससीबी से ऋण के प्रवाह में लगातार गिरावट आई जो आर्थिक गतिविधियों में मंदी दर्शाती है। यह गिरावट विशेष रूप से निजी और विदेशी बैंकों के मामले में अधिक स्पष्ट थी ।

ऋण-जमा अनुपात

4.42 एससीबी के वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात और निवेश-जमा (आइ-डी) अनुपात ने निवेश और ऋण के संबंध में बैंकों का व्यवहार दर्शाया। ऋण वृद्धि के उच्च चरण (2002-03

सारणी IV.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	27 मार्च 2009 को बकाया	घट-बढ									
		2007-08				2008-09				2009-10	
		ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
घटक											
1. निवासियों की कुल जमाराशियां (क+ख)	37,66,842	58,993	2,08,191	67,544	2,60,803	53,155	1,83,287	1,11,471	2,78,925	1,30,600	1,54,127
क) मांग जमाराशियां	5,23,085	-41,898	57,771	-7,894	86,600	-77,630	52,219	-60,449	84,635	-32,922	61,410
ख) मीयादी जमाराशियां	32,43,757	1,00,890	1,50,420	75,439	1,74,204	1,30,785	1,31,068	1,71,920	1,94,290	1,63,522	92,717
2. मांग/मीयादी निधीयन	1,13,936	-2,984	5,756	7,441	10,455	-1,116	7,015	-685	2,217	-15,786	-3,561
स्रोत											
1. सरकार को ऋण	11,55,786	50,067	68,965	27,436	36,136	33,245	-19,641	99,566	83,955	1,26,014	75,338
2. वाणिज्य क्षेत्र को ऋण (क से ग)	29,95,361	-13,527	1,34,775	94,969	2,42,980	40,471	1,30,938	1,25,746	1,49,109	62,935	60,661
क. बैंक ऋण	27,75,549	-36,348	1,42,638	87,012	2,37,422	31,325	1,57,787	92,708	1,31,815	-7,563	1,05,169
i. खाद्य ऋण	46,211	-2,564	-6,948	3,259	4,131	5,748	-4,971	6,934	-5,899	14,450	-18,244
ii. खाद्येतर ऋण	27,29,338	-33,784	1,49,586	83,752	2,33,291	25,577	1,62,758	85,774	1,37,714	-22,014	1,23,413
ख. प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	1,671	-282	780	1,370	-1,146	-797	-1,174	1,520	-1,400	-508	3,753
ग. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10,624	-384	-1,010	-654	-357	-194	-567	-1,360	-309	-96	6,221
घ. अन्य निवेश (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में)	2,07,517	23,487	-7,634	7,241	7,061	10,136	-25,109	32,877	19,003	71,967	-54,482
3. वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (क+ख-ग)	-53,359	2,817	-16,584	974	-16,793	-19,924	-5,564	33,708	8,618	27,733	-26,244
क. विदेशी मुद्रा	55,312	-8,312	-9,934	-781	-8,537	-8,383	2,934	24,151	5,421	18,428	-29,440
ख. अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशि	67,268	-4,202	-1,181	-3,490	-1,653	2,048	3,898	-2,323	6,710	755	416
ग. समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	41,404	-6,928	7,830	1,734	9,909	9,494	4,600	-7,234	-9,907	-10,060	-3,611
4. निवल बैंक आरक्षित निधियां	2,46,748	6,468	76,009	-22,695	21,268	28,526	35,997	-1,16,193	27,252	-17,189	20,787
5. पूंजी खाता	3,32,444	26,813	24,184	6,887	11,937	47,618	4,932	3,043	4,230	41,256	2,584

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

से 2006-07) के दौरान दो श्रृंखलाएं एक-दूसरे से अलग हो गईं क्योंकि सी-डी अनुपात तेजी से बढ़ा और परिणामस्वरूप आइ-डी अनुपात कम हो गया जो बैंकों द्वारा निवेश की तुलना में उधार को तरजीह देना दर्शाता है। वस्तुत:, बैंकों ने 2005-06 में कुछ निवेश समाप्त कर दिया था जिससे वृद्धिशील आइ-डी अनुपात में तेज गिरावट हुई। किंतु, बाद में चक्रीय कारकों के कारण ऋण वृद्धि की दर कम हो जाने के कारण वृद्धिशील सी-डी अनुपात और आइ-डी अनुपात की प्रवृत्ति बदल गई। सितंबर 2008 के बाद की अवधि के दौरान, वृद्धिशील सी-डी अनुपात तेजी से कम हो गया जो ऋण वृद्धि में मंदी दर्शाता है। ऋण वृद्धि में मंदी यह दर्शाती है कि व्यापक मंदी को देखते हुए कंपनियों ने अपने निवेश आस्थगित कर दिए थे। इसके परिणामस्वरूप, वृद्धिशील आइ-डी अनुपात बढ़ गया, हालांकि ब्याज दरें कम हुई थीं (चार्ट IV.5)।

4.43 बकाया राशि पर आधारित सी-डी अनुपात और आइ-डी अनुपात पिछले तीन वर्षों से लगभग स्थिर रहे हैं। इस प्रकार, सी-डी अनुपात, जो 2007-08 में 74.6 प्रतिशत था, मार्च 2009 के अंत में थोड़ा कम होकर 73.9 प्रतिशत रह गया जबकि आइ-डी अनुपात इसी अवधि के दौरान 35.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 35.7 प्रतिशत हो गया।

4.44 बैंक समूहों के बीच, निजी क्षेत्र के नए बैंकों का सी-डी अनुपात (बकाया राशि के संदर्भ में) मार्च 2009 के अंत में सर्वाधिक था, इसके बाद विदेशी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्थान था (चार्ट IV.6)। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का सी-डी अनुपात लगातार निम्नतम बना रहा।

4.45 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आइडीबीआइ बैंक लि. छोड़कर, का सी-डी अनुपात दायराबद्ध बना रहा जो पिछले वर्ष के स्वरूप जैसा ही था। यह दायरा 64.9 प्रतिशत (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) और 77.8 प्रतिशत (स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर) के बीच था। किंतु, आइडीबीआइ बैंक लि. का सी-डी अनुपात 92.0 प्रतिशत पर बहुत अधिक था। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में, सी-डी अनुपात 51.2 प्रतिशत (बैंक ऑफ राजस्थान) और 71.3 प्रतिशत (लक्ष्मी विलास बैंक) के दायरे में था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों का सी-डी अनुपात 69.2 प्रतिशत (एचडीएफसी बैंक) और 106.3 प्रतिशत (कोटक महिंद्रा बैंक) के दायरे में था। शीर्ष पांच विदेशी बैंकों के मामले में सी-डी अनुपात 55.2 प्रतिशत (हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन) और 104.4 प्रतिशत (एबीएन अम्रो बैंक) के दायरे में था। 30 विदेशी बैंकों में से 9 बैंकों का सी-डी अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था। इससे पता चलता है कि उधार के मामले में विदेशी

चार्ट IV.5: एससीबी का ऋण और निवेश-जमा अनुपात

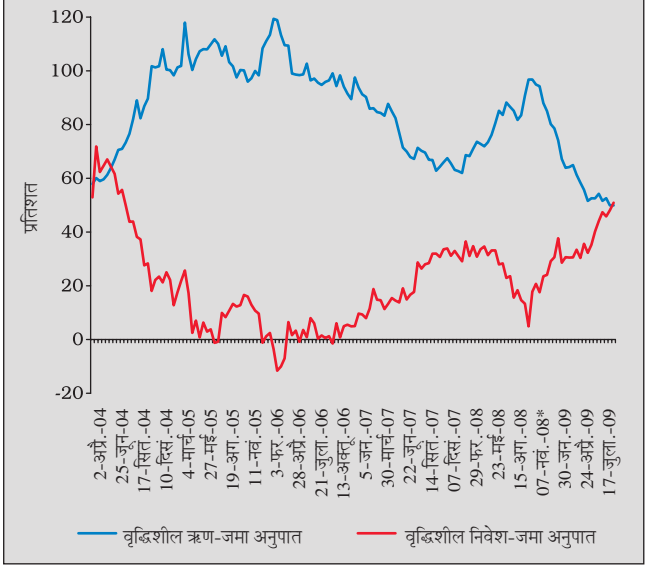

चार्ट IV.6: ऋण-जमा अनुपात-बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

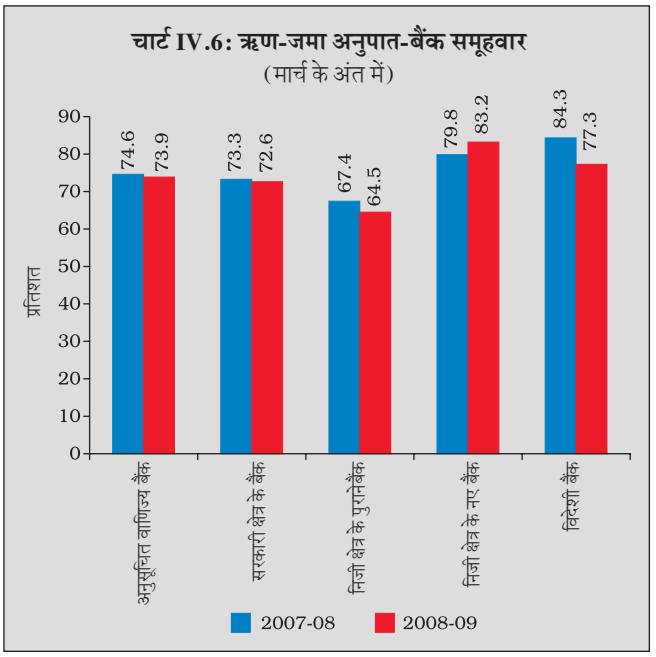

बैंक बहुत सक्रिय थे और इनके बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक मध्यम मार्ग अपना रहे थे (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

बैंकों की आस्तियों और देयताओं का अवधिपूर्णता प्रोफाइल

4.46 निजी क्षेत्र के बैंकों की अवधिपूर्णता की संरचना के व्यापक स्वरूप से पता चलता है कि अल्पावधि अवधिपूर्णता (एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता) से मध्यावधि अवधिपूर्णता (1-3 वर्ष और 3-5 वर्ष) की ओर रुझान हुआ है। यह 2008-09 की पहली छमाही में सावधि ब्याज दर बढ़ने का संकेत है और दीर्घावधि परियोजनाओं के वित्तपोषण की दृष्टि से अच्छी बात है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के संबंध में यह स्वरूप उधार के मामले में भी स्पष्ट है जहां अधिमान अल्पावधि अवधिपूर्णता से दीर्घावधि अवधिपूर्णता समूह की ओर अंतरित हो गया। इसके विपरीत, निवेश स्वरूप से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के पुराने और विदेशी बैंकों के मामले में मध्यावधि (1-3 वर्ष) से 1 वर्ष के अवधिपूर्णता समूह की ओर अंतरित हो गया जो बैंकों की यह धारणा दर्शाता है कि निकट भविष्य में ब्याज दर बढ़ेंगे। मार्च 2009 के अंत में, विदेशी बैंकों जमाराशियों, उधार, ऋण और अग्रिम के साथ ही निवेश का अधिकतर हिस्सा अल्पावधि अवधिपूर्णता समूह में था। किंतु, इसके विपरीत सरकारी बैंकों की जमाराशियां, उधार और ऋण तथा अग्रिम अल्पावधि थे जबकि निवेश दीर्घावधि थे (सारणी IV.19)।

3. तुलनपत्रेतर परिचालन

4.47 एससीबी के तुलनपत्रेतर परिचालन जिनमें वायदा विनिमय संविदाएं, गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन आदि शामिल होते हैं, हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गए। किंतु, 2008-09 इस प्रवृत्ति से भिन्न रहा जिसमें एससीबी ने अपने तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर पिछले वर्ष की तुलना में 26.4 प्रतिशत कम कर दिए (चार्ट IV.7)। इसने आंशिक रूप से यह दर्शाया कि रिज़र्व बैंक द्वारा ओबीएस एक्सपोजर पर लागू किए गए विवेक सम्मत विनियमन मजबूत हुए थे।

4.48 ओबीएस में गिरावट विशेष रूप से विदेशी बैंकों के मामले में स्पष्ट थी जिनकी आकस्मिक देयताएं समग्र रूप से और कुल

सारणी IV.19: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का बैंक समूहवार अवधिपूर्णता स्वरूप

(मार्च के अंत में)

(कुल में प्रतिशत)

आस्तियां/देयताएं	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां								
क) एक वर्ष तक	44.1	45.7	50.9	48.3	57.1	53.1	64.7	63.8
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	26.5	27.3	35.5	38.4	34.3	35.6	33.3	23.1
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	10.3	8.4	7.7	8.4	2.5	3.7	0.4	9.6
घ) पांच वर्ष से अधिक	19.1	18.7	6.0	4.9	6.0	7.6	1.6	3.5
II. उधार राशियां								
क) एक वर्ष तक	69.6	70.8	79.1	76.7	49.2	44.3	90.9	84.8
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	16.5	23.9	5.4	7.8	25.4	30.8	8.4	13.9
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	6.0	3.6	3.0	5.7	21.9	19.3	0.3	1.3
घ) पांच वर्ष से अधिक	7.9	1.7	12.5	9.8	3.5	5.5	0.3	0.0
III. ऋण और अग्रिम								
क) एक वर्ष तक	38.0	39.1	40.4	40.8	33.6	32.4	49.6	55.8
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	33.3	33.5	36.1	35.5	34.2	35.5	34.4	24.1
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.2	9.9	11.5	12.3	12.2	14.0	6.6	10.1
घ) पांच वर्ष से अधिक	17.6	17.5	12.0	11.4	19.9	18.1	9.4	10.0
IV. निवेश								
क) एक वर्ष तक	19.0	22.8	21.3	37.2	55.8	46.3	62.2	69.0
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	19.0	14.9	16.5	7.1	21.1	25.0	25.9	18.8
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	13.8	15.5	12.2	11.1	5.4	5.5	4.1	6.0
घ) पांच वर्ष से अधिक	48.2	46.8	50.0	44.7	17.6	23.2	7.8	6.2

चार्ट IV.7: कुल आस्तियों की तुलना में तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र
(मार्च के अंत में)

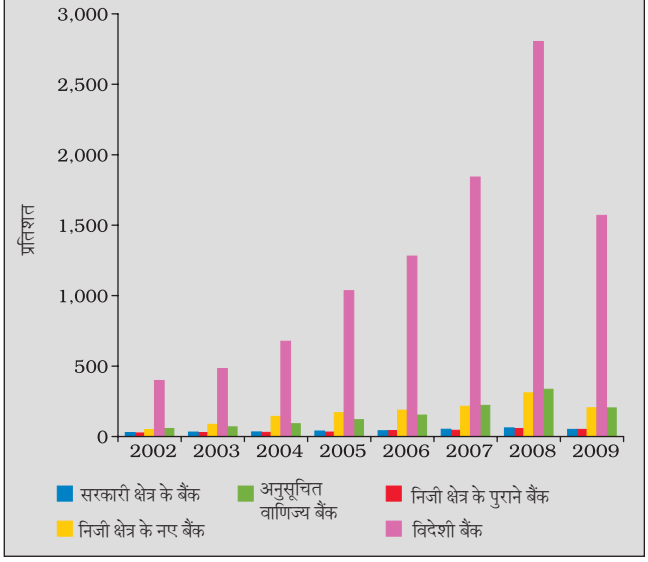

देयताओं के प्रतिशत के रूप में भी सर्वाधिक थीं। विदेशी बैंकों के अलावा, स्टेट बैंक समूह और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के ओबीएस में गिरावट हुई (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

4.49 एससीबी के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी बैंकों का बना रहा (65.8 प्रतिशत), इनके बाद सरकारी क्षेत्र के बैंक (17.9 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र के नए बैंक (15.2 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.8)।

चार्ट IV.8: तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र में बैंक समूहवार अंश
(मार्च के अंत में)

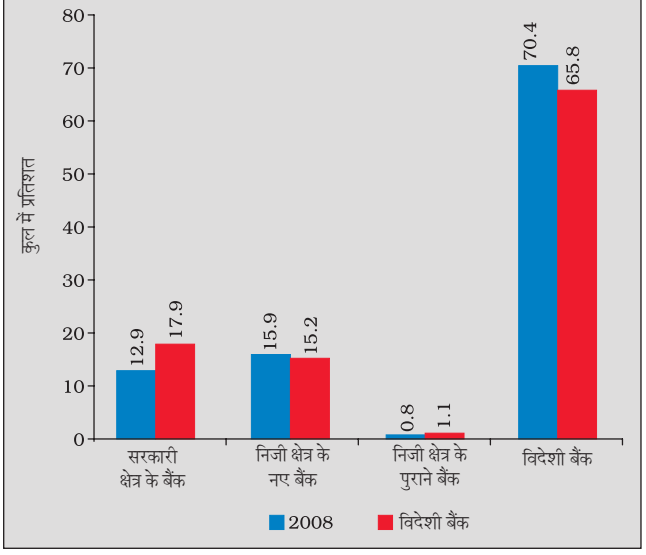

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य - निष्पादन

4.50 भारत स्थित एससीबी के तुलनपत्र वैश्विक वित्तीय संकट और विभिन्न अंतरण माध्यमों से इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के समय भी मजबूत बने रहे। किंतु, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी से पूर्णत: अप्रभावित नहीं रहा जैसा कि एससीबी के वित्तीय कार्य निष्पादन से स्पष्ट है। एससीबी की आय और व्यय की वृद्धि दर कम हो गई जिससे निवल लाभ भी कम हो गया। लाभ-वृद्धि में इस गिरावट का कारण जमाराशि और उधार की लागत में वृद्धि किंतु निवेश पर प्रतिलाभ का कम होते जाना था। किंतु, आरओए और आरओई जैसे कार्य कुशलता मानदंडों में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। संक्षेप में, वित्तीय क्षेत्र की आकलन रिपोर्ट (2009) में रेखांकित किए अनुसार, ''भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के आघातों को सह लिया और किसी भी मुख्य वित्तीय मानदंड ने कोई भी विशेष भेद्यता नहीं दर्शाई''।

ब्याज दर परिदृश्य

4.51 विभिन्न बैंक समूहों के बीच एससीबी की जमा और उधार दरों ने 2008-09 की पहली छमाही के दौरान सामान्यत: ऊर्ध्वमुखी रुख दर्शाया। रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा से संकेत लेते हुए एससीबी ने 2008-09 की दूसरी छमाही में अपनी जमा और उधार दरें कम कर दीं । 2009-10 की पहली छमाही (11 सितंबर 2009 तक) एससीबी की जमा और उधार दरें और कम हो गईं (सारणी IV.20 और चार्ट IV.9)।

जमाओं की लागत और अग्रिमों पर प्रतिलाभ

4.52 ब्याज दरों में विशेष रूप से 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान कमी आने के बावजूद एससीबी की निधियों और जमाराशि की लागत तथा उधार की लागत पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी। इसी अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण वार्षिक मौद्रिक नीति दस्तावेज में दर्शाए

सारणी IV.20: जमा और उधार की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

ब्याज दरें	मार्च 2007	मार्च 2008	अक्तू. 2008	मार्च 2009	जून 2009	सितं. 2009**
1	2	3	4	5	6	7
आवधिक जमा दर						
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
क) 1 वर्ष तक	2.75-8.75	2.75-8.50	2.75-10.25	2.75-8.25	1.00-7.00	1.00-6.75
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	7.25-9.50	8.25-9.25	9.50-10.75	8.00-9.25	6.50-8.00	6.50-7.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	7.50-9.50	8.00-9.00	8.50-9.75	7.50-9.00	6.75-8.50	6.50-8.00
निजी क्षेत्र के बैंक						
क) 1 वर्ष तक	3.00-9.00	2.50-9.25	3.00-10.50	3.00-8.75	2.00-7.50	2.00-7.00
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	6.75-9.75	7.25-9.25	9.00-11.00	7.50-10.25	6.00-8.75	5.25-8.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	7.75-9.60	7.25-9.75	8.25-11.00	7.50-9.75	6.00-9.00	5.75-8.25
विदेशी बैंक						
क) 1 वर्ष तक	3.00-9.50	2.25-9.25	3.50-10.75	2.50-8.50	1.80-8.00	1.25-8.00
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3.50-9.50	3.50-9.75	3.50-11.25	2.50-9.50	2.25-8.50	2.25-8.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	4.05-9.50	3.60-9.50	3.60-11.00	2.50-10.00	2.25-9.50	2.25-8.50
बेंच मार्क मूल उधार दर						
सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.25-12.75	12.25-13.50	13.75-14.75	11.50-14.00	11.00-13.50	11.00-13.50
निजी क्षेत्र के बैंक	12.00-16.50	13.00-16.50	13.75-17.75	12.75-16.75	12.50-16.75	12.50-16.70
विदेशी बैंक	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-17.00	10.00-17.00	10.50-16.00	10.50-16.00
वास्तविक उधार दर*						
सरकारी क्षेत्र के बैंक	4.00-17.00	4.00-17.75	–	3.50-18.00	3.50-17.50	–
निजी क्षेत्र के बैंक	3.15-25.50	4.00-24.00	–	4.75-26.00	4.10-26.00	–
विदेशी बैंक	5.00-26.50	5.00-28.00	–	5.00-25.50	2.76-25.50	–

– : अनुपलब्ध।

* : दोनो पक्षों से अधिकतम पांच प्रतिशत ऋण दर को छोड़कर 2 लाख रुपए से अधिक निर्यात से इतर मांग तथा मीयादी ऋण पर ब्याज दर।

** : 11 सितम्बर 2009 की स्थिति के अनुसार ।

स्रोत : बैंको से विशिष्ट पखवाड़ा आधार पर (VI-बी,VI ए बी) / तिमाही (VI-ए सी) प्राप्त विवरणियां।

चार्ट IV.9: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार दरों के बीच स्प्रेड

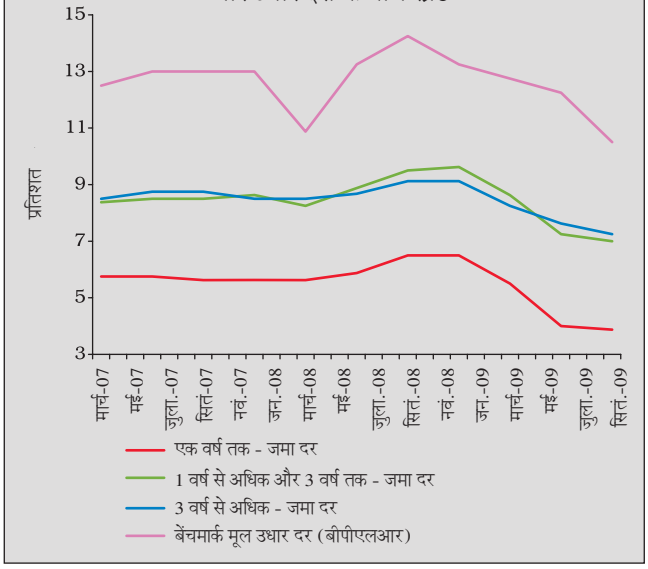

अनुसार ब्याज दरों में अनेक संरचनात्मक कड़ाइयां थीं। लागत और प्रतिलाभ की इन प्रवृत्तियों ने बैंकों के स्प्रेड पर प्रतिकूल प्रभाव डाला यह प्रवृत्ति लगभग सभी बैंक समूहों में देखी गई (सारणी IV.21)।

आय

4.53 एससीबी की आय वृद्धि 2008-09 के कम होकर 25.7 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 34.3 प्रतिशत थी किंतु 2006-07 की 24.4 प्रतिशत से अधिक थी। आस्तियों के प्रति आय का अनुपात पिछले वर्ष के 8.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गया। कम उधार दर दर्शाते हुए मार्च 2009 के अंत में एससीबी की ब्याज आय वृद्धि पिछले वर्ष के 33.2 प्रतिशत से कम होकर 26.0 प्रतिशत रह गई (सारणी IV.22)।

सारणी IV.21 : निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

संकेतक	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. जमा की लागत	5.4	5.6	5.7	6.2	5.9	6.4	3.8	4.3	5.4	5.7
2. उधारों की लागत	3.5	4.0	4.6	5.0	3.1	3.7	4.5	3.9	3.6	3.9
3. निधियों की लागत	5.3	5.5	5.7	6.1	5.5	6.0	3.9	4.2	5.3	5.5
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ	8.6	9.1	9.6	11.0	10.0	10.8	9.8	12.4	8.9	9.6
5. निवेशों पर प्रतिलाभ	6.6	6.2	6.3	5.7	6.4	6.9	7.1	6.7	6.6	6.4
6. निधियों पर प्रतिलाभ	8.0	8.2	8.5	9.1	8.7	9.5	8.7	9.9	8.2	8.5
7. अंतर (स्प्रेड) (6-3)	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.5	4.8	5.7	2.9	3.0

टिप्पणी : 1. जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / जमाराशियां।
2. उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / उधार।
3. निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (जमाराशियां + उधार)।
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / अग्रिम।
5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / निवेश।
6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर प्रतिलाभ) / (अग्रिम+निवेश)।

4.54 कुल आय में ब्याजेतर आय का हिस्सा 2002-2004 की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ता रहा किंतु बाद की अवधि अर्थात 2005-07 में कम हुआ। किंतु, पिछले दो वर्षों में इसमें पुन: वृद्धि हुई और ब्याज आय के हिस्से में तदनुरूपी गिरावट हुई (चार्ट IV.10)।

4.55 2004-05 से 2007-08 के बीच ब्याजेतर आय में ब्याज आय और कुल आय की वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति के विपरीत 2008-09 के दौरान ब्याजेतर आय वृद्धि में हुई गिरावट दो अन्य श्रृंखलाओं की तुलना में बहुत तेज थी (चार्ट IV.11)।

4.56 2008-09 के दौरान लेनदेन आय की वृद्धि दर कम होकर 40.2 प्रतिशत रह गई किंतु विदेशी मुद्रा आय की वृद्धि दर बढ़कर 44.1 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.15)।

4.57 बैंक समूहों के बीच, 2008-09 के दौरान विदेशी बैंकों की आय सर्वाधिक दर (29.2 प्रतिशत) से बढ़ी, इसके पश्चात

सारणी IV.22 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07		2007-08		2008-09	
	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आय	2,74,716	7.9	3,68,873	8.5	4,63,837	8.8
क) ब्याज आय	2,31,675	6.7	3,08,482	7.1	3,88,816	7.4
ख) अन्य आय	43,041	1.2	60,391	1.4	75,021	1.4
2. व्यय	2,43,514	7.0	3,26,147	7.5	4,11,066	7.8
क) खर्च किया गया ब्याज	1,42,420	4.1	2,08,001	4.8	2,63,221	5.0
ख) परिचालन व्यय	66,319	1.9	77,283	1.8	89,268	1.7
जिसमें से: वेतन बिल	36,148	1.0	39,954	0.9	47,660	0.9
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	34,775	1.0	40,864	0.9	58,578	1.1
3. परिचालन लाभ	65,977	1.9	83,590	1.9	1,11,349	2.1
4. निवल लाभ	31,203	0.9	42,726	1.0	52,771	1.0
5. निवल ब्याज आय/मार्जिन (1क-2क)	89,255	2.6	1,00,481	2.3	1,25,596	2.4

टिप्पणी : 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या क्रमश: 82, 79 और 80 थी।

चार्ट IV.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज तथा ब्याज से इतर आय का अंश

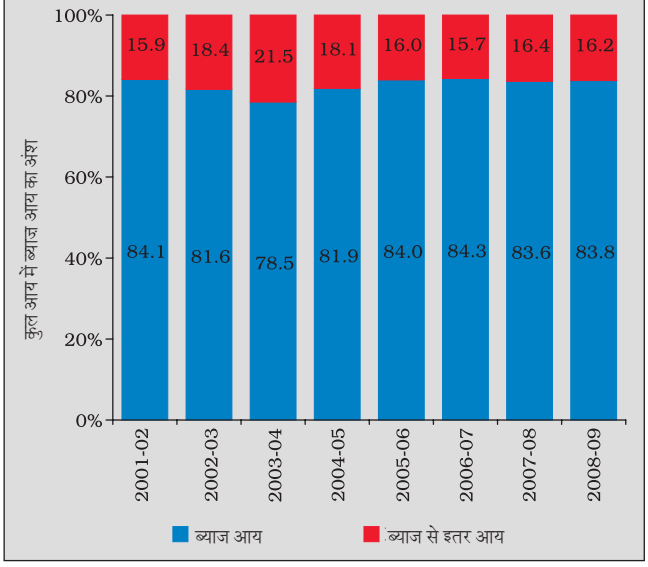

सरकारी क्षेत्र के बैंक (28.4 प्रतिशत) एकदम करीब थे। सभी बैंक समूहों के कुल आस्ति-ब्याज आय अनुपात में सुधार हुआ जबकि एसबीआइ समूह के ये अनुपात अपरिवर्तित बने रहे। एससीबी के 'अन्य आय' घटक में गिरावट आई। यह गिरावट एसबीआइ समूह को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों में देखी गई [परिशिष्ट सारणी IV.16, परिशिष्ट सारणी IV.17(ए से जी)]।

चार्ट IV.11: ब्याज और ब्याज से इतर आय की वृद्धि दर

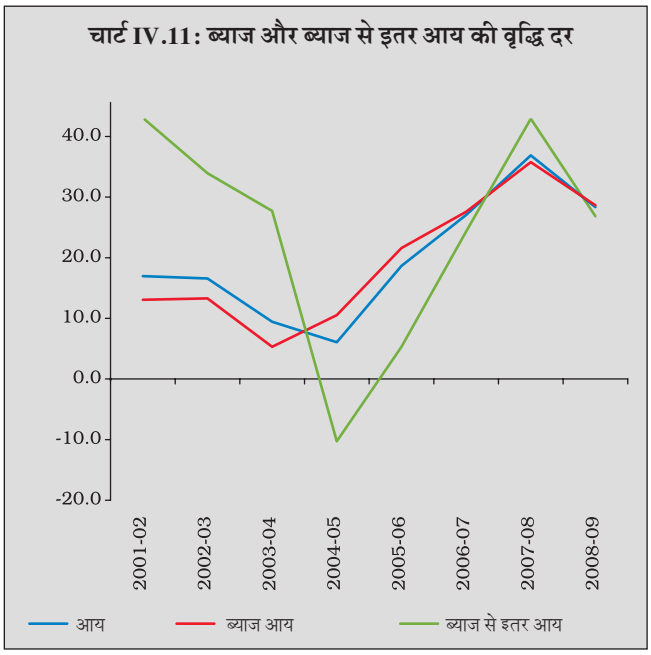

व्यय

4.58 मार्च 2009 के अंत में, एससीबी का व्यय कम होकर 26.0 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष 33.9 प्रतिशत था। एससीबी के व्यय के बड़े घटकों के बीच, व्यय किए गए ब्याज की वृद्ध-दर तेजी से कम होकर 26.5 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 46.0 प्रतिशत बढ़ी थी। ब्याजेतर या परिचालन व्यय भी कम हो गए जबकि प्रावधानीकरण में तेज वृद्धि हुई (सारणी IV.23)।

4.59 कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किए गए ब्याज का अनुपात एससीबी के मामले में 2005-06 से बढ़ रहा है। इस प्रवृत्ति के अनुकूल, यह अनुपात 2008-09 में बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गया जो कि पिछले वर्ष 4.8 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.22)। इस प्रवृत्ति के बदलाव में, एससीबी की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय, जिसमें 2004-08 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति थी, बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.23)। इसी प्रकार, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधानीकरण और प्रासंगिक व्यय भी 2004-2008 की गिरावट के बाद 2008-09 में पहली बार बढ़े(परिशिष्ट सारणी IV.24)। किंतु, कुल आस्ति-परिचालन व्यय अनुपात के मामले में यह प्रवृत्ति जारी रही और यह अनुपात 2008-09 में कम होकर 1.7 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष 1.8 प्रतिशत

सारणी IV.23 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय-व्यय में घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08		2008-09	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क + ख)	**94,157**	**34.3**	**94,964**	**25.7**
क) ब्याज आय	76,807	33.2	80,334	26.0
ख) अन्य आय	17,350	40.3	14,630	24.2
2. व्यय (क + ख + ग)	**82,634**	**33.9**	**84,918**	**26.0**
क) ब्याज व्यय	65,581	46.0	55,219	26.5
ख) अन्य व्यय	10,963	16.5	11,985	15.5
ग) प्रावधानन	6,089	17.5	17,714	43.3
3. परिचालन लाभ	**17,612**	**26.7**	**27,759**	**33.2**
4. निवल लाभ	**11,523**	**36.9**	**10,046**	**23.5**

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

था (परिशिष्ट सारणी IV.25)। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों का भार (ब्याजेतर आय की तुलना में ब्याजेतर व्यय) 2007-08 की कुल आस्तियों के 0.4 प्रतिशत और 2006-07 के 0.7 प्रतिशत से बहुत कम होकर 2008-09 में 0.3 प्रतिशत रह गया। कुशलता अनुपात (निवल ब्याज आय के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय + ब्याजेतर आय) 2006-07 के 50.1 प्रतिशत से और मार्च 2008 के अंत के 48.0 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 44.5 प्रतिशत रह गया जो ब्याजेतर आय में वृद्धि और परिचालन व्यय में गिरावट दर्शाता है जो संयुक्त रूप से निवल ब्याज आय में गिरावट से अधिक थे (कुल आस्तियों के संदर्भ में)।

4.60 अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी दर्शाते हुए, परिचालन व्यय में वेतन का हिस्सा अधिकांश बैंक समूहों के मामले में वर्ष के दौरान लगभग स्थिर बना रहा (चार्ट IV.12)। एससीबी के वेतन के हिस्से में हुई थोड़ी वृद्धि में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान था। इन दोनों बैंक समूहों के मामले में वेतन बिल में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में, एसीबी का वेतन बिल पिछले वर्ष जैसा ही 0.9 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। वस्तुत:, कुल आस्ति-वेतन बिल अनुपात निजी क्षेत्र के नए बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों के मामले में अपरिवर्तित बना रहा।

चार्ट IV.12: परिचालन व्यय की तुलना में वेतन बिल

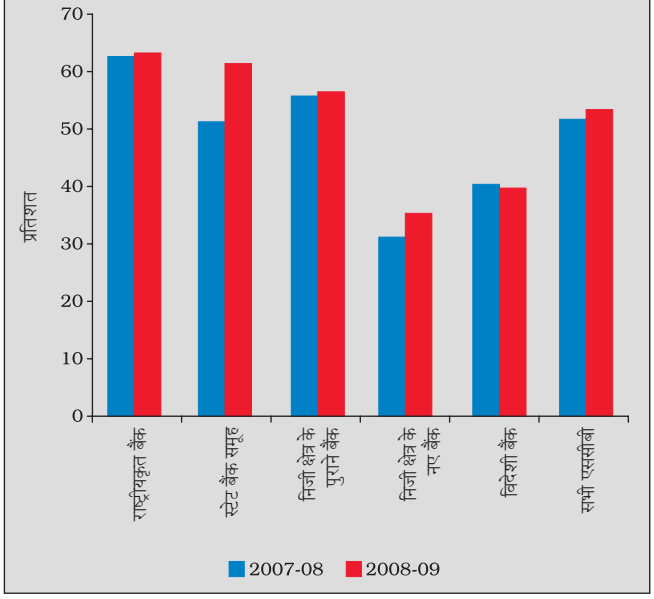

निवल ब्याज आय

4.61 एससीबी की निवल ब्याज आय, अर्थात ब्याज आय और ब्याज व्यय के बीच का अंतर, 2008-09 में तेजी से बढ़ गया जो मुख्यत: वर्ष के दौरान अलग-अलग समय लागू ब्याज दरों की भिन्नता दर्शाता है। वर्ष के दौरान स्टेट बैंक समूह को छोड़कर लगभग सभी बैंक समूहों का आस्ति-निवल ब्याज आय अनुपात बढ़ गया (परिशिष्ट सारणी IV.23)।

परिचालन लाभ

4.62 एससीबी के परिचालन लाभ में मार्च 2009 के अंत में 33.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण ब्याज व्यय घटक की वृद्धि दर में तेज गिरावट था। इस तेज वृद्धि के कारण 2008-09 के दौरान कुल आस्ति-परिचालन लाभ 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया। बैंक समूहवार विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ तेजी से बढ़ा किंतु निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का के संबंध में मंदी रही। आस्ति-परिचालन लाभ अनुपात 'सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक' छोड़कर बाकी सभी बैंक समूहों के मामले में बढ़ा (परिशिष्ट सारणी IV.16)।

प्रावधान और आकस्मिक व्यय

4.63 एससीबी के प्रावधान और आकस्मिक व्यय 2008-09 के दौरान 43.4 प्रतिशत की बहुत अधिक दर पर बढ़े जबकि पिछले वर्ष यह दर 17.7 प्रतिशत थी। एसपीए के लिए प्रावधान में 43.0 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष 28.4 प्रतिशत थी। बैंक समूहवार, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय 'सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक' के संबंध में कम हो गए जबकि अन्य सभी बैंक समूहों के संबंध में बढ़ गए।

निवल लाभ

4.64 एससीबी के निवल लाभ में वृद्धि 2008-09 के दौरान कम होकर 23.5 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 36.9 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण प्रावधान और आकस्मिक व्यय में तेज वृद्धि होना था (सारणी IV.24)।

सारणी IV.24: परिचालन लाभ तथा निवल लाभ - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	परिचालन लाभ				निवल लाभ			
	2007-08	प्रतिशत घटबढ़	2008-09	प्रतिशत घटबढ़	2007-08	प्रतिशत घटबढ़	2008-09	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**83,590**	**26.7**	**1,11,349**	**33.2**	**42,726**	**36.9**	**52,771**	**23.5**
सरकारी क्षेत्र के बैंक	50,307	17.9	66,972	33.1	26,592	32.0	34,394	29.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	31,563	15.0	42,184	33.6	16,856	30.2	21,639	28.4
स्टेट बैंक समूह	17,444	22.1	23,410	34.2	9,006	37.0	11,896	32.1
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	1,299	43.3	1,378	6.0	729	15.7	859	17.7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3,604	19.3	4,799	33.2	1,978	76.3	2,409	21.8
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15,632	46.3	19,480	24.6	7,544	41.2	8,459	12.1
विदेशी बैंक	14,047	46.0	20,098	43.1	6,612	44.2	7,510	13.6

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

आस्तियों पर प्रतिलाभ

4.65 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) दक्षता का एक संकेतक है जिसके आधार पर बैंक अपनी आस्तियों को नियोजित करते हैं । 2008-09 के दौरान एससीबी का आस्तियों के प्रति निवल लाभ-अनुपात 2007-08 के 0.99 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 1.02 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.13)। वस्तुत:, विदेशी बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों का आरओए बढ़ गया।

इक्विटी पर प्रतिलाभ

4.66 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दक्षता के साथ पूंजी के उपयोग का संकेतक है। एससीबी का आरओई 2007-08 के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 13.2 प्रतिशत हो गया। बैंक समूहवार विश्लेषण दर्शाता है कि विदेशी बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों का आरओई 2008-09 के दौरान बढ़ गया।

चार्ट IV.13: भारत में बैंक समूहों की निवल लाभप्रदता

5. सुदृढ़ता संकेतक

4.67 वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सुदृढ़ और कार्यकुशल बैंकिंग प्रणाली अनिवार्य है। अत:, हाल के वर्षों में पूंजी अपेक्षाओं के सुदृढ़ीकरण पर काफी बल दिया गया है। एससीबी का जोखिम भारित आस्ति-प्रति अनुपात, जो अनपेक्षित हानियों को अवशोषित करने की बैंकिंग प्रणाली की क्षमता का मापक है, मार्च 2008 के अंत के 13.0 प्रतिशत से और सुधरकर मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत हो गया। भारत में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों से सुधार होता आया है जैसा कि अग्रिम-एनपीए अनुपात में गिरावट से दिखता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के दबाव और अनिश्चितता के वातावरण के बावजूद निवल अग्रिम-निवल एनपीए अनुपात मार्च 2008 के अंत के 1.0 प्रतिशत से थोड़ा ही बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 1.1 प्रतिशत हो गया। महत्वपूर्ण रूप से, सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। इस प्रकार, दो प्रमुख सुदृढ़ता संकेतकों, अर्थात पूंजी और आस्ति गुणवत्ता के संदर्भ में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने परीक्षा की घड़ी में आघात सहनीयता दर्शाई (चार्ट IV.14)।

चार्ट IV.14: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर और एनपीए में उतार-चढ़ाव

(मार्च के अंत में)

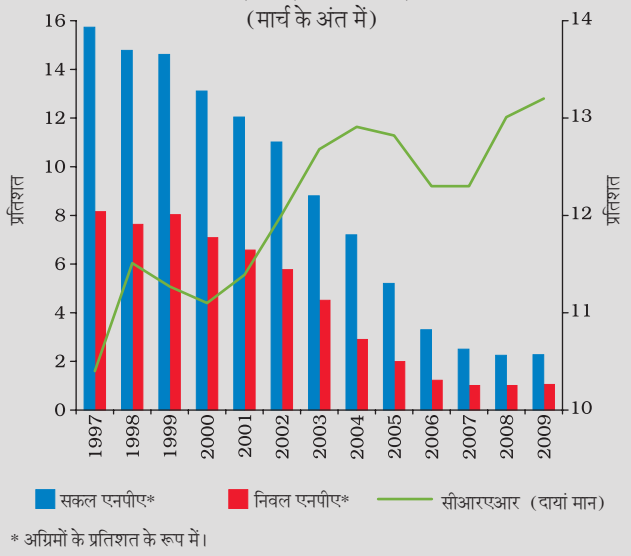

* अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।

आस्ति गुणवत्ता

4.68 वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति लगातार बनी रही। भारतीय बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान एनपीए की अधिक राशि वसूल की। 2008-09 के दौरान वसूली तथा बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि 38,828 करोड़ रुपए 2007-08 के 28,283 करोड़ रुपए से अधिक होने के बावजूद यह वर्ष के दौरान जुड़े नए एनपीए (52,382 करोड़ रुपए) से कम थी। इसके परिणामस्वरूप, एससीबी का सकल एनपीए सभी बैंकों के मामले में बढ़ गया (सारणी IV.25)। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान वित्तीय संकट के संदर्भ में एनपीए में कुछ गिरावट हो सकती है। फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि यह गिरावट विश्वभर के बैंकों द्वारा सामना की गई समस्याओं की तुलना में कम थी।

4.69 अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए बैंकों के समक्ष उपलब्ध वसूली के अनेक चैनलों में से ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और सरफेसाई अधिनियम वसूली गई राशि के संबंध में सर्वाधिक प्रभावशाली रहे हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से वसूल की गई राशि का प्रतिशत सर्वाधिक था, इसके बाद सरफेसाई अधिनियम का स्थान था (सारणी IV.26)।

सारणी IV.25 : अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहवार उतार चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल अनर्जक आस्तियाँ							
2007-08 का अंतिम शेष	56,309	40,452	23,410	15,478	2,557	10,440	2,859
2008-09 का प्रारंभिक शेष	55,419	40,089	23,410	15,303	2,557	9,901	2,872
2008-09 के दौरान जुड़ाव	52,382	31,338	17,822	12,879	2,094	10,520	8,430
2008-09 के दौरान वसूले गए	37,314	26,271	15,863	9,829	1,579	6,510	2,954
2008-09 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	1,514	0	0	0	0	0	1,514
2008-09 को अंतिम शेष	68,973	45,156	25,368	18,352	3,072	13,911	6,833
निवल अनर्जक आस्तियां							
2007-08 का अंतिम शेष	24,730	17,836	8,245	8,509	740	4,907	1,247
2008-09 को अंतिम शेष	31,424	21,033	9,339	10,745	1,165	6,253	2,973

टिप्पणी : 2007-08 का अंतिम शेष 2008-09 के प्रारंभिक शेष से निम्नलिखित कारणों से मेल नहीं खाता है: क) एक बैंक के मामले में 2007-08 का अंतिम शेष 2008-09 के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं खाता। ख) बैंकों के कुछ विलयन हुए हैं और नए विदेशी बैंक सकल एनपीए की धनात्मक प्रारंभिक शेष के साथ खुले।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

सारणी IV.26: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विविध माध्यमों के जरिए वसूल किया गया एनपीए

(राशि करोड़ रुपए)

वसूली माध्यम	2007-08				2008-09			
	संदर्भित मामलो की संख्या	शामिल राशि	वसूली गइ राशि	कॉलम (3) के प्रतिशत के रुप में कॉलम (4)	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कॉलम (3)के प्रतिशत के रुप में कॉलम (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	1,86,535	2,142	176	8.2	5,48,308	4,023	96	5.4
ii) डीआरटी	3,728	5,819	3,020	51.9	2,004	4,130	3,348	81.1
iii) सरफेसाई अधिनियम	83,942#	7,263	4,429	61.0	61,760	12,067	3,982	33.0

: जारी नोटिसों की संख्या।

4.70 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली दर (मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत) पिछले कुछ वर्षों से कम होता जा रहा है। इस प्रवृत्ति के अनुरूप, वसूली दर जून 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कम होकर 75.4 प्रतिशत रह गई जो कि एक वर्ष पूर्व 79.7 प्रतिशत थी (सारणी IV.27)।

4.71 रिज़र्व बैंक ने अभी तक 12 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किए हैं जिनमें से 11 ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। जून 2009 के अंत में, रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एससी/आरसी द्वारा अर्जित आस्तियों की कुल राशि का बही मूल्य 51,542 करोड़ रुपए था जो वर्ष के दौरान (जुलाई 2008 से जून 2009) 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जहां बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिदान की गई प्रतिभूति रसीदों की राशि 9,570 करोड़ रुपए थी, वहीं प्रतिभूति रसीदों की मोचित राशि 2,792 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.28)।

सारणी IV.27: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली

(राशि करोड़ रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेयताएं	मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2006	46,567	37,298	9,269	80.1
2007	73,802	58,840	14,958	79.7
2008	95,100	71,739	23,361	75.4

अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में गतिविधि

4.72 2008-09 के दौरान किया गया प्रावधान वर्ष के दौरान के अतिरिक्त प्रावधानीकरण के राइट-बॅक से अधिक था। फिर भी वर्ष के दौरान निवल एनपीए में वृद्धि हुई जिसका कारण सकल एनपीए में वृद्धि था। वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान सभी बैंक समूहों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के राइट-बॅक से अधकि थे। सकल एनपीए-संचयी प्रावधान अनुपात सभी बैंक समूहों के मामले में कम हो गया (सारणी IV.29)।

4.73 एससीबी संबंधी सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल

सारणी IV.28: प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

(राशि करोड़ रुपए)

मद	जून 2008 के अंत में	जून 2009 के अंत में
1. अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	41,414	51,542
2. जारी प्रतिभूति रसीदें	10,658	12,801
3. निम्न द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें		
(क) बैंक	8,319	9,570
(ख) प्रतिभूतिकरण कंपनिया / पुनर्निर्माण कंपनियां	1,647	2,544
(ग) विदेशी संस्थागत निवेशक	–	–
(घ) अन्य (क्यूआइबी)	692	687
4. पूर्णतया मोचित प्रतिभूति रसीदों की राशि	1,299	2,792

– : शून्य / नगण्य।

स्रोत : एससी /आरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

सारणी IV.29 : अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (80)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (27)*	राष्ट्रीय कृत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (7)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (15)	निजी क्षेत्र के नए बैंक (7)	विदेशी बैंक (31)
1	2	3	4	5	6	7	8
एनपीए के लिए प्रावधान							
मार्च 2008 के अंत में	29.307	21.091	13,910	6,729	1,719	5,109	1,387
जोड़िए :वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	23.129	11.415	6,409	4,807	706	7,907	3,099
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए, अधिक्य के प्रति राइट बॅक	17.048	10.071	5,853	4,054	613	5,373	989
मार्च 2009 के अंत में	35.388	22.435	14,465	7,482	1,811	7,642	3,498
ज्ञापन :							
सकल अनर्जक आस्तिया	68.972	45.155	25,368	18,352	3,072	13,911	6,833
निम्न को सकल एसपीए के प्रति बकाया प्रावधान (प्रतिशत)							
मार्च 2008 के अंत में	52.0	52.1	59.4	43.5	67.2	48.9	48.5
मार्च 2009 के अंत में	51.3	49.7	57.0	40.8	59.0	54.9	51.2

*: आइडीबीआइ बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े मार्च 2009 के अंत के लिए उस समू में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात कम हो गया किंतु निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंकों के मामले में बढ़ गया। निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए) एससीबी के मामले में थोड़ा बढ़ गया (सारणी IV.30 और परिशिष्ट सारणी IV.27 और IV.28)।

सारणी IV.30: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक समूहवार सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियाँ

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक समूह / वर्ष	सकल अग्रिम राशि	सकल अनर्जक आस्तियां			निवल अग्रिम राशि	निवल अनर्जक आस्तियां		
		राशि	सकल अग्रिमों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत		राशि	सकल अग्रिमों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक								
2008	25,07,885	56,309	2.3	1.3	24,76,936	24,730	1.0	0.6
2009	30,38,254*	68,973	2.3	1.3	30,00,906	31,424	1.1	0.6
सरकारी क्षेत्र के बैंक								
2008	18,19,074	40,452	2.2	1.3	17,97,401	17,836	1.0	0.6
2009	22,83,473	45,156	2.0	1.2	22,60,156	21,033	0.9	0.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक								
2008	1,13,404	2,557	2.3	1.3	1,11,670	740	0.7	0.4
2009	1,30,352*	3,072	2.4	1.3	1,28,512	1,165	0.9	0.5
निजी क्षेत्र के नए बैंक								
2008	4,12,441	10,440	2.5	1.4	4,06,733	4,907	1.2	0.7
2009	4,54,713	13,911	3.1	1.8	4,46,824	6,253	1.4	0.8
विदेशी बैंक								
2008	1,62,966	2,859	1.8	0.8	1,61,133	1,247	0.8	0.3
2009	1,69,716	6,833	4.0	1.5	1,65,415	2, 973	1.8	0.7

* **:** 2009 के लिए तमिलनाड मर्केंटाइल बैक लि. के देशी आंकड़े (अलेखापरीक्षित) प्रयुक्त किए गए हैं।

स्रोत : कॉलम 2 की अप्रत्यक्ष विवरणियाँ और अन्य कॉलमों के लिए संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

सारणी IV.31: निवल अनर्जक आस्तियाँ-निवल अग्रिम अनुपात के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	मार्च के अंत में				
	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**28**	**28**	**28**	**28**	**27**
2 प्रतिशत तक	19	23	27	28	27
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	7	5	1	0	0
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	2	0	0	0	0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**20**	**20**	**17**	**15**	**15**
2 प्रतिशत तक	4	11	15	15	14
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	12	7	1	0	1
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	4	2	1	0	0
निजी क्षेत्र के नए बैंक	**9**	**8**	**8**	**8**	**7**
2 प्रतिशत तक	5	6	7	7	4
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	3	2	1	1	3
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	1	0	0	0	0
विदेशी बैंक	**31**	**29**	**29**	**28**	**31**
2 प्रतिशत तक	23	25	27	25	24
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	2	0	1	2	6
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	2	0	0	1	1
10 प्रतिशत से अधिक	4	4	1	0	0

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

4.74 सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक का निवल अग्रिम-निवल एनपीए अनुपात मार्च 2009 के अंत में 2 प्रतिशत से कम था। अन्य बैंक समूहों के मामले में इस अनुपात का वितरण भी विषम था जिसमें मात्र 10 बैंक ''2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत से कम'' की श्रेणी में थे और मात्र 1 बैंक ''5 प्रतिशत से अधकि और 10 प्रतिशत से कम'' की श्रेणी में था (सारणी IV.31)। मार्च 2005 के अंत के अनुपात के वितरण के एकदम विपरीत किसी भी बैंक का निवल अग्रिम-निवल एनपीए अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक नहीं था। इससे हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति में समग्र सुधार का पता चलता है (परिशिष्ट सारणी IV.27 और IV.28)।

4.75 यह महत्वपूर्ण है कि जहां ''संदिग्ध'' और ''हानि'' श्रेणी में एनपीए का हिस्सा कमोबेश स्थिर बना रहा, वहीं ''अवमानक'' श्रेणी के हिस्से में अंतर था। आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार, अवमानक आस्ति वह होती है जो 12 माह तक की अवधि के लिए एनपीए रहती है। इस प्रकार, अवमानक श्रेणी के हिस्से में उल्लिखित वृद्धि पिछले एक वर्ष में आस्तियों में ह्रास की द्योतक है (सारणी IV.32)।

सारणी IV.32: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक समूह	मानक आस्तियाँ		अवमानक आस्तियाँ		संदिग्ध आस्तियाँ		हानि आस्तियाँ		कुल सकल एनपीए		कुल सकल अग्रिम
	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्य बैंक											
2008	24,51,217	97.7	26,541	1.1	24,507	1.0	5,619	0.2	56,668	2.3	25,07,885
2009	29,61,524	97.7	37,030	1.2	26,998	0.9	6,035	0.2	70,063	2.3	30,31,587
सरकारी क्षेत्र के बैंक											
2008	17,78,476	97.8	17,290	1.0	19,291	1.1	4,018	0.2	40,598	2.2	18,19,074
2009	22,37,556	98.0	20,603	0.9	21,019	0.9	4,296	0.2	45,918	2.0	22,83,473
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2008	1,10,847	97.7	816	0.7	1,346	1.2	395	0.3	2,557	2.3	1,13,404
2009	1,20,733	97.6	1,295	1.1	1,267	1.0	390	0.3	2,952	2.4	1,23,685
निजी क्षेत्र के नए बैंक											
2008	4,02,013	97.5	6,473	1.6	3,106	0.8	849	0.2	10,428	2.5	4,12,441
2009	4,40,813	96.9	9,258	2.0	3,708	0.8	934	0.2	13,900	3.1	4,54,713
विदेशी बैंक											
2008	1,59,882	98.1	1,962	1.2	764	0.5	358	0.2	3,084	1.9	1,62,966
2009	1,62,422	95.7	5,874	3.5	1,004	0.6	416	0.3	7,294	4.3	1,69,716

* : सकल अग्रिमों का प्रतिशत।

टिप्पणी: 1. पूर्णांकित किए जाने के कारण घटक मदें कुल से भिन्न हो सकती हैं।

2. 2009 के आंकड़ों में तमिलनाड़ मर्केन्टाइल बैंक शामिल नहीं है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीएसबी विवरणियां (बीएसए)।

सारणी IV.33 : क्षेत्रवार-एनपीए - बैंक समूहवार*

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2007- 08	2008-09	2007-08	2008- 09	2007- 08	2008- 09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25,287	24,318	1,338	1,233	2,080	2,407	28,705	27,958
	(0.8)	(0.7)	(0.7)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.7)	(0.5)
i) कृषि	8,268	5,708	243	263	1,225	1,178	9,735	7,149
	(0.3)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)
ii) लघु उद्योग	5,805	6,984	359	307	292	363	6,456	7,654
	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	–	–	(0.2)	(0.2)
iii) अन्य	11,214	11,626	737	663	563	866	12,514	13,155
	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.3)
ख. सार्वजनिक क्षेत्र	299	474	–	–	–	75	299	549
	–	–	–	–	–	–	–	–
ग. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	14,163	19,251	1,219	1,839	8,339	11,334	23,721	32,423
	(0.5)	(0.5)	(0.6)	(0.8)	(1.1)	(1.4)	(0.6)	(0.6)
कुल (क +ख +ग)	**39,749**	**44,042**	**2,557**	**3,072**	**10,419**	**13,815**	**52,725**	**60,930**
	(1.3)	**(1.2)**	**(1.3)**	**(1.3)**	**(1.4)**	**(1.7)**	**(1.2)**	**(1.2)**

* : विदेशी बैंकों को छोड़कर।

– : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

4.76 जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आई, वहीं गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में 36.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में गिरावट में प्रमुख योगदान कृषि क्षेत्र का था जो केंद्र सरकार द्वारा 2007 में किसानों के लिए घोषित ऋण माफी योजना का आंशिक प्रभाव दर्शाती है। गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में तेज वृद्धि अर्थव्यवस्था में मंदी और कंपनियों की दबावयुक्त वित्तीय स्थिति दर्शाती है [सारणी IV.33, परिशिष्ट सारणी IV.29 (क) और 29 (ख); और परिशिष्ट सारणी 30 (क) और (ख)]। यह उल्लेखनीय है कि रिज़र्व बैंक ने अन्यथा व्यवहार्य आस्तियों के आर्थिक और उत्पादक मूल्य कर परिरक्षण के लिए असाधारण बाह्य कारकों को देखते हुए एक बारगी उपाय के रूप में और सीमित अवधि के लिए ऋण चुकौती के पुनर्निधारण पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में घटबढ़

4.77 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रावधान मार्च 2009 के अंत में 24.6 प्रतिशत बढ़े जबकि मार्च 2008 के अंत में उनमें 11.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी वर्ष के दौरान बट्टे खाते डालने और अतिरिक्त प्रावधानों के राइट-बॅक की तुलना में प्रावधानों का आधिक्य दर्शाती है। निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रावधानों में विदेशी बैंकों के मामले में ही गिरावट हुई जो वर्ष के दौरान अधिक राशि बट्टे खाते में डालना दर्शाती है (सारणी IV.34)

4.78 वित्तीय विवरणों का उद्देश्य किसी उद्यम की वित्तीय स्थिति, कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह की जानकारी उपलब्ध कराना है जो कि आर्थिक निर्णय लेने में विविध प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होती है। टिप्पणियों और वर्णनात्मक जानकारी के साथ कंपनियों के वित्तीय विवरणों का उद्देश्य यह होता है कि निवेशक नकदी प्रवाहों का अनुमान लगा सकें, निवेशित पूंजी पर उत्पन्न प्रतिलाभ निर्धारित कर सकें, व्यवसाय की चलनिधि का आकलन कर सकें और प्रबंधकीय कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कर सकें। वित्तीय विवरणों में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न संयोजनों के साथ माप के विविध उपाय अपनाए जाते हैं। इनमें ऐतिहासिक लागत, परिशोधित सीओएस और उचित मूल्य शामिल होते हैं। उचित मूल्य लेखांकन (एफवीए) सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) का 1990 के

सारणी IV.34: निवेश के मूल्य ह्रास पर प्रावधानों में बैंक समूहवार उतार -चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान							
मार्च 2008 के अंत में	10,408	7,800	5,862	1,359	347	909	1,353
जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7,467	6,067	3,540	2,235	211	1,123	66
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आधिक्य के प्रति राइट ऑफ किए गए	4,917	3,916	2,103	1,262	140	326	534
मार्च 2009 के अंत में	12,959	9,951	7,299	2,333	418	1,705	885

*: आइडीबीआइ बैंक लि. शामिल है।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

दशक के प्रारंभ से ही एक भाग रहने के बावजूद पिछले दशक से उचित मूल्य माप की लगातार वृद्धि हुई है जो कि प्राथमिक रूप से प्रासंगिक और समय पर वित्तीय विवरणों के लिए निवेशकों की मांग के प्रतिसाद में थी जो बेहतर सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायक होती है। हाल के वित्तीय संकट ने एफवीए के पक्ष-विपक्ष में गंभीर चर्चा आरंभ कर दी है जिसने एफवीए की मूल धारणा के प्रति भारी चुनौती खड़ी कर दी है (बॉक्स IV.2)।

पूंजी पर्याप्तता

4.79 सीआरएआर में सुधार इस बात का एक प्रमुख संकेतक है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है। एससीबी के तुलनपत्र मजबूत बने रहे जो इस क्षेत्र की आघात सहनीयता दर्शाते हैं। सभी एससीबी का समग्र सीआरएआर मार्च 2009 के अंत में सुधरकर 13.2 प्रतिशत हो गया जो एक वर्ष पूर्व के 13.0 प्रतिशत था और इस प्रकार यह 9.0 प्रतिशत न्यूनतम के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर बना रहा। सीआरएआर में हुई वृद्धि का प्रमुख कारण बैंकों की टियर II पूंजी की उच्च वृद्धि दर बनी रहना था (पिछले वर्ष के 28.9 प्रतिशत से 27.2 प्रतिशत), हालांकि टियर I पूंजी (पिछले वर्ष के 41.4 प्रतिशत से 17.0 प्रतिशत) और जोखिम भारित आस्तियों (पिछले वर्ष के 29.7 प्रतिशत से 18.4 प्रतिशत) दोनों की वृद्धि दर में गिरावट आई थी (सारणी IV.35)।

4.80 टियर I सीआरएआर 4.5 प्रतिशत की वर्तमान निर्धारित अपेक्षा और रिज़र्व बैंक द्वारा 27 अप्रैल 2007 को जारी बासेल II लागू करने के अंतिम दिशानिर्देशों में निर्धारित 6.0 प्रतिशत के मानदंड से भी अधिक बना रहा। जैसा कि चार्ट IV.19 से स्पष्ट है, एससीबी के टियर I सीआरएआर और टियर II सीआरएआर में घट-बढ़ एक-दूसरे की अनुपूरक रही है जिससे सीआरएआर को निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों से काफी ऊपर बनाए रखने में आसानी हुई। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, टियर I सीआरएआर में हुई थोड़ी गिरावट (पिछले वर्ष के 9.1 प्रतिशत से मार्च 2009 के अंत में 8.9 प्रतिशत) की तुलना में टियर II सीआरएआर में वृद्धि (3.9 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत) अधिक थी जिससे समग्र रूप से सीआरएआर में वृद्धि हुई और यह 13.0 प्रतिशत से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.15)।

4.81 2008-09 के दौरान, प्रमुख बैंक समूहों का सीआरएआर स्थिर रहा या उसमें सुधार हुआ जिसका अपवाद सरकारी क्षेत्र के बैंक थे जिनके मामले में थोड़ी गिरावट हुई थी। पीएसई के सीआरएआर में गिरावट मुख्यत: एसबीआइ समूह और उसके सहयोगियों के कारण आई थी। वस्तुत:, अकेले पीएसबी समूह का सीआरएआर ही औद्योगिक-औसत से नीचे था जबकि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों, निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में यह औद्योगिक-औसत से ऊपर था (सारणी IV.36)।

बॉक्स IV.2: उचित मूल्य लेखांकन - मुद्दे और परिप्रेक्ष्य

लेखांकन में, उचित मूल्य किसी आस्ति (या देयता) के बाजार मूल्य के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसके लिए बाजार मूल्य का प्राथमिक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि आस्ति के लिए कोई भी अनुमानित बाजार नहीं है। यूएस सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) (एफएएस 157) के तहत, आस्ति का उचित मूल्य वह राशि होती है जिस पर परिसमापनाधीन से भिन्न इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में आस्ति का क्रय या विक्रय किया जा सकता है। तुलनपत्र के दूसरे पक्ष में, किसी देयता का उचित मूल्य वह राशि होती है जिस पर परिसमापनाधीन से भिन्न इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में देयता ली या निपटाई जा सकती है। यदि उपलब्ध हो,तो किसी सक्रिय बाजार में निर्दिष्ट बाजार मूल्य उचित मूल्य की सर्वोत्तम साक्ष्य होती है और इसे माप के लिए आधार के रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिए। यदि निर्दिष्ट बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो उचित मूल्य के अनुमान में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करना चाहिए, हालांकि इससे विस्तार का घटक सामने आता है। उचित मूल्य लेखांकन (एफवीए) जीएएपी का 1990 के दशक के प्रारंभ से ही एक भाग रहने के बावजूद पिछले दशक से उचित मूल्य माप की लगातार वृद्धि हुई है जो कि प्राथमिक रूप से प्रासंगिक और समय पर वित्तीय विवरणों के लिए निवेशकों की मांग के प्रतिसाद में थी जो बेहतर सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायक होती है।

उचित मूल्य माप और संबंधित प्रकटीकरण में संगतता और तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए एफएएस 157 आस्तियों या देयताओं के लिए उचित मूल्य क्रम स्थापित करता है जो मूल्यांकन तकनीक में प्रयोग में लाई गई निविष्टि या धारणाओं की प्राथमिकता तय करता है। इस प्रकार, स्तर एक पर निर्दिष्ट मूल्यों के साथ चलनिधियुक्त आस्तियां, जैसे कि चलनिधियुक्त प्रतिभूति निविष्टि बनती है। दूसरे स्तर पर, मूल्यांकन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाजार दृष्टिगोचरों पर आधारित होता है। दृष्टिगोचर बाजार निविष्टि में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं: एक जैसी आस्तियों के लिए निर्दिष्ट मूल्य, ब्याज दर, आय वक्र, ऋण विस्तार, पूर्वचुकौती की गति, आदि। तीसरे स्तर में, मूल्यांकन संस्था के आंतरिक मूल्यांकन मॉडल जैसी गैर-दृष्टिगोचर धारणा पर आधारित होता है। यह पद्धति विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब बाह्य जानकारी प्राप्त करने की लागत और प्रयास बहुत अधिक हो।

मानक निर्धारकों ने उचित मूल्य लेखांकन पद्धतियों में विस्तार के लिए हाल के समय में अनेक उपाय किए हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों और विशेष रूप से जी 20 में की गई चर्चा के आधार पर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएएसबी) ने मई 2009 में उचित मूल्य माप पर संवेदनशील मानक के लिए एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रकाशित किया है।

उचित मूल्य लेखांकन की धारणा आर्थिक संकट के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आस्तियों के लिए बाजार दुर्बल हो जाते हैं और व्यापार भी तुलनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। ऐसे दौर में, ऐसे उत्पादों के लिए यदि कोई क्रेता हो तो वे बहुत कम होते हैं जिससे मार्किंग प्रक्रिया जटिल हो जाती है। हाल के वित्तीय संकट से उचित मूल्य लेखांकन (एफवीए) के पक्ष-विपक्ष पर गंभीर चर्चा प्रारंभ हुई। एक गहन विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि वित्तीय बाजारों में हुई उथल-पुथल का कारण एफवीए नहीं हो सकता। बल्कि, अधिकतर विवाद इस बात की स्पष्टता से उत्पन्न होते हैं कि एफवीए में नया या भिन्न क्या है। दूसरा, जहां वित्तीय संकट के समय में मार्किंग टू मार्केट (या शुद्ध एफवीए) संबंधी उचित चिंता है, वहीं यह अधिक स्पष्ट नहीं है कि ये एफवीए पर लागू होंगे या नहीं जैसा कि लेखांकन मानकों द्वारा निर्धारित है, फिर भले ही यह कार्य आइएफआरएस या यूएस जीएएपी द्वारा किया गया हो। तीसरा, ऐतिहासिक लागत लेखांकन उपाय नहीं हो सकती क्योंकि इसके संबंध में भी बहुत सी चिंताएं हैं और ये समस्याएं एफवीए संबंधी समस्याओं से अधिक हो सकती हैं। चौथा, माना कि एफवीए मानकों को दोष देना कठिन है फिर भी कार्यान्वयन के मामले, विशेष रूप से विवाद संबंधी, चिंता का विषय हैं।

लेखांकन नियम, जिनके लिए आस्तियां और देयताएं उचित मूल्य में धारित की जाती हैं, जटिल हैं। वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए आस्तियों की कुछ श्रेणियां डेरिवेटिव और लेनदेन योग्य इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे उचित मूल्य में करने की आवश्यकता है। ऋण प्राप्यता और ऋण प्रतिभूतियों जैसी अन्य प्रकार की आस्तियों के लिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आस्तियां व्यापार के लिए (सक्रिय क्रय और विक्रय) या दीर्घावधि/अवधिपूर्णता तक धारित हैं। बैंकों द्वारा एफवीओ का प्रयोग कुछ पर्यवेक्षणीय चिंताओं को बढ़ाता है। एक महत्वपूर्ण चिंता अचलनिधि युक्त वित्तीय लिखतों के लिए माप के रूप में उचित मूल्य बढ़ाने से संबंधित है जिसके लिए दृष्टिगोचर बाजार मूल्य नहीं है। बैंकों को उनकी अपनी धारणाएं प्रयोग करने की अनुमति देते समय ब्याज दर, चूक की दर, पूर्व-भुगतान की गति आदि जैसे बाजार के आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

अनेक चर्चाओं के बावजूद, एक सामान्य सहमति है कि बाजार में अचलनिधि की अस्थायी स्थिति को दूर करने के लिए उचित मूल्य लेखांकन की स्थिति विपरीत नहीं होनी चाहिए।

भारतीय लेखांकन मानक सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप ही हैं, हालांकि इनमें कुछ भिन्नता भी है। भारत में, हमने अब तक मार्किंग-टू-मार्केट की अपेक्षा को पूर्णत: नहीं अपनाया है जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों में उपलब्ध है। भारतीय मानक तुलनात्मक रूप से परंपरागत हैं और लाभ और हानि लेखे या इक्विटी में वसूल न हुए लाभ को मान्यता नहीं देना चाहते, यद्यपि वसूली न हो सकी हानियों को हिसाब में लेना अपेक्षित है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों में मार्क-टू-मार्केट निवेश आवधिक अंतराल पर, संविभागीय आधार पर किए जाएं और निवल हानि के लिए प्रावधान किए जाएं और निवल आय को नजरअंदाज किया जाए। यह स्थिरीकरण कारक के रूप में सिद्ध हो चुका है, जहां तक इससे प्रोत्साहन संरचना में असंतुलन न आया हो और साथ ही यह कम प्र-चक्रीय भी सिद्ध हो चुका है।

सारणी IV.35 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - घटकवार सीआरएआर
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद / मार्च अंत	2007	2008	2009
1	2	3	4
अ. पूंजीगत निधियां (i+ii)	**2,96,191**	**4,06,835**	**4,88,653**
i) टियर I पूंजी	2,00,386	2,83,339	3,31,513
जिसमें से :			
प्रदत्त पूंजी	29,462	41,178	46,339
आरक्षित निधियाँ	1,64,077	2,40,248	2,55,793
अनाबंटित / विप्रेषणीय अधिशेष	20,387	23,846	53,336
टियर I पूंजी के लिए कटौतियां	13,662	21,933	19,576
ii) टियर II पूंजी	95,794	1,23,496	1,57,141
जिसमें से : बट्टाकृत गौण ऋण	63,834	73,297	86,396
आ. जोखिम भारित आस्तियां	**24,12,236**	**31,28,093**	**37,05,166**
जिसमें से :			
जोखिम भारित ऋण और अग्रिम	17,17,810	21,66,234	25,67,787
इ. सीआरएआर (ख के प्रतिशत के रूप में क)	**12.3**	**13.0**	**13.2**
जिसमें से :			
टियर I	8.3	9.1	8.9
टियर II	4.0	3.9	4.2

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

4.82 भारत स्थित पांच सबसे बड़े एससीबी के बीच, आइसीआइसीआइ बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों के मामले

चार्ट IV.15: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर
(मार्च के अंत में)

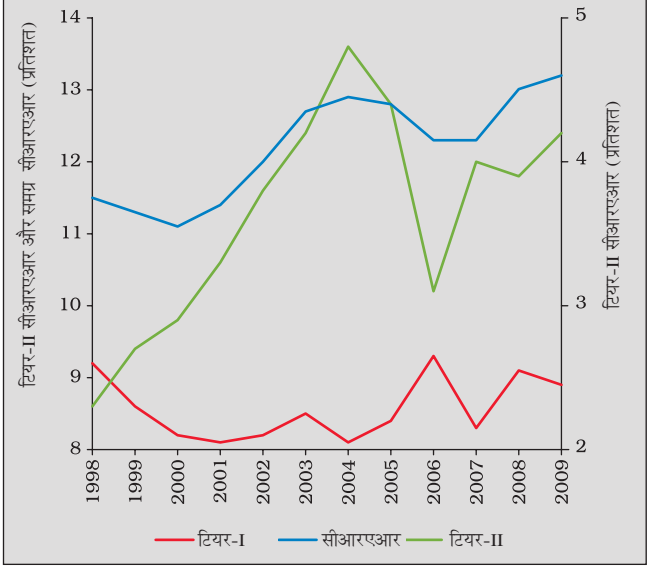

में 2008-09 के दौरान गिरावट देखी गई, हालांकि उनका सीआरएआर तब भी 9 प्रतिशत के विवेकसम्मत मानदंड से काफी ऊपर था। यह महत्वपूर्ण है कि इन बैंकों में से प्रत्येक के सीआरएआर में कुछ गिरावट आने के बावजूद उनकी टियर I पूंजी और साथ ही टियर II पूंजी में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। इस प्रकार, सीआरएआर में गिरावट वित्तीय बाजारों में विद्यमान उच्च अनिश्चितता के संदर्भ में इन बैंकों की आस्तियों को दिए गए उच्च जोखिम भारांकों को ही दर्शाती है और यह विनियामक चिंता की बात नहीं है (चार्ट IV.16)।

सारणी IV.36: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11.4	12.0	12.7	12.9	12.8	12.3	12.3	13.0	13.2
सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.2	11.8	12.6	13.2	12.9	12.2	12.4	12.5	12.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	10.2	10.9	12.2	13.1	13.2	12.3	12.4	12.1	12.1
एसबीआइ समूह	12.7	13.3	13.4	13.4	12.4	11.9	12.3	13.2	12.7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.9	12.5	12.8	13.7	12.5	11.7	12.1	14.1	14.3
निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.5	12.3	11.3	10.2	12.1	12.6	12.0	14.4	15.1
विदेशी बैंक	12.6	12.9	15.2	15.0	14.0	13.0	12.4	13.1	15.1

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

चार्ट IV.16: पांच सबसे बड़े बैंकों का सीआरएआर
(मार्च के अंत में)

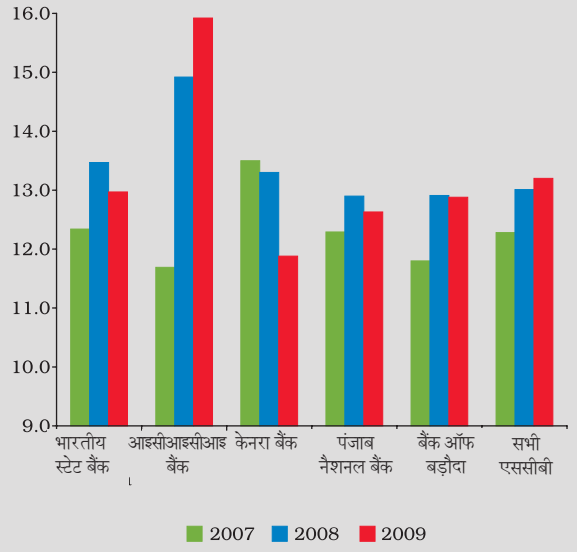

4.83 पहले उल्लेख किए अनुसार, सीआरएआर में सुधार इस बात का एक प्रमुख संकेतक है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है। वैयक्तिक बैंक स्तर पर, मार्च 2009 के अंत में सभी एससीबी का सीआरएआर 9 प्रतिशत की निर्धारित अपेक्षा से अधिक था। 78 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से ऊपर था और मात्र एक बैंक का 9 से 10 प्रतिशत के दायरे में था (सारणी IV.37)।

4.84 भारत स्थित एससीबी ने बासेल II संरचना में उपलब्ध सामान्य दृष्टिकोण अपनाया है। इससे बैंकों की विनियामक पूंजी उनकी आर्थिक पूंजी के अनुरूप होने में मदद मिलेगी और उससे उनकी पूंजीगत क्षमता में वृद्धि होगी (बॉक्स IV.3)।

6. पूंजी बाजार में बैंकों के परिचालन

बैंकों द्वारा प्राथमिक पूंजी बाजार से जुटाए गए संसाधन

4.85 2008-09 के दौरान एससीबी ने प्राथमिक बाजार से संसाधन नहीं जुटाए जबकि पिछले वर्ष उन्होंने 29,955 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसका मुख्य कारण भारतीय पूंजी बाजार के प्राथमिक घटक में चलनिधि का अभाव कहा जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश मांग को रोकना तथा गौण बाजार का मंद निष्पादन कहा जा सकता है। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त निधि भी वह महत्वपूर्ण कारण हो सकती है जिससे बैंकों ने प्राथमिक पूंजी बाजार से संसाधन नहीं जुटाए (सारणी IV.38)।

4.86 बैंकों ने निजी स्थानन बाजार में ऋण निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने को तरजीह दी जो 2008-09 के दौरान 34.6 प्रतिशत बढ़ा (सारणी IV.39)।

सारणी IV.37: सीआरएआर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2007-08			2008-09		
	9 प्रतिशत से कम	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	9 प्रतिशत से कम	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीयकृत बैंक*	–	–	20	–	1	19
स्टेट बैंक समूह	–	–	8	–	–	7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	–	1	14	–	–	15
निजी क्षेत्र के नए बैंक	–	–	8	–	–	7
विदेशी बैंक	–	1	27	–	–	30
कुल	**–**	**2**	**77**	**–**	**1**	**78**

– : शून्य / नगण्य।
* : आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड के आंकड़े शामिल हैं।
स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

बॉक्स IV.3: बासेल I और बासेल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता: भारतीय अनुभव

पारंपरिक रूप से, बैंक दिवालियेपन और चल आस्तियों-नकदी और प्रतिभूतियां-के संबंध में सुरक्षा के रूप में पूंजी रखते हैं ताकि जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओ के अनपेक्षित आहरणों के समय स्थिति अनुकूल बनी रहे (सेडनबर्ग और स्ट्राहन, 1999)। बैंकों के विनियमन का पारंपरिक दृष्टिकोण पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा की सकारात्मक विशेषताओं पर बल देता है (दिवात्रीपॉट और तिरोले, 1994)। दूसरी ओर, यह तर्क दिया जाता है कि पूंजी अपेक्षाओं से जोखिम उठाने का व्यवहार बढ़ सकता है। यदि इक्विटी पूंजी जमाराशि से अधिक महंगी है तो जोखिम-आधारित पूंजी अपेक्षाओं में वृद्धि की जांच करके उधार देने की बैंकों की इच्छा कम हो सकती है (ठाकोर,1996)। यह भी पाया गया है कि पूंजी अपेक्षाएं बढ़ाने से बैंकों पर कम जमाराशि की आपूर्ति का दबाव आता है जिससे बैंकों की चलनिधि उपलब्ध कराने की भूमिका घटती है। इस पक्ष-विपक्ष को देखते हुए, अब यह तर्क दिया जाता है कि पूंजी, जिसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जोखिम प्रोफाइल और परिचालन माहौल से संगत होनी चाहिए। बासेल II ढांचा इस दिशा में एक कदम है क्योंकि इन मानदंडों का उद्देश्य न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को बैंकों की निहित जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप लाना है।

बासेल I ढांचा बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तक सीमित था और मुख्यत: ऋण जोखिम पर केंद्रित था। दूसरी ओर, बासेल II ढांचा इस दृष्टिकोण को बढ़ाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी अपेक्षा का व्यापक रूप से नई, जोखिम-पर्याप्तता गणना शामिल है जिसमें (पहली बार) स्पष्ट रूप से बाजार और ऋण जोखिम के अलावा परिचालनात्मक जोखिम भी शामिल है। जहां बासेल I में उधारदाता से यह अपेक्षित था कि वे प्रत्येक आस्ति श्रेणियों की सीमित संख्या के लिए एकल जोखिम भार के आधार पर पूंजी के न्यूनतम स्तर की गणना करें, वहीं बासेल II के तहत पूंजी अपेक्षाएं अधिक जोखिम-संवेदनशील हैं। बासेल II पूंजी पर्याप्तता नियम 'मेनू' दृष्टिकोण पर आधारित है जो बैंकों के स्वरूप और बाजारों के स्वरूप, जिनमें वे कार्य करते हैं, के संबंध में दृष्टिकोणों में अंतर की अनुमति देता है। इस प्रकार, बासेल II के निर्धारण पूंजी पर्याप्तता से पूंजी दक्षता में अंतरित हुए हैं जिसका अर्थ यह है कि बैंक पूंजी के उपयोग में अधिक सक्रिय रुख अपनाते हैं जिसमें पूंजी अपने अधिकतम दक्ष उपयोग में तुरंत प्रवाहित हो जाएगी। बासेल II केये घटक विनियामक ढांचे को अनेक बड़े बैंकों में अपनाए गए व्यवसाय मॉडलों के करीब ले जाते हैं।

भारत स्थित सभी एससीबी ने मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार संशोधित ढांचे के तहत अपनी पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी-जोखिम भारांकित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखें। रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक के संबंधित जोखिम कारक और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन हिसाब में लेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा धारित पूंजी उसकी समग्र जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है। इसमें अन्य के साथ ही बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, संकेद्रन जोखिम और अवशिष्ट जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन/माप, निगरानी और प्रबंधन में बैंक की जोखिम प्रबंधन का कौशल शामिल होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक की संबंधित जोखिम प्रोफाइल और उनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर पिलर 2 ढांचे के तहत प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी अनुपात का उच्चतर स्तर निर्धारित करने पर विचार करेगा। इसके अलावा, नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे की पिलर 2 अपेक्षाओं के संदर्भ में बैंकों से अपेक्षित है कि वे न्यूनतम अपेक्षाओं से उचित ऊंचाई के स्तर पर परिचालन करें।

इसके अलावा, संशोधित ढांचा लागू करने पर बैंकों द्वारा बनाए रखी गई न्यूनतम पूंजी विवेकसम्मत स्तर की शर्त पर होगी जो निम्नलिखित राशि से अधिक होगी: क) संशोधित ढांचे के अनुसार बनाए रखने हेतु अपेक्षित न्यूनतम पूंजी; ख) ऋण और बाजार जोखिमों के लिए बासेल I के अनुसार बनाए रखने हेतु अपेक्षित न्यूनतम पूंजी का विनिर्दिष्ट प्रतिशत। यह विनिर्दिष्ट प्रतिशत सारणी 1 में दर्शाए अनुसार क्रमिक रूप से कम होता जाएगा।

सारणी 1: विवेकसम्मत स्तर

को समाप्त वित्तीय वर्ष*	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011
विवेकसम्मत स्तर (ऋण और बाजार जोखिमों के लिए चालू (बासेल I) ढांचे के अनुसार गणना की गई न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के % के रूप में)	100	90	80

*: 31 मार्च 2009 से संशोधित ढांचे को लागू करने वाले बैंकों के लिए संगत अवधि मार्च 2009, मार्च 2010 और मार्च 2011 होगी।

बासेल I और बासेल II पर आधारित बैंक वार सीआरएआर के आंकड़े उपलब्ध हैं और परिशिष्ट IV.31 में दिए गए हैं। 80 बैंकों में से बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया और सोनाली बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों ने बासेल II के अंतर्गत सीआरएआर की सूचना दी है और 14 बैंकों ने बासेल II के अंतर्गत सीआरएआर की सूचना नहीं दी। बासेल I और बासेल II दोनों के अंतर्गत सीआरएआर की सूचना देने वाले 64 बैंकों के आंकड़ों पर आधारित बारंबारता संवितरण से पता चलता है कि सीआरएआर का मानक दायरा 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है (सारणी 2)।

बैंक समूहवार विश्लेषण से पता चलता है कि 2008-09 के लिए भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के संबंध में बासेल II के तहत सीआरएआर बासेल I की तुलना में अधिक था। अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में भी यही प्रवृत्ति देखी गई। दूसरी ओर, विदेशी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने बासेल II की तुलना में बासेल I के तहत अधिक सीआरएआर की सूचना दी। किंतु, निजी क्षेत्र के बैंकों ने मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाई (परिशिष्ट IV.31)।

सारणी 2: बैंकों का सीआरएआर पर आधारित वितरण

सीआरएआर (%)	31 मार्च 2009 को बैंकों की संख्या					
	बासेल I			बासेल II		
	भारतीय	विदेशी	कुल	भारतीय	विदेशी	कुल
9-12	12	0	12	6	0	6
12-15 (मॉडल रेंज)	**26**	**4**	**30**	**29**	**4**	**33**
15-18	2	2	4	5	4	9
18-21	2	2	4	2	0	2
21-24	1	0	1	1	1	2
24-27	0	0	0	0	3	3
27-30	0	2	2	0	0	0
30-33	0	2	2	0	0	0
33 और अधिक	1	8	9	1	8	9
कुल	**44**	**20**	**64**	**44**	**20**	**64**

संदर्भ:

दिवात्रीपॉन्ट, एम. एंड जे.तिरोले, 1994.दि प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। कैम्ब्रिज: एमएएमआइटी प्रेस, एलिजाल्दे,ए.और आर.रेपुलो,2006. ''इकॉनोमिक एंड रेगुलेटरी कैपिटल इन बैंकिंग: वाट इज द डिफरेंस?''। सीईपीआर डिसकसन पेपर, 4770.

सेडनबर्ग, एम. और पी.स्ट्राहन. 1999. ''आर बैंक्स इंपॉर्टंट फॉर फाइनान्सिंग लार्ज बिजनेसेस?'' करंट इश्यूज इन इकॉनोमिक्स एंड फाइनान्स, 5(12)।

ठाकोर, ए.1996.''कैपिटल रिक्वायरमेंट, मॉनिटरी पॉलिसी एंड एग्रिगेट बैंक लेंडिंग: थ्योरी एंड एविडेंस''। जर्नल ऑफ फाइनान्स, 51:279-324.

सारणी IV.38: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		**सकल जोड़**
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
2004-05	3,336	–	4,108	1,478	7,444	1,478	8,922
2005-06	5,413	–	5,654	–	11,067	–	11,067
2006-07	7,82	–	284	–	1,066	–	1,066
2007-08	17,552	–	12,403	500	29,955	500	30,455
2008-09	–	–	–	–	–	–	–

– : कुछ नहीं / नगण्य।

सारणी IV.39: बैंकों द्वारा निजी स्थानन के जरिए जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए)

श्रेणी	2007-08		2008-09	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	10	2,090	13	6,967
सरकारी क्षेत्र के बैंक	58	24,109	52	28,304
कुल	**68**	**26,199**	**65**	**35,271**

स्रोत : मर्चेंट बैंकर्स और वित्तीय संस्थाएं।

गौण बाजार में बैंकिंग शेयरों का कार्य-निष्पादन

4.87 भारत में देशी शेयर बाजार, जिसमें 2003-04 से तेजी की स्थिति थी, में वैश्विक वित्तीय संकट के चलते 2008-09 के दौरान भारी हानि देखी गई। बीएसई सेंसेक्स में 2008-09 के दौरान 37.9 प्रतिशत की गिरावट हुई। बीएसई बैंकेक्स में 2008-09 के दौरान 41.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जो कि बीएसई सेंसेक्स की तुलना में अधिक थी।

4.88 2008-09 के दौरान बीएसई बैंकेक्स में घट-बढ़ (घट-बढ़ के सहगुणांक द्वारा मापे अनुसार) (23.8 प्रतिशत) बीएसई सेंसेक्स (24.2 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ी ही कम थी (सारणी IV.40)।

4.89 2009-10 में अब तक, बीएसई बैंकेक्स ने बीएसई सेन्सेक्स की तुलना में तेज सुधार दर्शाया, हालांकि बीएसई सेन्सेक्स की तुलना में उसमें घट-बढ़ भी अधिक हुई थी।

4.90 समग्र प्रवृत्ति के अनुरूप, बीएसई में सूचीबद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर अन्य सभी बैंकों के शेयरों में वर्ष के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति रही। मूल्यों में गिरावट की यह प्रवृत्ति बैंक शेयरों के मूल्य अर्जन (पी/ई)अनुपातों में भी दिखी। यह उल्लेखनीय है कि औसतन निजी क्षेत्र के बैंकों के पी/ई अनुपातों में गिरावट सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक थी। इसका आंशिक कारण यह तथ्य था कि निजी क्षेत्र के बैंकों, जिनका मूल्यांकन 2007-08 के दौरान अधिक था, ने 2008-09 के दौरान

सारणी IV.40: बैंक स्टॉक का कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ

सूचकांक	प्रतिलाभ*			अस्थिरता@		
	2007-08	2008-09	2009-10#	2007-08	2008-09	2009-10#
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई बैंकेक्स	18.0	-41.8	119.5	13.8	23.8	15.6
बीएसई सेसेंक्स	19.7	-37.9	76.4	12.0	24.2	12.5

* : अंक-दर-अंक आधार पर सूचकांकों में प्रतिशत अंतर।
@ : अंतर के सहगुणांक के रूप में परिभाषित।
# : सितंबर 2009 के अंत तक।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

सारणी IV.41: बैंक स्टाक का संबंधित अंश - टर्नओवर तथा बाजार पूंजीकरण

(प्रतिशत)

वर्ष	कुल टर्नओवर में बैंक स्टाक के टर्नओवर का अंश	कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टाक के पूंजीकरण का अंश*
1	2	3
2005-06	6.8	7.1
2006-07	5.3	6.8
2007-08	6.6	7.2
2008-09	12.3	7.7

* : अवधि के अंत में।

टिप्पणी: बैंकों के टर्नओवर और बाजार पूंजीकरण के आंकड़े एनएसइ के बैंक निफ्टी सूचकांक से संबंधित हैं।

स्रोत: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में शेयर मूल्यों में अधिक गिरावट देखी (परिशिष्ट सारणी IV.32)।

4.91 बैंक के शेयर भारतीय इक्विटी बाजार के बाजार पूंजीकरण के लगातार 7 प्रतिशत भाग बने रहे। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, एनएसई के कुल पण्यावर्त में बैंकिंग शेयरों का हिस्सा 2008-09 के दौरान लगभग दुगुना हो गया (सारणी IV.41)।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारिता का स्वरूप

4.92 घोषित नीति के अनुरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी शेयर धारिता 51 प्रतिशत के स्तर से अधिक बनी रही। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निजी शेयर धारिता का स्वरूप, जिसमें निवासी और अनिवासी वित्तीय संस्थाओं, निवासी और अनिवासी कंपनियों

सारणी IV.42: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयरधारिता*

(मार्च के अंत में)

श्रेणी	2008	2009
1	2	3
10 प्रतिशत तक	2	2
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	2	2
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	3	2
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	3	4
40 से ऊपर तथा 49 प्रतिशत तक	11	11

– : शून्य/ नगण्य

* : 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआइ लि. को मिलाकर।

तथा निवासी और अनिवासी व्यक्तियों की शेयर धारिता शामिल होती हैं, यूको बैंक को छोड़कर अन्य के संबंध में पिछले वर्ष जैसा ही बना रहा। पूंजी पुनर्निर्धारण की सरकारी पहलों के कारण यूको बैंक में सरकार की शेयर धारिता कम होकर 63.6 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 75.0 प्रतिशत थी (सारणी IV.42 और परिशिष्ट सारणी IV.33)।

4.93 भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, में विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफआइआइ) की शेयर धारिता की प्रवृत्ति मिश्रित स्वरूप की थी। वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में एफआइआइ की शेयर धारिता में गिरावट सामान्य रूप से शेयर बाजार में और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में मंद स्थिति और संविभागीय प्रवाहों के निवल बहिर्वाह दर्शाती है (सारणी IV.43)।

सारणी IV.43: भारतीय बैंकों में विदेशी वित्तीय संस्थाओं (अनिवासी) की शेयरधारिता

(मार्च के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

श्रेणी	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
कुछ नहीं	12	11	2	2	7	7
10 प्रतिशत तक	3	8	–	–	–	–
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	13	8	1	1	2	2
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	–	–	2	1	3	3
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	–	–	1	2	1	3
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	–	–	1	–	1	–
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	–	–	–	–	1	–
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	–	–	1	1	–	–
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	–	–	–	–	–	–
कुल	**28**	**27**	**8**	**7**	**15**	**15**

7. बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

4.94 व्यापक होती जा रही बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रिज़र्व बैंक ने काफी समय से ध्यान केंद्रित किया है। भारत स्थित बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का उपयोग न केवल अपने आंतरिक कार्यों में सुधार लाने के लिए, बल्कि ग्राहक सुविधाएं और सेवाएं बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से बैंकों के व्यापक ग्राहक आधार ने लेनदेनों की बढ़ी हुई मात्रा का सटीक और समय पर प्रबंध करना आसान कर दिया है। इसका एक गोचर परिणाम यह है कि बैंक अब विशेष रूप से बनाए गए, सरल, सुरक्षित और फिर भी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रस्तुत करके बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन का कार्य शुरू करके देश की अब तक बैंकिंग से वंचित रही जनसंख्या को सेवा देने का लक्ष्य बना रहे हैं।

4.95 वर्ष के दौरान, समाशोधन आंकड़ों का प्रसारण - चेक समाशोधन और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा दोनों के लिए, समन्वित मुद्रा तिजोरी परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) के एक भाग के रूप में निविष्टियों का मिलान करने के लिए सिक्योर्ड वेबसाइट का उपयोग किया गया। लेखांकन अपेक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की अपेक्षाओं की प्रोसेस की वर्तमान आइटी प्रणाली को केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस) से प्रतिस्थापित किया गया जो पहले वाली प्रणाली से अधिक मजबूत और यूजर फ्रेंडली है।

4.96 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्राथमिक दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में नीलामी प्रक्रिया को सुगम और तेज बनाने के लिए भारिबैं की ओर से भारतीय समाशोधन निगम द्वारा विकसित और उनके पास रखा गया तयशुदा लेनदेन प्रणाली नीलामी माड्यूल का नया रूप 11 मई 2009 को शुरू किया गया। नीलामी के इस नए मंच ने भारिबैं में रखे गए पीडीओ एनडीएस अप्लिकेशन के तहत उपलब्ध नीलामी मंच का स्थान लिया।

4.97 भारत में बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्राधिकारी अर्थात आइडीआरबीटी ने 1,20,000 डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जिससे बैंक आरटीजीएस, सीएफएमएस, कारपोरेट ई-मेल, एसएफएमएस, इंटरनेट बैंकिंग वेब सर्वर, ओएलटीएएस और सीसीआइएल सेटलमेंट अप्लिकेशन आदि को परिचालित करते हुए सुरक्षित माहौल में कार्य कर सकें। 133 पंजीयन प्राधिकारी (आरओ) हैं जो सरकारी क्षेत्र के 33 बैंकों, निजी क्षेत्र के 31 बैंकों और 5 वित्तीय संस्थाओं को कवर करते हैं जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के लिए निर्मित 16 पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय शामिल हैं। आइडीआरबीटी उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय के रूप में कार्य करता है जिनके पास आरए संरचना नहीं है।

4.98 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मिली एक मुख्य सफलता यह थी कि कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) उपलब्ध कराने वाली शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई। सीबीएस लागू करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 31 मार्च 2008 के 35,464 से बढ़कर 31 मार्च 2009 को 44,304 हो गई। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया, जो सभी प्रौद्योगिकीय पहलों का आरंभ है, पूरी होने के निकट है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कंप्यूटरीकरण तथा संचार नेटवर्क के विकास पर बड़े पैमाने पर धन खर्च करना जारी रखा। वस्तुत:, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटरीकरण पर व्यय की गई राशि की वृद्धि दर 2007-08 में कुछ कम हो गई थी जो कि 2008-09 के दौरान तेजी से बढ़ गई। सितंबर 1999 से मार्च 2009 के बीच व्यय की गई कुल राशि 18,168 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि थी (परिशिष्ट सारणी IV.34)। पिछले वर्ष देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, कुल शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराने वाली शाखाओं की संख्या 2008-09 के दौरान तेजी से बढ़ी (सारणी IV.44)।

4.99 पूरी तरह कंप्यूटरीकरण करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का अनुपात मार्च 2008 के अंत के 93.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 95.0 प्रतिशत हो गया। बैंकों द्वारा उच्च लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास जारी हैं और बहुत से बैंक '90 प्रतिशत से अधिक किंतु 100 प्रतिशत से कम' की श्रेणी में पहुंच गए हैं (परिशिष्ट सारणी IV.35)।

सारणी IV.44: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण
(मार्च के अंत में)

(कुल बैंक शाखाओं का प्रतिशत)

श्रेणी	2008	2009
1	2	3
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं (i+ii)	93.7	95.0
i) कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाएं	67.0	79.4
ii) पहले से ही पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं#	26.6	15.6
अंशतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं	6.3	5.0

: कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाओं से भिन्न।

4.100 2008-09 के दौरान, बैंकों द्वारा स्थापित कुल एटीएम में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें एसबीआइ समूह के एटीएम की संख्या में 34.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई थी। जहां निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की संख्या उनकी शाखाओं की संख्या से 3 गुना से भी अधिक थी वहीं अन्य बैंक समूहों का एटीएम-शाखा अनुपात काफी कम था (सारणी IV.45,परिशिष्ट सारणी IV.36)।

4.101 मार्च 2009 के अंत तक देश में स्थापित सभी एटीएम में से निजी क्षेत्र के नए बैंकों के ऑफ-साइट एटीएम की संख्या सबसे अधिक थी जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऑन-साइट एटीएम की संख्या सबसे अधिक थी (चार्ट IV.17)।

चार्ट IV.17: एटीएम - बैंक समूहवार अंश
(मार्च 2009 के अंत में)

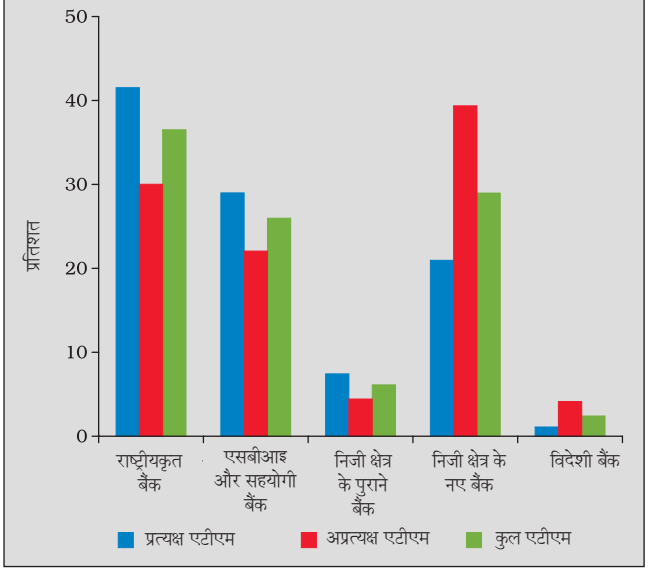

4.102 हाल के वर्षों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के प्रयोग में कई गुना इजाफा हुआ है जो आंशिक रूप से यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी अपनाने में वृद्धि हुई है। किंतु, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से किए गए लेनदेनों की संख्या 2007-08 के 41.4 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 में 24.8 प्रतिशत रह गई (सारणी IV.46)। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से किए गए लेनदेनों के मूल्य में 2008-09 के दौरान तेज गिरावट हुई जो आंशिक रूप से यह दर्शाती है कि आर्थिक गतिविधियों में मंदी की स्थिति थी। इस पूरी गिरावट का कारण ईसीएस क्रेडिट संबंधी लेनदेन के मूल्य में 87.5 प्रतिशत गिरावट आना

सारणी IV.45: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम
(मार्च 2009 के अंत में)

बैंक समूह	बैंक /शाखाओं की संख्या					एटीएम की संख्या			कुल एटीएम के प्रतिशत के रूप में परोक्ष एटीएम	शाखाओं के प्रतिशत रूप में एटीएम
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	प्रत्यक्ष	परोक्ष	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i) राष्ट्रीयकृत बैंक	13,381	8,669	8,951	8,375	**39,376**	10,233	5,705	**15,938**	35.8	**40.2**
ii) स्टेट बैंक समूह	5,560	4,835	3,043	2,624	**16,062**	7,146	4,193	**11,339**	37.0	**29.0**
iii) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	842	1,554	1,344	933	**4,673**	1,830	844	**2,674**	31.6	**56.9**
iv) निजी क्षेत्र के नए बैंक	271	1,084	1,371	1,478	**4,204**	5,166	7,480	**12,646**	59.2	**296.6**
v) विदेशी बैंक	4	4	52	233	**293**	270	784	**1,054**	74.4	**357.3**
जोड़ (i से v)	**20,058**	**16,146**	**14,761**	**13,643**	**64,608**	**24,645**	**19,006**	**43,651**	**43.5**	**67.0**

सारणी IV.46: फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेनदेन

प्रकार	लेनदेनों की संख्या (000'में)			लेनदेनों में वृद्धि (प्रतिशत)		लेनदेनों का मूल्य (रुपए करोड में)			मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत)	
	2006-07	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ईसीएस जमा	69,019	78,365	88,394	13.5	12.8	83,273	7,82,222	97,487	839.3	-87.5
2. ईसीएस नामे	75,202	1,27,120	1,60,055	69.0	25.9	25,441	48,937	66,976	92.3	36.9
3. ईएफटी/ एनइएफटी	4,776	13,315	32,161	178.8	141.5	77,446	1,40,326	2,51,956	81.2	79.6
4. क्रेडिट कार्ड	1,69,536	2,28,203	2,59,561	34.6	13.7	41,361	57,984	65,356	40.2	12.7
5. डेबिट कार्ड	60,177	88,306	1,27,654	46.7	44.6	8,172	12,521	18,547	53.2	48.1
कुल	**3,78,710**	**5,35,309**	**6,67,825**	**41.4**	**24.8**	**2,35,693**	**10,41,990**	**5,00,322**	**342.1**	**-52.0**

था। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि 2007-08 के दौरान ईसीएस क्रेडिट के मूल्य में तेज वृद्धि का मुख्य कारण स्टॉक एक्सचेंजों की अनिवार्यता के अनुसार कंपनियों द्वारा उनके आइपीओ के अभिदान की अतिरिक्त राशि लौटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना था। अत:, 2008-09 के दौरान ईसीएस क्रेडिट के मूल्य में गिरावट को चिंता के विषय के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य प्रवृत्ति की वापसी के रूप में देखा जा सकता है।

4.103 2008-09 के दौरान ईसीएस क्रेडिट और विशेष रूप से ईसीएस डेबिट पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के अनुरूप लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते रहे [चार्ट IV.18(क)और IV.18(ख)]।

4.104 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) सरकारी प्रतिभूति समाशोधन तथा विदेशी मुद्रा समाशोधन शामिल हैं। आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 में इसे प्रचलन में लाए जाने के बाद से ही निर्बाध रूप से काम कर रही है। अगस्त 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, 107 सहभागी (96 बैंक, 8 प्राथमिक व्यापारी, रिज़र्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा भारतीय समाशोधन निगम लि.) आरटीजीएस प्रणाली के सदस्य हैं। आरटीजीएस की पहुंच तथा उसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। बैंक / शाखा नेटवर्क कवरेज 10,000 से अधिक केंद्रों में बढ़कर 58,720 शाखाओं का हो गया है जिससे निधि अंतरण के इस माध्यम का प्रयोग बढ़ गया है। अगस्त 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, लगभग 1,200 बिलियन रुपए के लिए लेनदेनों का दैनिक औसत मूल्य 90,000 था जिसमें से लगभग 980 बिलियन रुपए के 82,000 लेनदेन ग्राहक लेनदेन से संबंधित थे (चार्ट IV.19)।

चार्ट IV.18: इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन

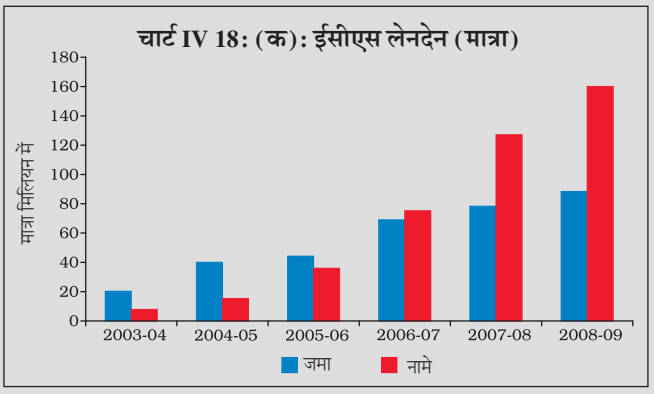

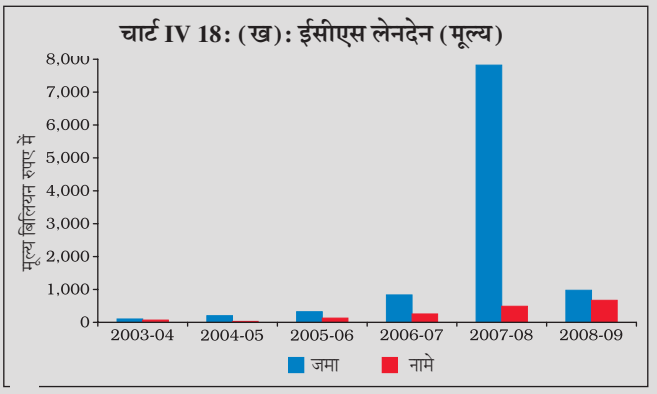

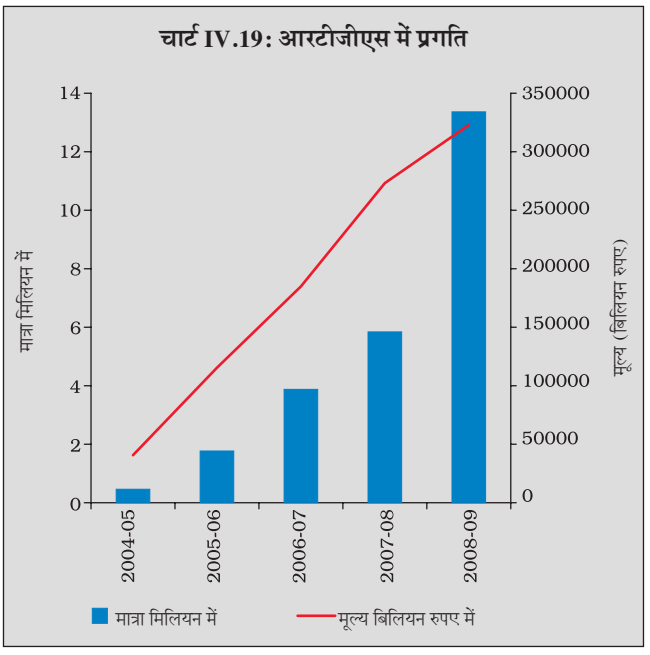

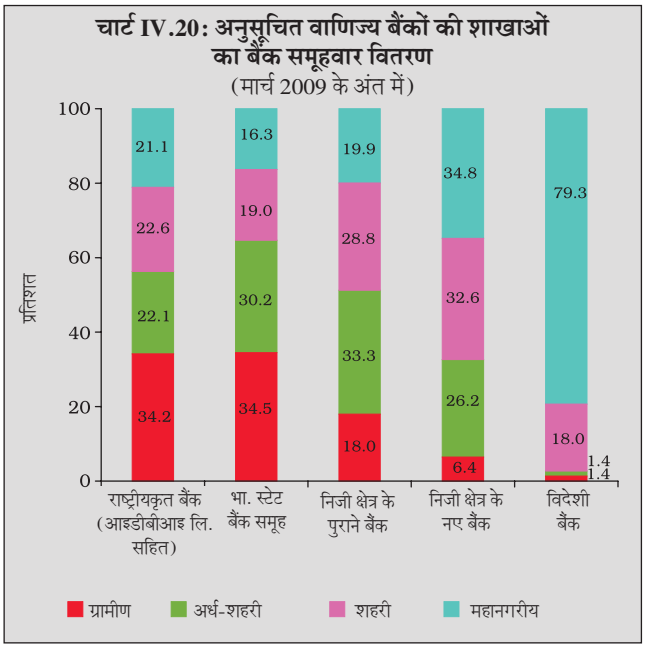

8. बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार

4.105 उचित मूल्ययुक्त और सुविधाजनक स्थल पर स्थित वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं किसी भी देश की वित्तीय समावेशन की पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैंकिंग का एकसमान क्षेत्रीय विस्तार भारत जैसे विशाल देश में इसकी क्षेत्रीय विविधता की विशेषता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बैंकिंग के क्षेत्रीय विस्तार पर ठोस आंकड़े प्राप्त होने की दृष्टि से आधारभूत सांख्यिकी विवरणी को विशेष रूप से बनाया गया है और वर्षों में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। यह डेटासेट देशभर के बैंकिंग परिचालनों की समग्र जानकारी उपलब्ध कराता है और इसलिए यह नीति निमार्ण की दृष्टि से मूल्यवान और आवश्यक डेटासेट है।

4.106 एससीबी की शाखाओं की कुल संख्या मार्च 2009 के अंत में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी। समग्र संदर्भ में, बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्र में थी जो मुख्यत: रिजर्व बैंक का नीतिगत बल दर्शाती है। किंतु, दूसरी ओर, कुल में ग्रामीण शाखाओं के हिस्से में हाल के वर्षों में गिरावट हुई है जबकि शहरी और महानगरीय शाखाओं का हिस्सा बढ़ रहा है। सारणी IV.52 में दर्शाए अनुसार, बैंकों के लिए व्यवसाय का मुख्य भाग शीर्ष के सौ केंद्रों द्वारा अर्जित किया गया जो मुख्यत: शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में थे। एसबीआइ समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में था। किंतु, विदेशी बैंकों की शाखाएं मुख्यत: शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में संकेंद्रित थीं और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति नगण्य थी (चार्ट IV.20 और परिशिष्ट सारणी IV.36)।

4.107 शीर्षस्थ सौ केंद्रों में कार्यालयों की कुल संख्या का लगभग एक चौथाई भाग था किंतु कुल जमाराशि का 70 प्रतिशत और कुल ऋण का 78.5 प्रतिशत उनके पास था। इससे यह बात पता चलती है कि जमाराशि जुटाने तथा ऋण के आबंटन में शीर्षस्थ सौ केंद्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है (सारणी IV.47)।

सारणी IV.47: कुल जमाराशियों तथा समग्र बैंक ऋण में शीर्ष के सौ केंद्रों का हिस्सा

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	जमाराशियां		ऋण	
	कार्यालय	राशि	कार्यालय	राशि
1	2	3	4	5
2008	25.7	69.7	25.6	77.8
2009	26.2	69.2	26.2	78.5

स्रोत: मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-7।

चार्ट IV.21: बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण

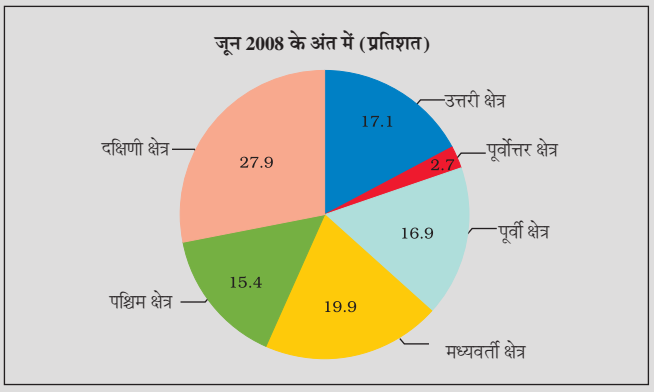

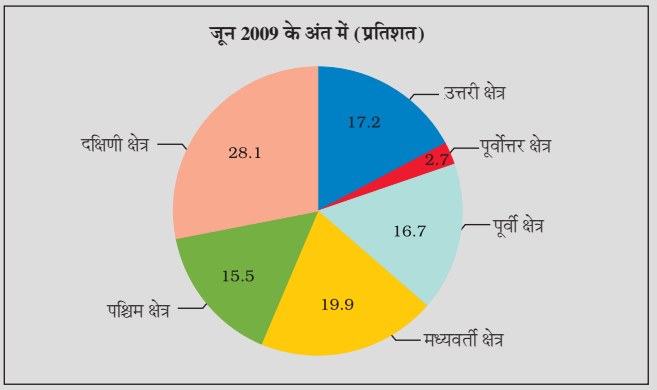

4.108 बैंक शाखाओं की संख्या की विस्तार दर 2007-08 के दौरान के 5.2 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 के दौरान 4.5 प्रतिशत रह गई। एक बैंक शाखा द्वारा सेवा प्राप्त करने वाली औसत आबादी जून 2008 के अंत की तुलना में जून 2009 के अंत में भी 15,000 पर अपरिवर्तित बनी रही (परिशिष्ट सारणी IV.37)। जारी प्रवृत्ति के अनुक्रम में, 2008-09 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा बैंक शाखाओं का सर्वाधिक प्रतिशत बना रहा जिसके बाद मध्य, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का स्थान था। 2008-09 के दौरान दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, वहीं पूर्वी क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई (चार्ट IV.21, परिशिष्ट सारणी IV.38)। जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान नई शाखाएं खोलने में दक्षिणी क्षेत्र (वृद्धिशील शाखाओं का 30.7 प्रतिशत) तथा मध्य क्षेत्र (वृद्धिशील शाखाओं का 19.8 प्रतिशत) सबसे आगे थे।।

4.109 क्षेत्रवार ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात क्षेत्र के विकास में क्षेत्रीय स्तर पर बैंकों की भूमिका के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन के आकलन को दर्शाने वाला संकेतक है। ''ऋण-जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल'' (अध्यक्ष: श्री वाइ.एस.पी.थोरात) (नवंबर 2004) ने सुझाव दिया था कि चूंकि ऋण-जमा अनुपात ने राज्यों के विकास में बैंकिंग प्रणाली के योगदान के वास्तविक प्रयासों को दर्शाना चाहिए, अत: बैंकों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य स्तरीय उद्यमों के बांडों में किए गए निवेश को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। इस सिफारिश के अनुसरण में, सी-डी अनुपात के अलावा, निवेश प्लस ऋण-जमा अनुपात को भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा, चूंकि आरआइडीएफ बैंकों द्वारा राज्यों को दी गई संसाधन सहायता का प्रतिनिधित्व करता है, अत: यह महसूस किया गया कि निवेश प्लस ऋण प्लस आरआइडीएफ जमा अनुपात बैंकों के कार्य निष्पादन की बेहतर स्थिति प्रस्तुत करेगा [9]। इसके मद्देनजर, निवेश प्लस ऋण प्लस आरआइडीएफ जमा अनुपात के क्षेत्रवार आंकड़ों का संकलन और प्रसारण किया जा रहा है (परिशिष्ट IV.39)।

4.110 2007-08 के दौरान देखी गई प्रवृत्ति जारी रखते हुए, अखिल - भारतीय सी-डी अनुपात मार्च 2009 के अंत में और कम होकर 72.6 प्रतिशत रह गया। सी-डी अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के साथ ही निवेश प्लस ऋण-जमा अनुपात सभी क्षेत्रों के बीच दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक था, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र का स्थान था। यही प्रवृत्ति निवेश प्लस ऋण-जमा अनुपात के साथ ही निवेश प्लस ऋण प्लस आरआइडीएफ जमा अनुपात में भी देखी गई (चार्ट IV.22)।

[9] आरआइडीएफ पर विस्तृत ब्योरे के लिए ''अध्याय V: सहकारी बैंकिंग में गतिविधियां'' देखें।

चार्ट IV.22: एससीबी का क्षेत्रवार ऋण-जमा अनुपात
(मार्च 2008 के अंत में - उपयोग के अनुसार)

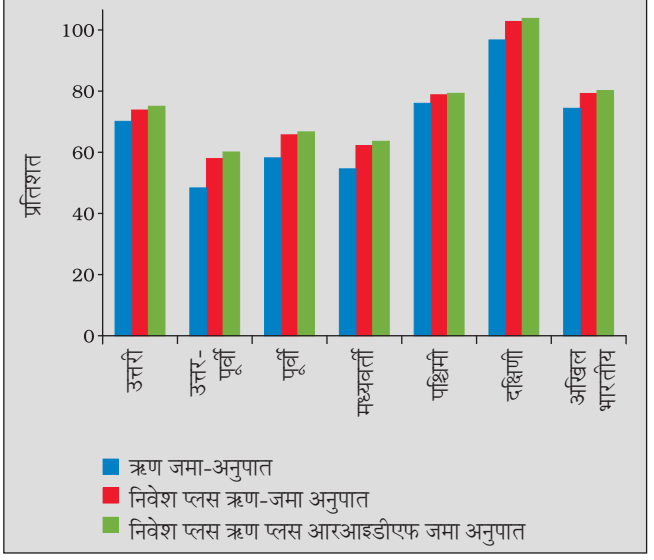

भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

4.111 जून 2009 के अंत में भारत में 32 विदेशी बैंक काम कर रहे थे जिनकी 293 शाखाएं थीं जबकि जून 2008 के अंत में 30 विदेशी बैंक काम कर रहे थे जिनकी 279 शाखाएं थीं। ये बैंक 23 अलग-अलग देशों के थे । इसके अलावा, भारत में 43 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से काम कर रहे थे। जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान की अवधि में चार मौजूदा विदेशी बैंकों को भारत में अपनी 12 शाखाएं तथा तीन नए विदेशी बैंकों (सीआइएमबी बैंक बर्हाद, मलेशिया, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फर्स्ट रैंड बैंक लि.) में से प्रत्येक को भारत में अपनी पहली एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई है। इसी अवधि के दौरान, तीन विदेशी बैंकों (केएफडब्ल्यू-आइपीईएक्स बैंक जीएमबीएच, टोरोंटो डोमिनियन बैंक और डंकन लॉरी लि.) में से प्रत्येक को भारत में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। तीन विदेशी बैंकों, अर्थात डीबीएस बैंक लि., डस्टच बैंक एजी और फर्स्ट रैंड बैंक लि. ने जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान कुल मिलाकर 12 शाखाएं खोली। इसके अलावा, दो विदेशी बैंकों, अर्थात डीएनबी एनओआर बैंक और केएफडब्ल्यू-आइपीईएक्स बैंक जीएमबीएच में से प्रत्येक ने इसी अवधि के दौरान एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला।

विदेश में भारतीय बैंकों का परिचालन

4.112 भारतीय बैंकों का विदेशों में विस्तार का क्रम जारी रहा। यद्यपि विदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा की उपस्थिति लगातार सर्वाधिक बनी रही, किंतु भारतीय स्टेट बैंक ने भी वर्ष के दौरान विदेश में अपने परिचालन बढ़ाकर यह अंतर कम किया (सारणी IV.48)। 2008-09 के दौरान, विदेशी शाखाओं की कुल आस्तियों में यूएसडी 6,570 मिलियन (10.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2009 को वे यूएसडी 67,129 मिलियन थीं। वर्ष के दौरान आस्तियों में वृद्धि में मुख्य योगदान ग्राहक ऋण में यूएसडी 5,988 मिलियन की वृद्धि का था। आस्तियों में वृद्धि का निधीयन मुख्यत: अंतर-शाखा उधार और ग्राहक जमा राशि से हुआ था जिसमें क्रमश: यूएसडी 2,906 मिलियन (121.8 प्रतिशत) और यूएसडी 2,107.44 मिलियन (10.4 प्रतिशत) की वृद्धि होकर 31 मार्च 2009 को वे यूएसडी 5,293 मिलियन और यूसडी 2,2376 मिलियन थे।

9. ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश

4.113 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) कार्यालयों में वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के विरुद्ध आम जनता से शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। शिकायतकर्ता ई-मेल से, ऑनलाइन या डाक के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं। बीओ कार्यालयों द्वारा ये शिकायतें संबंधित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। 2008-09 के दौरान 15 बीओ कार्यालयों में 69,117 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जबकि पिछले वर्ष 47,887 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अधिकतम शिकायतें क्रेडिट कार्ड से संबंधित थीं, इसके बाद दी गई वचनबद्धताओं को पूरा न किए जाने संबंधी शिकायतों का स्थान था। बहुत सी शिकायतें पेंशन भुगतान (विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में) और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंकों के संबंध में) थीं (सारणी IV.49 और परिशिष्ट सारणी IV.40)।

सारणी IV.48: भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

(वास्तविक रू प से परिचालनात्मक)

बैंक का नाम	शाखा		अनुषंगी		प्रतिनिधि-कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सरकारी क्षेत्र के बैंक	**121**	**130**	**19**	**18**	**28**	**34**	**7**	**7**	**175**	**189**
1 इलाहाबाद बैंक	1	1	–	–	1	1	–	–	2	2
2 आंध्रा बैंक	–	–	–	–	1	2	–	–	1	2
3 बैंक ऑफ बड़ौदा	45	46	8	8	4	3	1	1	58	58
4 बैंक ऑफ इंडिया	23	24	3	3	4	5	1	1	31	33
5 केनरा बैंक	2	3	–	–	1	–	–	–	3	3
6 इंडियन बैंक	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3
7 कॉर्पोरेशन बैंक	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
8 इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	1	3	3	–	–	10	10
9 पंजाब नैशनल बैंक	2	3	1	1	3	4	1	1	7	9
10 भारतीय स्टेट बैंक	33	38	6	5	7	8	4	4	50	55
11 सिंडिकेट बैंक	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
12 यूको बैंक	4	4	–	–	2	2	–	–	6	6
13 यूनियन बैंक	1	1	–	–	2	3	–	–	3	4
14 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
II. निजी क्षेत्र के नए बैंक	**10**	**11**	**3**	**3**	**15**	**16**	**–**	**–**	**28**	**30**
14 एक्सिस बैंक	3	3	–	–	2	2	–	–	5	5
15 एचडीएफसी बैंक लि.	–	1	–	–	2	2	–	–	2	3
16 आइसीआइसीआइ बैंक लि.	7	7	3	3	8	8	–	–	18	18
17 इंडसइंड बैंक लि.	–	–	–	–	2	2	–	–	2	2
18 फेडरल बैक लिमिटेड	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
19 कोटक महिंद्रा बैंक लि.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
कुल	**131**	**141**	**22**	**21**	**43**	**50**	**7**	**7**	**203**	**219**

–: कुछ नहीं।
टिप्पणी: आंकड़े जून के अंत से संबंधित हैं ।

4.114 नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई के बीओ कार्यालयों को 2008-09 के दौरान कुल शिकायतों में से 44.1 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुईं जबकि पिछले वर्ष 36.3 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुई थीं (सारणी IV.50)।

4.115 बीओ योजना, 2006 (मई 2007 तक यथा संशोधित) के संदर्भ में, शिकायतकर्ता/बैंक बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी (उप गवर्नर) के पास अपील कर सकते हैं। 2008-09 के दौरान ऐसी 269 शिकायतें प्राप्त हुईं जबकि पिछले वर्ष के दौरान 186 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

''नो फ्रिल्स'' खाते

4.116 वित्तीय समावेशन उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2005 में सभी बैंकों को सूचित किया कि वे ''शून्य'' या कम न्यूनतम शेष और प्रभार वाले आधारभूत बैंकिंग के ''नो फ्रिल्स'' खाते उपलब्ध कराएं। इसके पीछे मूल विचार यह था कि कम आय वाले समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने से एक ऐसा चक्र तैयार होगा जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि के लाभों का समान वितरण होगा जिससे कम आय वाले समूहों की आय के स्तर में सुधार होगा। इससे कम आय वाले समूहों द्वारा खोले गए खातों में जमाराशि की औसत मात्रा में वृद्धि होगी और इससे वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए परिचालनात्मक रूप से लाभप्रद और व्यवहार्य व्यवसाय का अनुपात बनेगा। कम लागत या शून्य लागत वाले खाते बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और विशेष रूप से कम आय वाले समूहों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय रूप से

सारणी IV.49: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त बैंक समूहवार शिकायतें – 2008-09

शिकायतों का स्वरूप	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (3+6+9)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (4+5)	राष्ट्रीकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक (7+8)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	यूसीबी/ आरआरबी/ अन्य	**कुल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल प्राप्त शिकायतें (1 से 10)	**66,823**	**33,141**	**14,974**	**18,167**	**21,982**	**1,177**	**20,805**	**11,700**	**2,294**	**69,117**
1) जमा खाता	6,550	3,353	1,941	1,412	2,470	126	2,344	727	156	6,706
2) विप्रेषण	5,210	3,523	1,722	1,801	1,386	94	1,292	301	125	5,335
3) क्रेडिट कार्ड	17,603	5,916	1,220	4,596	5,950	73	5,877	5,737	45	17,648
4) ऋण / अग्रिम (क+ख)	7,863	4,201	2,536	1,665	2,666	204	2,462	996	311	8,174
क) सामान्य	7,040	3,867	2,333	1,534	2,291	191	2,100	882	291	7,331
ख) आवास ऋण	823	334	203	131	375	13	362	114	20	843
5) बिना पूर्व सूचना के प्रभार	4,740	1,898	898	1,000	2,080	132	1,948	762	54	4,794
6) पेंशन	2,907	2,862	842	2,020	33	6	27	12	9	2,916
7) की गई वचनबद्धता न निभाना	11,446	6,560	3,434	3,126	3,736	326	3,410	1,150	378	11,824
8) प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	2,954	1,410	780	630	1,016	58	958	528	64	3,018
9) नोट और सिक्के	110	64	34	30	35	4	31	11	3	113
10) अन्य	7,440	3,354	1,567	1,787	2,610	154	2,456	1,476	1,149	8,589

सारणी IV.50: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त क्षेत्र-वार शिकायतें

क्रम सं.	कार्यालय	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
		2007-08	2008-09
1	2	3	4
1	अहमदाबाद	2,855	3,732
2	बेंगलूर	2,975	3,255
3	भोपाल	3,402	3,375
4	भुवनेश्वर	998	1,159
5	चण्डीगढ़	2,331	2,634
6	चेन्नै	4,545	10,381
7	गुवाहाटी	282	455
8	हैदराबाद	2,843	3,961
9	जयपुर	3,369	3,688
10	कानपुर	5,340	7,776
11	कोलकाता	2,815	3,671
12	मुंबई	6,070	9,631
13	नई दिल्ली	6,742	10,473
14	पटना	1,480	2,110
15	तिरुवनंतपुरम	1,840	2,816
कुल		**47,887**	**69,117**

सहायक माने जाते हैं। बैंकों द्वारा अन्य नाम के साथ ऐसे ही खाते विभिन्न देशों में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि स्वयं बैंकों की ओर से या सरकारों की ओर से जन सामान्य की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक उपलब्ध कराई जाए [10]। भारत में बैंकों द्वारा खोले गए ''नो फ्रिल्स'' खातों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है (सारणी IV.51)।

सारणी IV.51: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गए नो फ्रिल्स खातों की संख्या

बैंक समूह	मार्च अंत 2007	मार्च अंत 2008	मार्च अंत 2009
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,865,419	13,909,935	29,859,178
निजी क्षेत्र के बैंक	860,997	1,845,869	3,124,101
विदेशी बैंक	5,919	33,115	41,482
कुल	6,732,335	15,788,919	33,024,761

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

[10] भारतीय रिज़र्व बैंक, (2008): मुद्रा और वित्त रिपोर्ट, 2006-08।

10. व्यष्टि वित्त

4.117 व्यष्टि वित्त ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों के लिए मितव्ययिता, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है और बहुत छोटी राशि का उत्पाद है जिससे वे अपना आय-स्तर बढ़ा कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में व्यष्टि वित्त की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 1992 में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किए गए स्व-सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसबीएलपी) से हुई। यह कार्यक्रम न केवल बहुत सफल सिद्ध हुआ, बल्कि यह भारत में व्यष्टि वित्त के बेहद लोकप्रिय मॉडल के रूप में उभरा। देश में व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) के माध्यम से व्यष्टि वित्त की सुपुर्दगी जैसे अन्य माध्यम भी उभरे। भारत में एमएफआइ की विशेषता विविधतायुक्त संस्थागत और विधिक स्वरूपीय है। निर्धन लोगों के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की व्यष्टि वित्त की संभावना को देखते हुए रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और सिडबी ने भारत में व्यष्टि वित्त को और प्रोत्साहन देने के लिए पिछले अनेक वर्षों में विविध उपाय किए हैं।

एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसबीएलपी) दृष्टिकोण

4.118 एसएचजी लगभग 15 से 20 ऐसे लोगों का समरूपी संलग्नता वाला छोटा समूह होता है जो किसी समान कार्य के लिए अपना समूह बनाते हैं। इन समूहों द्वारा स्वैच्छिक बचत के कार्य नियमित आधार पर किए जाते हैं और इस प्रकार जमा हुई बचत की राशि समूह के सदस्यों को ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। बचत की आदत लगाने के अलावा, एसएचजी के कार्यों में वित्तीय मध्यस्थता और संसाधनों को हैंडिल करने जैसी धारणाएं भी समझाई जाती है। समूह का गठन हो जाने पर यह बैंकों से जुड़ जाता है और उनकी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करता है।

4.119 एसबीएलपी ने 1990 के दशक की शुरुआत में अपने प्रारंभ से बैंकों के साथ जुड़े एसएचजी ऋणों और एसएचजी द्वारा संवितरित बैंक ऋणों के मामले में काफी प्रगति की है। अब तक देखी गई प्रवृत्ति के अनुसार, 2008-09 में एसएचजी को ऋण देने में वाणिज्य बैंक सबसे आगे रहे हैं, इनके बाद आरआरबी और सहकारी बैंकों का स्थान है (सारणी IV.52)।

4.120 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार, एसबीएलपी के तहत 4.2 मिलियन एसएचजी की ओर 22,680 करोड़ रुपए का बैंक ऋण बकाया था। कुल बकाया ऋण में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 68 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंको के हिस्से में तदनुरूपी गिरावट हुई (सारणी IV.53)।

4.121 31 मार्च 2009 को बैंकिंग क्षेत्र के साथ बचत खाता मेनटेन करने वाले एसएचजी की संख्या 6.1 मिलियन थी और

सारणी IV.52: एजेंसीवार स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम

(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000 में)				वितरित बैंक ऋण			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य बैंक	735	161	1,005	133	5,404	1,104	8,061	1,102
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	328	65	406	82	2,652	598	3,193	655
सहकारी बैंक	165	21	199	50	794	156	999	258
कुल	**1,228**	**247**	**1,610**	**265**	**8,849**	**1,858**	**12,254**	**2,015**

* : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) एवं अन्य प्रायोजित योजनाओं सहित।
टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण आंकड़े अपने संबंधित योग से मेल नहीं खा सकते ।
स्रोत: नाबार्ड।

सारणी IV.53: एसबीएलपी के अंतर्गत बकाया बैंक ऋण
(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000 में)				वितरित बैंक ऋण			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य बैंक	2,378	638	2,831	645	11,475	3,226	16,149	3,961
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	876	223	978	259	4,421	1,332	5,224	1,508
सहकारी बैंक	371	55	415	73	1,103	259	1,306	392
कुल	**3,626**	**917**	**4,224**	**977**	**17,000**	**4,817**	**22,680**	**5,862**

* : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) एवं अन्य प्रायोजित योजनाओं सहित
टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण आंकड़े अपने संबंधित योग से मेल नहीं खा सकते ।
स्रोत: नाबार्ड।

बकाया बचत की राशि 5,546 करोड़ रुपए थी। हालांकि एसएचजी की बचत में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा लगातार सर्वाधिक बना रहा, किंतु उनका हिस्सा मार्च 2008 के 55 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 में 50 प्रतिशत रह गया। जहां सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग अपरिवर्तित रहा, वहीं आरआरबी का हिस्सा इसी अवधि में 31 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.54)।

4.122 एसएचजी को दिए गए बैंक ऋणों का वसूली निष्पादन निजी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों के मामले में उच्च स्तर पर बना रहा जिसमें वसूली दर 80-94 प्रतिशत की आदर्श श्रेणी में थी। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में आदर्श श्रेणी 95 प्रतिशत और अधिक की थी (सारणी IV.55)।

एमएफआइ दृष्टिकोण

4.123 निर्धन लोगों को वित्तीय सेवाएं देने में बैंकों के अलावा एमएफआइ की उभरती भूमिका को मान्यता मिल रही है और बैंकिंग क्षेत्र आगे एसएचजी को देने के लिए एमएफआइ को ऋण दे रहे हैं। 2008-09 के दौरान, 581 एमएफआइ को 3,732 करोड़ रुपए का बैंक ऋण संवितरित किया गया था जिससे 31 मार्च 2009 को

सारणी IV.54: स्वयं सहायता समूहों की बैंकों में बचत
(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000 में)				एसएचजी की बचतें			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य बैंक	2,811	766	3,550	931	2,078	527	2,773	682
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,387	357	1,629	434	1,166	211	1,990	775
ऋण सहकारी बैंक	812	80	943	140	541	72	783	107
कुल	**5,010**	**1,203**	**6,121**	**1,506**	**3,785**	**810**	**5,546**	**1,563**

* : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) एवं अन्य प्रायोजित योजनाओं सहित।
टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण आंकड़े अपने संबंधित योग से मेल नहीं खा सकते ।
स्रोत: नाबार्ड।

सारणी IV.55: स्वयं सहायता समूहों के प्रति बैंक ऋणों का एजेंसीवार वसूली निष्पादन
(मार्च अंत के अनुसार 2009)

(बैंकों की संख्या)

बैंक की श्रेणी	रिपोर्टिंग बैंकों की कुल संख्या	स्वयं सहायता समूहों को दिए गए बैंक ऋण का वसूली निष्पादन			
		95 प्रतिशत और उससे अधिक	80-94 प्रतिशत	50-79 प्रतिशत	50 प्रतिशत से कम
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	25	6 (24.0)	12 (48.0)	7 (28.0)	0 (0.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	7	5 (71.4)	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	65	12 (18.5)	31 (47.7)	15 (23.1)	7 (10.8)
सहकारी बैंक	170	56 (32.9)	58 (34.1)	37 (21.8)	19 (11.2)
कुल	**267**	**79** **(29.6)**	**102** **(38.2)**	**59** **(22.1)**	**27** **(10.1)**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एजेंसी वार योग में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

1915 एमएफआइ की ओर बकाया ऋण 5,009 करोड़ रुपए हो गया (सारणी IV.56)।

4.124 व्यष्टि वित्त की गतिविधियां भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। किंतु, वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में, अनर्जक ऋणों में वृद्धि, चलनिधि और निधीयन में कमी, लाभप्रदता में गिरावट और प्रबंधन तथा कंपनी संचालन में दुर्बलता पर अंतरराष्ट्रीय रूप से चिंता प्रकट की गई है[11]।.

सारणी IV.56: एमएफआइ को उपलब्ध कराए गए बैंक ऋण
(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक की श्रेणी	बैंकों द्वारा एमएफआइ को संवितरित ऋण		एमएफआइ के विरुद्ध बकाया ऋण	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
वाणिज्य बैंक	1,969 (497)	3,719 (522)	2,745 (1,072)	4,978 (1,762)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2 (8)	13 (59)	4 (24)	31 (153)
सहकारी बैंक	0.04 (13)	– (0)	0.02 (13)	– (0)
कुल	**1,970** **(518)**	**3,732** **(581)**	**2,749** **(1,109)**	**5,009** **(1,915)**

– : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एमएफआइ की संख्या दर्शाते हैं।
2. एफआइ की वास्तविक संख्या कम होगी क्योंकि कुछ एफआइ ने एक से अधिक बैंकों से ऋण लिया है।

11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4.125 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की शुरुआत 1976 का आरआरबी अधिनियम लागू होने के समय से हुई। क्षेत्रीय-उन्मुख ग्रामीण बैंकों के इस नए सेट की उत्पत्ति के पीछे यह विचार था कि स्थानीय स्पर्श और सहकारी संस्थाओं की विशेष ग्रामीण समस्याओं की जानकारी को वाणिज्य बैंकों की व्यावसायिकता और उनके व्यापक संसाधन आधार को जोड़ दिया जाए। आरआरबी की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50:15:35 के अनुपात में धारित होती है।

4.126 भारत में कृषि तथा ग्रामीण ऋण के प्रति बहु-एजेंसी दृष्टिकोण में आरआरबी का एक विशेष स्थान है। स्थानीय संस्था

[11] वित्तीय नवोन्मेष अध्ययन केंद्र (2009): ''माइक्रोफिनान्स बनाना स्किन्स: कन्फ्रन्टिंग क्राइजेस एंड चेंज'', जून। http://www.cgap.org पर उपलब्ध है।

होने के कारण आरआरबी वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। कृषि तथा ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बहु एजेंसी दृष्टिकोण से आरआरबी की वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में आरआरबी की दुर्बल वित्तीय स्थिति पर नरसिम्हन समिति (1991) द्वारा चिंता व्यक्त करने पर रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए।

4.127 खानखोजे और साठे (2008)[12] ने 1990 से 2002 के लिए भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादकता-कौशल स्कोर की गणना की है। इन स्कोरों की गणना डाटा एन्वेलपमेंट एनालिजीज की नॉन-पॅरामेट्रिक तकनीक का उपयोग करके की गई। इन बैंकों का व्यापक पुनर्गठन 1993-94 में होने के कारण इस बात की जांच करने के लिए कि पुनर्गठन से इन बैंकों की कार्य कुशलता बढ़ी या नहीं, पुनर्गठन-पूर्व और पुनर्गठन-पश्चात के वर्षों के माध्य-कार्य कुशलता स्कोरों की तुलना एएनओवीए का प्रयोग करके की गई। यह अध्ययन दर्शाता है कि आरआरबी के माध्य-कार्य कुशलता स्कोर में काफी वृद्धि हुई है। यह अध्ययन सिफारिश करता है कि अनर्जक आस्तियां कम करने की वर्तमान नीति और बैंक स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से स्थापना व्यय कम करना तथा ग्रामीण शाखाओं का औचित्यीकरण सही दिशा में किए गए उपाय हैं जो कुछ समय के उपरांत इन बैंकों की कार्य कुशलता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

4.128 कृषि और संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रवाह पर परामर्शदाता समिति (अध्यक्ष: प्रो. वी.एस.व्यास) ने जून 2004 में आरआरबी के पुनर्गठन की सिफारिश की थी ताकि उनकी परिचालनात्मक क्षमता में सुधार हो सके और उन्हें बड़े पैमाने की किफायतें मिल सकें। इसके पश्चात, आरआरबी के सुदृढ़ीकरण के लिए मौजूदा विधिक संरचना के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच के लिए रिज़र्व बैंक ने आरआरबी पर आंतरिक कार्यदल का गठन किया। आरआरबी को भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण सुपुर्दगी का प्रभावी माध्यम बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के साथ विचार-विमर्श करके सितंबर 2005 से आरआरबी का राज्य-स्तरीय प्रायोजक बैंकवार समामेलन शुरू किया ताकि आरआरबी में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें व्यवहार्य तथा लाभप्रद बनाया जा सके। मार्च 2009 के अंत में, 45 समामेलित और 41 स्टैंड-अलोन आरआरबी सहित 86 आरआरबी थे।

आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण

4.129 ऋणात्मक निवल मालियत वाले आरआरबी के चरणबद्ध पुनर्पूंजीकरण की योजना 2007-08 के बजट में घोषित की गई। 31 मार्च 2007 को ऋणात्मक निवल मालियत वाले 27 आरआरबी पुनर्पूंजीकरण के लिए चुने गए। इसके लिए 1,796 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता थी। इसमें से, राज्य सरकारों, प्रायोजक बैंकों और भारत सरकार का अंशदान क्रमश: 269 करोड़ रुपए (15 प्रतिशत), 629 करोड़ रुपए (35 प्रतिशत) और 898 करोड़ रुपए (50 प्रतिशत) था। उक्त 27 आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

आरआरबी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.130 आरआरबी के समेकित तुलन पत्र ने मात्रा में 2007-08 के 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। आस्तियों के मामले में, आरआरबी के निवल अग्रिमों में इस अवधि के दौरान 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयता पक्ष की प्रमुख मदों में वर्ष के दौरान जमाराशि और उधार में क्रमश: 19.1 प्रतिशत तथा 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आरआरबी का ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के 59.5 प्रतिशत से कुछ कम होकर मार्च 2009 के अंत में 58.5 प्रतिशत रह गया (सारणी IV.57)।

[12] खानखोजे,डी. और साठे एम. (2008),ड इफिसियंसी ऑफ रूरल बैंक्स: दि केस ऑफ इंडियाड , इटरनैशनल बिजनेस रिसर्च,खंड 1,सं.2,अप्रैल। http://www.ccsenet.org/journal html पर उपलब्ध है।

सारणी IV.57: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009अ	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4
देयताएं	**1,25,194**	**1,45,824**	**16.5**
शेयर पूंजी	196	197	0.5
आरक्षित निधियां	5,703	5,914	3.7
शेयर पूंजी जमाराशि	2,833	3,946	29.3
जमाराशि	**99093**	**117984**	**19.1**
चालू	5716	6204	8.5
बचत	53371	66920	25.4
मीयादी	40006	44860	12.1
उधार	**11494**	**11686**	**1.7**
नाबार्ड	7992	8191	2.5
प्रोयोजक बैंक	3078	3228	4.9
अन्य	424	267	-37.0
अन्य देयताएं	5875	6097	3.8
आस्तियां	**125194**	**145824**	**16.5**
उपलब्ध नकदी	1404	1502	7.0
भा.रि. बैंक के पास शेष	7164	10317	44.0
अन्य बैंक शेष	22338	23361	4.6
अन्य निवेश	30166	34168	13.3
ऋण तथा अग्रिम (निवल)	57568	69030	19.9
अचल आस्तियां	241	292	21.2
अन्य आस्तियां#	6313	7154	13.3
ज्ञापन मदें:			
क. ऋण-जमा अनुपात	59.5	58.5	
ख. निवेश-जमा अनुपात	49.0	48.8	
ग. (ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	108.5	107.2	

अ : अनंतिम। – : कुछ नहीं/नगण्य। # : संचित हानि सहित ।
स्रोत: नाबार्ड।

4.131 अब तक उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2008-09 के दौरान 86 आरआरबी ने 9.4 मिलियन उधारकर्ताओं को 41,273 करोड़ रुपए के नए ऋण दिए जबकि 2007-08 के दौरान यह संख्या क्रमश: 9.3 मिलियन उधारकर्ता और 38,464 करोड़ रुपए थी। इसमें से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जारी ऋणों का हिस्सा 82.6 प्रतिशत था। उधारकर्ता कवरेज की संख्या के संदर्भ में, 2008-09 के दौरान जारी कुल ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जारी ऋणों का हिस्सा लगभग 84 प्रतिशत था। मार्च 2009 के अंत में, आरआरबी के बकाया अग्रिमों की राशि 69,030 करोड़ रुपए थी और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 83.3 प्रतिशत था। मार्च 2009 के अंत में, कृषि ऋणों का हिस्सा कुछ कम होकर 52.8 प्रतिशत रह गया जो कि एक वर्ष पूर्व 56.3 प्रतिशत था (सारणी IV.58)।

सारणी IV.58: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम

(राशि करोड़ रुपए)

प्रयोजन/मार्च के अंत में	2007	2008	2009अ
1	2	3	4
I. कृषि (i से iii)	**27,452**	**33,216**	**36,466**
कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	**56.6**	**56.3**	**52.8**
i. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	18,707	22,748	24,986
ii. मीयादी ऋण (कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों के लिए)	3,745	10,468	11,480
iii. अप्रत्यक्ष अग्रिम	–	–	–
II. कृषीतर (iv से vii)	**21,041**	**25,768**	**32,564**
कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	**43.4**	**43.9**	**41.2**
iv. ग्रामीण कारीगर, *आदि*	736	671	820
v. अन्य उद्योग	880	1,227	1,400
vi. खुदरा व्यापार, *आदि*	3,677	4,531	5,015
vii. अन्य प्रयोजन	15,748	19,339	25,329
कुल (I+II)	**48,493**	**58,984**	**69,030**
ज्ञापन मदें:			
क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	39,852	48,894	57,528
ख) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	8,641	10,090	11,502
ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा (कुल में प्रतिशत)	82.2	82.9	83.3

अ : अनंतिम। - : कुछ नहीं / नगण्य।
स्रोत : नाबार्ड।

4.132 आरआरबी के समामेलन के परिणामस्वरूप, मार्च 2009 के अंत में लाभ अर्जित करने वाले आरआरबी की संख्या बढ़कर 80 हो गई तथा घाटा उठाने वाले आरआरबी की संख्या कम होकर 6 रह गई जो मार्च 2008 के अंत में क्रमश: 82 और 8 थी।

4.133 मार्च 2009 के अंत में आरआरबी की कुल आय कम होकर 19.5 प्रतिशत रह गई जो पिछले वर्ष 20.0 प्रतिशत थी। इस गिरावट का कारण 'अन्य आय' में कमी आना था। किंतु, आरआरबी का व्यय तेजी से बढ़ा जिसका मुख्य कारण व्यय किए गए ब्याज में वृद्धि और प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय में वृद्धि होना था। 2008-09 में 86 आरआरबी में से 80 आरआरबी ने 1,405 करोड़ रुपए का लाभार्जन किया वहीं 6 आरआरबी को 36 करोड़ रुपए की हानि हुई। इस प्रकार, 2008-09 के दौरान आरआरबी को कुल मिलाकर 1,369 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ जबकि पिछले वर्ष 1,027 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। आरआरबी के कार्य निष्पादन में सुधार 2008-09 के दौरान एनपीए (सकल और निवल दोनों) में गिरावट में भी दिखा। जहां मार्च 2009 के अंत में कुल ऋण-आस्ति अनुपात कम होकर 4.2 प्रतिशत रह गया जो

सारणी IV.59: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण	2007-08			2008-09(अ)			घटबढ़	
	घाटे में चल रहे [8]	लाभ में चल रहे [82]	कुल क्षे.ग्रा.बैं. [90]	घाटे में चल रहे [6]	लाभ में चल रहे [80]	कुल क्षे.ग्रा.बैं. [86]	स्तंभ (4) पर स्तंभ (7)	
							राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. आय (i+ii)	**286**	**9,120**	**9,406**	**276**	**10,975**	**11,251**	**1,831**	**19.5**
i) ब्याज आय	271	8,468	8,739	262	10,181	10,443	1,690	19.3
ii) अन्य आय	15	652	667	14	794	808	141	21.1
ख. व्यय (i+ii+iii)	**342**	**8,037**	**8,379**	**312**	**9,570**	**9,882**	**1,503**	17.9
i) ब्याज व्यय	212	4,545	4,757	200	5,517	5,717	960	20.2
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	13	819	832	12	1,246	1,258	426	51.2
iii) परिचालनगत व्यय	117	2,673	2,790	100	2,807	2,907	117	4.2
जिसमें से : वेतन बिल	100	1,954	2,054	85	2,018	2,103	49	2.4
ग. लाभ								
i) परिचालन लाभ/हानि	**-43**	**1,902**	**1,859**	**-24**	**2,651**	**2,627**	**768**	**41.3**
ii) निवल लाभ/हानि	**-56**	**1,083**	**1,027**	**-36**	**1,405**	**1,369**	**342**	**33.3**
घ. कुल आस्तियां	**4,548**	**1,20,646**	**1,25,194**	**3,250**	**1,42,574**	**1,45,824**	**20,630**	**16.5**
ङ. वित्तीय अनुपात @								
i) परिचालन लाभ	-1.0	1.6	1.5	-0.7	1.8	1.8	–	–
ii) निवल लाभ	-1.2	1.0	0.9	-1.1	1.0	0.9	–	–
iii) आय	6.3	7.6	7.5	8.5	7.6	7.7	–	–
क) ब्याज आय	6.0	7.0	7.0	8.1	7.1	7.2	–	–
ख) अन्य आय	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	–	–
iv) व्यय	7.5	6.7	6.7	9.7	6.7	6.8	–	–
क) ब्याज व्यय	4.7	3.8	3.8	6.2	3.8	3.9	–	–
ख) परिचालन व्यय	2.6	2.2	2.2	3.1	2.0	2.0	–	–
जसमें से: वेतन बिल	2.2	1.6	1.6	2.6	1.4	1.4	–	–
v) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	0.3	0.7	0.7	0.4	0.9	0.9	–	–
vi) सकल अनर्जक आस्तिया			6.1			4.2	–	–
vii) निवल अनर्जक आस्तिया			3.4			1.8	–	–

अ : अनंतिम। @ :कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में * : कर पूर्व

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत :नाबार्ड

कि एक वर्ष पूर्व 6.1 प्रतिशत था, वहीं इसी अवधि में ऋण आस्ति-एनपीए अनुपात 3.4 प्रतिशत से कम होकर 1.8 प्रतिशत रह गया (सारणी IV.59)।

4.134 पिछले कुछ वर्षों में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, 2008-09 के दौरान प्रति शाखा तथा प्रति कर्मचारी दोनों के संदर्भ में आरआरबी की उत्पादकता में और वृद्धि हुई। जहां आस्ति के प्रतिशत के रूप में संचित हानि पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही, वहीं वित्तीय विवरणी और निवल मार्जिन में 2008-09 के दौरान सुधार हुआ (सारणी IV.60)।

12. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

4.135 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की शुरुआत 1996 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में उक्त वर्ष के अगस्त में की गई थी। दो या तीन सहवर्ती जिलों के कार्यक्षेत्र वाले स्थानीय क्षेत्र के नए निजी बैंकों के गठन के पीछे यह विचार था कि स्थानीय बचत का संग्रह स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और स्थानीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) से यह अपेक्षित था कि वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता का अंतर मिटाएंगे और संस्थागत ऋण संरचना

सारणी IV.60: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबारी तथा वित्तीय संकेतक

संकेतक	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	196	196	196	133 #	96 #	90 #	86 #
निवल लाभ [1] (करोड़ रुपए)	519	769	748	617	596	1328	1830
प्रति शाखा उत्पादकता [2] (करोड़ रुपए)	5.0	5.7	6.6	7.7	9.1	10.7	12.4
प्रति कर्मचारी उत्पादकता [3] (करोड़ रुपए)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.3	2.7
आस्तियों के प्रतिशत के रूप में संचित हानि	4.4	3.9	3.5	2.9	2.6	2.1	2.1
आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन	2.3	2.6	2.0	2.1	1.9	1.9	1.8
वित्तीय विवरणी [4] (प्रतिशत)	9.6	8.9	8.2	7.7	7.7	8.1	8.2
वित्तीय लागत [5] (प्रतिशत)	6.1	5.4	4.6	4.1	4.1	4.4	4.5
वित्तीय मार्जिन [6] (प्रतिशत)	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
जोखिम, परिचालन और अन्य लागत (प्रतिशत)	2.6	2.2	2.3	2.8	2.9	2.7	2.6
निवल मार्जिन [7](प्रतिशत)	0.9	1.3	1.3	0.8	0.7	1.0	1.1

: सितंबर 2005 में आरम्भ हुए समामेलन के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटी है। वित्तीय निष्पादन विश्लेषण 90 आरआरबी (नए आरआरबी छोड़कर) से संबंधित है। 2008-09 के आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : 1. निवल लाभ अर्थात सकल लाभ (कर पूर्व) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाए गए घाटों के बीच अंतर।
2. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रत्येक शाखा के कारोबार (कुल जमाराशियों और सकल अग्रिमों के रूप में) का औसत स्तर।
3. वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति कर्मचारी के कारोबार (कुल जमाराशियों और सकल अग्रिमों के रूप में) का औसत स्तर।
4. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में अग्रिम तथा निवेश दोनों से कुल आय का प्रतिशत।
5. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में जमाराशियां, उधार आदि के लिए कुल ब्याज भुगतान का प्रतिशत।
6. वित्तीय विवरणी और वित्तीय लागत के बीच का अंतर।
7. वित्तीय मार्जिन और जोखिम, परिचालन और अन्य लागत तथा अन्य आय के बीच का अंतर।

स्रोत : नाबार्ड।

को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप, निजी क्षेत्र में एलएबी के गठन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने अगस्त 1996 में दिशानिर्देशों की घोषणा की। मार्च 2009 के अंत में देश में चार एलएबी कार्यरत थे।

4.136 2008-09 के दौरान, एलएबी की कुल आस्तियों, जमाराशियों और सकल अग्रिमों की वृद्धि दर में गिरावट आई जो आंशिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में समग्र मंदी और अनिश्चितता में वृद्धि दर्शाती है। विशेष रूप से, 2008-09 के दौरान, कुल आस्तियों में 20.3 प्रतिशत, जमाराशियों में 20.0 प्रतिशत और सकल अग्रिमों में 23.8 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 2006-07 के दौरान यह वृद्धि दर क्रमश: 32.2 प्रतिशत, 32.4 प्रतिशत और 35.5 प्रतिशत थी। कमोबेश यही वृद्धि दर सभी एलएबी के संबंध में देखी गई जिसका अपवाद कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि. था जिसकी वृद्धि दर काफी अधिक थी (सारणी IV.61)।

सारणी IV.61: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की रूपरेखा

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक	आस्तियां		जमाराशियां		सकल अग्रिम	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	466	549	393	461	243	296
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	76	100	56	73	43	57
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	81	99	43	56	52	64
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	31	39	22	27	17	23
कुल	**654**	**787**	**514**	**616**	**355**	**439**

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणी पर आधारित।

सारणी IV.62: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण			अंतर	
	2007-08	2008-09	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**68.2**	**90.6**	**22.5**	**33.0**
i) ब्याज आय	54.9	74.9	20.0	36.4
ii) अन्य आय	13.3	15.8	2.5	18.5
ख. व्यय (i+ii+iii)	**58.3**	**76.5**	**18.2**	**31.2**
i) ब्याज व्यय	29.9	41.7	11.8	39.4
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	6.1	7.8	1.7	27.4
iii) परिचालनगत व्यय	22.3	27.0	4.7	21.2
जिनमें से :				
वेतन बिल	9.9	12.2	2.3	23.1
ग. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ / हानि	**15.6**	**21.9**	**6.3**	**40.5**
ii) निवल लाभ /हानि	**9.5**	**14.1**	**4.6**	**48.9**
घ. स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	**25.0**	**33.2**	**8.2**	**32.9**
ङ कुल आस्तियां	**653.5**	**786.6**	**133.1**	**20.4**
च. वित्तीय अनुपात@				
i) परिचालन लाभ	2.4	2.8		
ii) निवल लाभ	1.5	1.8		
iii) आय	10.4	11.5		
iv) ब्याज आय	8.4	9.5		
v) अन्य आय	2.0	2.0		
vi) व्यय	8.9	9.7		
vii) ब्याज का भुगतान	4.6	5.3		
viii) परिचालन व्यय	3.4	3.4		
ix) वेतन बिल	1.5	1.5		
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.9	1.0		
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	3.8	4.2		

टिप्पणी: @कुल आस्ति का अनुपात।
स्रोत: अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

4.137 उक्त प्रवृत्ति के अनुरूप, एलएबी के वित्तीय निष्पादन में भी मंदी देखी गई। 2008-09 के दौरान, आय, व्यय, लाभ और कुल आस्तियों जैसे सभी संबंधित परिवर्तक 2007-08 की तुलना में कम गति से बढ़े। ब्याज आय और ब्याज से भिन्न आय दोनों की वृद्धि दर में गिरावट आई, हालांकि अन्य आय की वृद्धि में आई गिरावट अधिक मुखर थी। व्यय पक्ष में, व्यय किए गए ब्याज, प्रावधान और प्रासंगिक व्यय और साथ ही वेतन बिल की वृद्धि दर तेजी से कम हो गई। कुल मिलाकर, व्यय की वृद्धि दर की इस गिरावट के अलावा परिचालन लाभ और निवल लाभ की वृद्धि दर भी तेजी से कम हो गई। किंतु, सकारात्मक पक्ष में, परिचालन लाभ और निवल लाभ के वित्तीय अनुपात में 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई (सारणी IV.62)।

13. निष्कर्ष

4.138 भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की पृष्ठभूमि में आघात सहनीयता दर्शाई है। तुलन पत्र, आय और लाभप्रदता में दिखी कुछ मंदी के बावजूद, समग्र सीआरएआर में सुधार हुआ और आस्ति गुणवत्ता अनुकूल स्तर पर बनी रही। इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ बनी रही। चूंकि वाणिज्य बैंक प्रभावी संस्थाएं हैं और भारतीय वित्तीय प्रणाली के अन्य घटकों के साथ उनका संबंध है, अत: इस

क्षेत्र की शक्ति ने संकट के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान किया। बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी, में इस वर्ष कुछ गिरावट देखी गई। यह वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं की स्थिति के अनुरूप ही था। किंतु, यह आवश्यक है कि बैंकों के एक्सपोजर के ऐसे प्रकारों के प्रणालीगत निहितार्थों को देखते हुए उनसे जुड़ी जोखिमों की सतत निगरानी और आकलन किया जाए। एससीबी ने अब बासेल II का पूर्णत: अनुपालन किया है; अब आगे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी में वृद्धि की आवश्यकता का आकलन करके उपयुक्त नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंकों द्वारा उनकी कंपनी संचालन की प्रथा को मजबूत करने की आवश्यकता है। मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ चिह्न दिखने से बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार हो जाएं। ऊर्ध्वगामिता के दौरान, बैंकों को जोखिम और प्रतिलाभ के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा।